



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2007/भाद्र 1, 1929

No. 244]

NEW DELHI, THURSDAY AUGUST 23, 2007/BHADRA 1, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2007

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी आई पाइपों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/14/2005-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके तहत निर्मित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

2. यतः मै. इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लि. एवं मै. लेंको इंडस्ट्रीज लि. (जिन्हें एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके तहत निर्मित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसरण में चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी आई पाइपों (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है । प्राधिकारी द्वारा नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसरण में पाटन के आरोप के बारे में चीन जन.गण. के दूतावास को अवगत कराया गया ।

3. यतः प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 24.2.2006 को एक सार्वजनिक नोटिस भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया और पाटनरोधी शुल्क की संस्तुति हेतु कथित पाटन के अस्तित्व, सीमा तथा प्रभाव के निर्धारण के लिए नियमावली के उप-नियम 6(1) के अनुसरण में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू की गई ।

क. प्रक्रिया:

4. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरुआत के बारे में सूचित करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाने के बाद इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया ।

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2006 की जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रतियां संबद्ध देश के भारत स्थित दूतावास, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को भिजवाई गई और उनसे जांच अधिसूचना के 40 दिन के भीतर अपने विचार लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया गया है ।
- (ii) प्राधिकारी द्वारा ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों तथा चीन जन.गण. के दूतावास को उपलब्ध कराई गई ।
- (iii) नियम 6(2) के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य के भारत स्थित दूतावास को जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया और उनसे उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित अवधि में प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर भिजवाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया । निर्यातकों के नाम तथा पत्रों सहित निर्यातकों को भेजे गए पत्रों एवं प्रश्नावली की प्रतियां भी उन्हें भिजवाई गई ।
- (iv) बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रश्नावली सभी ज्ञात निर्यातकों एवं चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास तथा चीन जन.गण. के ब्यूरो ऑफ फेयर ट्रेड, चाइना (बी ओ एफ टी) को भिजवाई गई । यद्यपि, जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की संरचित लागत के आधार पर किया गया, तथापि प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निर्यातकों को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा आवेदकों के दावे की जांच यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-(7) एवं (8) के आलोक में प्रस्तावित है । अतः चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों से पैराग्राफ -8 के उप-पैराग्राफ (3) में उल्लिखित आवश्यक जानकारी/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार कर सकें कि क्या सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को, जो यह प्रदर्शित कर सकते हों कि वे उपर्युक्त पैराग्राफ में निर्धारित मानदंडों को संतुष्ट कर सकते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार स्वीकृत किया जा सकता है ।

- (v) प्राधिकारी द्वारा नियम 6(4) के अनुसरण में अपेक्षित जानकारी हासिल करने के लिए एक प्रश्नावली चीन जन.गण. के ज्ञात निर्यातकों को भिजवाई गई :

क. जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में मै. जिनजिन डक्टाइल आयरन पाइप्स कं. लि.(एक्सडीआईपीएल) ने पाटन के निर्धारण तथा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का खंडन करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई ।

- (vi) जिन निर्यातकों ने इस जांच में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, उन्हें असहयोगी निर्यातक माना गया है ।
- (vii) नियम 6(4) के अनुसरण में भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों एवं उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भिजवाई गईं और उनसे आवश्यक सूचना देने का अनुरोध किया गया । अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई :

- (क) मै. लार्सन एंड ट्यूबरो लि. चेन्नई
- (ख) मै. जे.वी. गोकल एंड कं. लि., मुंबई
- (ग) मै. गैमन इंडिया लि., मुंबई
- (घ) मै. इंजीनियरिंग (प्रोजेक्ट्स) इंडिया लि., नई दिल्ली

आंकड़ों से ज्ञात होता है कि केवल मै. जे.वी. गोकल एंड कं. लि., मुंबई ने ही जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था ।

- (viii) जिन आयातकों/प्रयोक्ताओं ने इस जांच में सूचना प्रदान नहीं की है, उन्हें असहयोगी आयातक/प्रयोक्ता माना गया है ।
- (ix) हितबद्ध पक्षों के विचारों को सुनने के लिए प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8.8.2006 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम में, हितबद्ध पक्षों से प्राप्त प्रस्तुतीकरण पर विचार किया गया है ।
- (x) प्राधिकारी द्वारा जिस सीमा तक आवश्यक समझा गया, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन किया गया ।
- (xi) प्राधिकारी द्वारा जिस सीमा तक आवश्यक समझा गया, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना का भी सत्यापन किया गया ।

- (xii) संबद्ध वस्तुओं के पिछले तीन वर्षों एवं जांच की अवधि के दौरान किए गए आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया ।
- (xiii) विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक फाइल (विधिवत सूचीबद्ध) के रूप में उपलब्ध कराया गया और इसे हितबद्ध पक्षों के अवलोकनार्थ खुला रखा गया । इस फाइल का निरीक्षण करने और रिकॉर्ड की प्रतियां लेने वाले हितबद्ध पक्षों की पावतियां सार्वजनिक फाइल में रखी गई हैं ।
- (xiv) सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर उत्पादन की इष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं को निर्मित करने और बेचने की लागत का आकलन किया गया ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त होगा ।
- (xv) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में ज्ञात हितबद्ध पक्षों को इन जांच परिणामों में विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधारों से अवगत कराया गया और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर जांच परिणाम में विधिवत विचार भी किया गया है ।
- (xvi) इस अधिसूचना में *** आवेदक द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसे नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है ।
- (xvii) यह जांच दिनांक 1.4.2005 से शुरू करके दिनांक 31.12.2005 (जांच अवधि) तक की अवधि के लिए की गई । क्षति के विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2002-मार्च, 2003, अप्रैल, 2003-मार्च, 2004, अप्रैल 2004-मार्च, 2005 तक की अवधि तथा जांच अवधि शामिल है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद:

5. विचाराधीन उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानक, आई एस ओ 2531 (जल तथा गैस हेतु) के खंड 3.1 तथा 3.2 एवं आई एस ओ: 7186 (मल व्ययन अनुप्रयोग हेतु) में यथापरिभाषित डक्टाइल आयरन स्पन पाइप है । इन्हें आम तौर पर स्फेराइडल ग्रेफाइट आयरन पाइप अथवा डक्टाइल कास्ट आयरन पाइप अथवा डक्टाइल आयरन स्पन पाइप भी कहा जाता है । इन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में 73030030 तथा 73030090 में वर्गीकृत किया गया है ।

6. डी आई पाइप्स तरल पदार्थ को अत्यधिक दबाव पर लंबी दूरी तक ले जाने का कार्य संपन्न करते हैं । इनका प्राथमिक रूप से उपयोग जल के परिवहन अथवा मल व्ययन एवं

गैस, घरेलू तथा औद्योगिक अवशिष्ट के परिवहन, ऑन शोर तथा ऑफ शोर अग्निशमन प्रणालियों में किया जाता है। डी आई पाइप्स के विभिन्न अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं :-

1. अत्यधिक दाब पर कच्चे, पेयजल तथा समुद्री जल का परिवहन।
2. पेय जल तथा गैस का वितरण।
3. घरेलू तथा औद्योगिक अवशिष्ट का निपटान।
4. ऑन शोर तथा ऑफ शोर अग्निशमन प्रणालियाँ।

डी आई पाइपों के विनिर्माण हेतु अपनाई गई उत्पादन प्रौद्योगिकी अपकेन्द्रीय कास्टिंग है।

ख. 2 "एक्स डी आई पी एल" द्वारा निर्यातित उत्पाद

7. भारत को निर्यातित एक्स डी आई पी एल के उत्पादों के विनिर्देशन भारत के घरेलू बाजार में बेचे जा रहे उत्पादों के समान है। इस जांच में शामिल उत्पाद का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 2531 के अनुसरण में पुश इन ज्वाइंट सहित, 6 मीटर की प्रभावी लंबाई में और डी एन 80 मि.मी.-डी एन 2600 मि.मी. के आकार में किया जाता है। इस उत्पाद का प्रयोग मुख्यतः पेयजल, मल व्ययन तथा सभी प्रकार की गैसों के परिवहन में किया जाता है।

8. एक्स डी आई पी एल द्वारा निर्यातित उत्पाद में मानक कोटिंग प्रयुक्त किया जाता है। उत्पाद का आंतरिक सीमेंट आईएसओ 4179 मानक के अनुसार है। बाहरी जिक कोटिंग और उत्पाद की बिटुमन कोटिंग आईएसओ 8179 मानक के अनुसार है। पाइपों की मोटाई ग्रेड के -9 है।

ख. 3 समान उत्पाद:

9. घरेलू उद्योग द्वारा डी आई पाइपों का विनिर्माण 80 मि.मी. से 1100 मि.मी. व्यास में विभिन्न आकारों में किया जाता है। इससे बड़े आकार के पाइप भी बनाए जा सकते हैं।

10. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित डी आई पाइप तथा चीन से आयातित डी आई पाइप विभिन्न विशेषताओं यथा उत्पाद के गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, मूल्य नीति, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से परस्पर तुलनीय है।

11. किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा समान वस्तु के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का यह अभिमत है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं चीन से आयातित डी आई पाइप्स पाटनरोधी नियमावली की धारा 2(घ) के अनुसार समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग और इसकी स्थिति:

12. पाटनरोधी जांच हेतु यह आवेदन मै. इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लि. तथा मै. लेंको इंडस्ट्रीज लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया। जांच शुरुआत के उपरांत मै. जिंदल सॉ लि. ने जांच

में अपना समर्थन दिया। आवेदक तथा समर्थक का डी आई पाइपों के उत्पादन में योगदान 100 % है अतः आवेदकगण वांछित "स्थिति" में हैं। जांच अवधि के दौरान भारतीय उत्पादकों के कुल उत्पादन में आवेदकों का योगदान 81% है, अतः पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार वे घरेलू उद्योग हैं।

13. निर्यातक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ मैस जिंदल सॉ लि. एक "महत्वपूर्ण" कंपनी है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा चीन के आयातों के प्रभाव, यदि कोई हो, के सही तथा पर्याप्त विश्लेषण के लिए जिंदल के संदर्भ में आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग का जांच अवधि के दौरान कुल उत्पादन में योगदान 81% है और वे नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं। मै. जिंदल सॉ लि. ने अपना उत्पादन जांच अवधि के दौरान ही शुरू किया था। इस कंपनी ने जांच के लिए अपना समर्थन दिया और कुछ जानकारी भी प्रदान की, परंतु बाद में प्राधिकारी के प्रश्नों के उत्तर देने और पहले से उपलब्ध कराए गए गोपनीय आंकड़ों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं दिया। प्राधिकारी के पास इन आंकड़ों को त्याग देने का विकल्प मौजूद है, तथापि क्षमता तथा मात्रा के रूप में उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित आंकड़ों पर मांग एवं क्षमता उपयोग के आंकलन हेतु विचार किया गया है। अन्य पहलुओं से संबंधित आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, निर्यातक ने भी मै. जिंदल सॉ लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के प्रयोग पर आपत्ति की है।

घ. अन्य मुद्दे:

घ. 1 ईसीएल तथा एक्सडीआईपीएल के बीच समझौता ज्ञापन से संबंधित मुद्दा

एक्सडीआईपीएल द्वारा प्रस्तुतीकरण

14. यह निवेदन किया गया है कि एक्सडीआईपीएल समूह वर्ष 1999 से इलेक्ट्रोस्टील को पेटेंटशुदा प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों की आपूर्ति करता रहा है। फरवरी, 2006 में इलेक्ट्रोस्टील ने एक्सडीआईपीएल की एक सहायक कंपनी से एक सिंटर संयंत्र की प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों की खरीद हेतु एक संविदा पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल, 2006 में इलेक्ट्रोस्टील के अधिकारियों ने एक्सडीआईपीएल के कारखाने का दौरा किया और अपनी स्वयं की इच्छा से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन में इलेक्ट्रोस्टील ने निम्नलिखित की सहमति व्यक्त की :

1. यह कि एक्सडीआईपीएल पाटन में लिप्त नहीं होंगे और यह कि एक्सडीआईपीएल एक अत्यंत पारदर्शी कंपनी है।
2. यह कि इलेक्ट्रोस्टील भारत सरकार को "सही" सूचना देगी और एक्सडीआईपीएल के विरुद्ध पाटनरोधी जांच को यथाशीघ्र "निरस्त" कराएगी।

15. इलेक्ट्रोस्टील ने तत्पश्चात "उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों" की आपूर्ति के जरिए अपने नए इस्पात संयंत्र की स्थापना में एक्सडीआईपीएल की मदद हासिल की। समझौता ज्ञापन पर उमंग केजरीवाल एवं उद्धव केजरीवाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रोस्टील ने समझौता ज्ञापन के अस्तित्व का खंडन नहीं किया है और उसकी विषय

वस्तु को स्वीकार किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि व्यापक अनुरोध के बावजूद कि डीजीएडी द्वारा नियम 14 के अंतर्गत जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए, डीजीएडी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यह बताया गया है कि डीजीएडी को समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इसी से सिद्ध होता है कि यह याचिका बिना किसी आधार के और बदनीयता से प्रस्तुत की गई।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीआई पाइपों के बारे में जांच शुरुआत के पश्चात एक्सडीआईपीएल द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया कि ईसीएल तथा एक्सडीआईपीएल के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक्सडीआईपीएल पाटन नहीं करेगा और इलेक्ट्रोस्टील भारत सरकार को "सही" सूचना देगा और एक्सडीआईपीएल के विरुद्ध पाटनरोधी जांच को यथाशीघ्र "निरस्त" कराएगा। इस समझौता ज्ञापन के आधार पर एक्सडीआईपीएल ने प्राधिकारी से जांच समाप्त करने का अनुरोध किया। निर्यातक ने इसी आधार पर जांच समाप्ति का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी।

17. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग एवं एक्सडीआईपीएल के निवेदनों पर विचार करने के बाद यह टिप्पणी की कि जांच की समाप्ति नियमावली के नियम 14(क) के अंतर्गत संभव है, यदि इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा लिखित में अनुरोध किया जाए। चूंकि जांच समाप्त करने के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा कोई लिखित अनुरोध नहीं किया गया, अतः प्राधिकारी ने इस जांच को जारी रखने का निर्णय लिया। हितबद्ध पक्षों को यह भी सूचित किया गया कि तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार यह जांच नियमावली के नियम 14 के उप-नियम (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) अथवा किसी अन्य प्रावधान के तहत जांच के दौरान भी समाप्त की जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) के अंतर्गत अनुरोध नहीं किया गया है।

18. अब यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाए। इस संबंध में प्राधिकारी का अभिमत है कि जांच की शुरुआत के पश्चात कोई भी निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षों के निवेदनों पर विचार करना होता है। प्राधिकारी का यह भी अभिमत है कि दो निजी पक्षकारों के बीच हुए करार अथवा समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु को प्राधिकारी का जांच परिणाम नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उन परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है, जिनमें दो निजी पक्षकारों के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, खास तौर से तब जब घरेलू उद्योग ने जांच जारी रखने पर जोर दिया हो। अतः पाटन तथा बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से संबंधित जांच परिणाम पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अपेक्षित मूल्यांकन के आधार पर जारी किए जाते हैं।

घ. 2 घरेलू उद्योग के उत्पादकों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा

19. हितबद्ध पक्षों ने यह मुद्दा उठाया है कि मै. जिंदल सॉ लि. इस जांच में शामिल नहीं हुए हैं। यह भी बताया गया है कि जांच अवधि के दौरान मै. जिंदल सॉ लि. के प्रवेश के कारण घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा गंवा दिया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मै. जिंदल सॉ लि. उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ उठा रहे हैं, अतः वे आवेदक घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार में नए उत्पादक के प्रवेश से उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती। इससे मौजूदा उत्पादकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन प्रभावित होता है। तथापि, वर्तमान जांच संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण अनुचित व्यापार पद्धति के विरुद्ध है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्ष 2004-05 में मै. जिंदल सॉ लिमिटेड डी आई पाइपों का उत्पादन नहीं कर रहे थे अतः जिंदल सॉ लि. और अन्य घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं हुई होगी। उस वर्ष घरेलू उद्योग ने उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में विक्रय कीमत नहीं बढ़ाई। आयातों के पहुंच मूल्य के कारण घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत में कीमत कटौती हुई जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों की बैचमार्किंग आयातों के साथ कर रहा था। तत्पश्चात वर्ष 2005-06 में जब जिंदल सॉ ने डी आई पाइपों का उत्पादन शुरू कर दिया तब घरेलू उत्पादकों के बीच इससे प्रतिस्पर्धा शुरू हुई होगी। तथापि, जांच अवधि के दौरान भी आयातों के पहुंच मूल्य द्वारा घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत की कीमत कटौती यह संकेत करती है कि घरेलू उत्पादक अपनी विक्रय कीमत की बैचमार्किंग आयातों के साथ कर रहे थे। प्राधिकारी का यह अभिमत है कि पाटनरोधी करार के अनुसार यदि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण यदि कोई क्षति हुई हो तो आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण हुई क्षति को अलग-अलग करना जरूरी नहीं है।

21. यह भी कहा गया है कि मै. जिंदल सॉ लि. को उत्पाद शुल्क में छूट के कारण यह कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक विक्रय कीमत की पेशकश के जरिए मौजूदा घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में थी। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. जिंदल सॉ लि. को सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में छूट एक क्षेत्र विशेष में इस उद्योग की स्थापना के नुकसान के निवारण के लिए प्रदान की गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि मै. जिंदल सॉ लि. ने पाटनरोधी जांच के संबंध में समर्थन व्यक्त किया है, हालांकि इस कंपनी ने इस जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं किया।

घ. 3 जी डी आर दस्तावेज में दिए गए वक्तव्य को जारी करना

22. सहयोगी निर्यातक द्वारा इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि ईसीएल द्वारा जीडीआर निर्गम के माध्यम से निधि जुटाई गई और यह भी ध्यान आकृष्ट किया गया है कि जो कंपनी घाटे में जा रही है, उसमें निवेशकों से निवेश आकृष्ट करने और 40 मिलियन अम.डॉ. की धनराशि जुटाने का आत्मविश्वास कैसे उत्पन्न हुआ। इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि जीडीआर पेशकश दस्तावेज में विभिन्न मानदंडों के संबंध में उल्लिखित कंपनी का कार्य-निष्पादन क्षति के प्रयोजनार्थ डीजीएडी को प्रस्तुत कार्य-निष्पादन के अनुरूप नहीं है। कंपनी की लाभप्रदता में गिरावट का स्पष्टीकरण कच्चे माल की लागत में वृद्धि के रूप में दिया गया है। जी डी आर पेशकश दस्तावेज से वह पाठ उद्धृत किया गया है जिसमें ईसीएल ने कहा है कि "जहां तक घरेलू बाजार का प्रश्न है, एक्सडीआईपीएल द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत को लगभग 10,000 टन डी आई पाइपों की आपूर्ति की गई, परंतु इसका भारतीय बाजार पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी यह मानती है कि इसके प्रबंधन के व्यापक अनुभव के साथ-साथ भारत में स्पर्धा पाइप के विनिर्माता के रूप में इसके 45 वर्षों के इतिहास की प्रतिस्पर्धियों अथवा घरेलू बाजार में किसी नई प्रविष्ट कंपनी द्वारा प्रतिकृति नहीं की जा सकती।" इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रोस्टील कॉस्टिंग लि. ने दिनांक 11.5.2006 के एफ सी सी बी से संबंधित पेशकश ज्ञापन में यही वक्तव्य दिया है कि "जहां तक घरेलू बाजार का प्रश्न है,

दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एक्सडीआईपीएल द्वारा भारत की लगभग 10,000 टन डी आई पाइप की आपूर्ति की गई, परंतु भारतीय बाजार पर इसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जी डी आर पेशकश के माध्यम से उत्पादकों में से एक ने धनराशि जुटाई है और पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित आंकड़े 31.3.2005 तक की अवधि के हैं, और जून, 2005 तक के कुछ अमंकित आंकड़े हैं, परंतु इसमें जांच की पूर्ण अवधि शामिल नहीं है। जीडीआर दस्तावेज कंपनी के पूर्ण कार्य निष्पादन से संबंधित है न कि पाटनरोधी जांच के विचारधीन उत्पाद से; जबकि प्राधिकारी द्वारा क्षति का विश्लेषण केवल जांच के अधीन उत्पाद तक और संपूर्ण घरेलू उद्योग के लिए जांच की एक विशिष्ट अवधि तक सीमित है न कि किसी अलग कंपनी के लिए।

24. जहां तक प्रबंधन में कंपनी के व्यापक अनुभव से संबंधित दावे का प्रश्न है, यह बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में उनकी शक्ति और आत्मविश्वास को व्यक्त करता है। यह वक्तव्य किसी अन्य देश से पाटन के जरिए अनुचित प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है। जहां तक इस वक्तव्य का संबंध है कि एक्सडीआईपीएल द्वारा चीन से आयातों के कारण भारतीय बाजार पर अभी कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि. ने वर्ष 2004-05 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि "कंपनी को सबसे बड़ा खतरा अर्थव्यवस्था के खुलने और आयात शुल्क में निरंतर कमी के कारण पड़ोसी एशियाई देशों से सस्ते आयातों के कारण है।" प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि दिनांक 11.5.2006 के एफसीसीबी से संबंधित पेशकश जापान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों से संबंधित वक्तव्य यद्यपि पाटनरोधी जांच की शुरुआत के बाद दिया गया था, यही वक्तव्य जीडीआर पेशकश दस्तावेज में भी दिया गया है, क्योंकि यह मार्च, 2005 तक किए गए आयातों के संबंध में है। अन्य संदर्भ में कंपनी द्वारा दिए गए वक्तव्य के मद्देनजर प्राधिकारी का अभिमत है कि इस जांच के परिणाम तथ्यों के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित हैं और ये अन्य संदर्भ में दिए गए वक्तव्यों पर आधारित नहीं हो सकते। इसके अलावा, अन्य संदर्भ में दिए गए वक्तव्य से किसी कंपनी को पाटन के रूप में अनुचित व्यापार के विरुद्ध जांच की मांग में बाधा उत्पन्न नहीं होती है।

घ. 4 कच्चे माल की बढ़ती लागत से घरेलू उद्योग की लाभप्रवृत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा वार्षिक रिपोर्टों एवं जीडीआर ऑफर दस्तावेज में दिए गए वक्तव्य

25. निर्यातक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा वार्षिक रिपोर्टों एवं जीडीआर ऑफर दस्तावेजों में उल्लिखित कार्य-निष्पादन अच्छा कार्य-निष्पादन दर्शाता है और भविष्य में इसका उत्साहजनक चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्टों एवं जीडीआर ऑफर दस्तावेज में इंगित कार्य निष्पादन संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और यह जांच अवधि से संबंधित अवधि में जांच के अधीन संबद्ध वस्तुओं तक सीमित नहीं है। कंपनी के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े संबद्ध वस्तुओं का कार्य निष्पादन नहीं माने जा सकते, अतः क्षति विश्लेषण की दृष्टि से इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं से संबंधित सत्यापित आंकड़ों पर विश्वास किया है।

26. निर्यातक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रमुख कच्चे माल की लागत में असाधारण वृद्धि हुई, जैसा कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों में तथा जीडीआर ऑफर दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है। कच्चे माल की कीमतों में असाधारण वृद्धि के प्रभाव का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग ने विक्रय कीमत में वृद्धि कर दी, परंतु यह वृद्धि कच्चे माल की कीमतों में असाधारण वृद्धि को निष्प्रभावी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह भी बताया गया है कि बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए घरेलू उद्योग ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के उपाय के रूप में संयंत्र में निवेश किया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह "अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और मेट कोक पर पाटनरोधी शुल्क के कारण वृद्धि के मिले-जुले प्रभाव की परिणति खरीद कीमतों में असाधारण वृद्धि में हुई जिसकी अदायगी घरेलू पाइप उद्योग के घरेलू निर्माताओं को करनी पड़ी। इसकी वजह से विनिर्माण की लागत बढ़ गई और परिणामस्वरूप लाभ के मार्जिन में मामूली कमी आई।" आगे यह भी तर्क दिया गया है कि "वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने अपने किसी भी प्रकाशित दस्तावेज में आयातों का लाभ में कमी के कारण के रूप में उल्लेख नहीं किया है और पहली बार डीजीएडी के समक्ष अपनी याचिका में आयातों का क्षति के कारण के रूप में उल्लेख किया है।"

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. जिंदल साँ लि. द्वारा वार्षिक रिपोर्टों तथा जीडीआर ऑफर दस्तावेजों में उल्लिखित अवधि के दौरान डी आई पाइपों का विनिर्माण नहीं किया गया। किसी प्रतिस्पर्धा के अभाव में घरेलू उद्योग को विनिर्माण की बढ़ी हुई लागत का भार उपभोक्ता पर डालने का कोई कारण नहीं था, सिवाय इसके घरेलू उद्योग अपने विक्रय मूल्य की बेंचमार्किंग आयातों के साथ कर रहा था, अतः घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में विक्रय कीमत में वृद्धि नहीं कर सका, जिससे यह स्पष्ट है कि कम कीमत पर आयात के कारण कीमतों में मंदी आ गई। एक्सडीआईपीएल ने तर्क प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने आयातों को घिंता का कारण नहीं बताया था, तथ्यादि प्राधिकारी नोट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लि. ने वर्ष 2004-05 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि "कंपनी को सबसे बड़ा खतरा अर्थव्यवस्था के खुलने और आयात शुल्क में निरंतर कमी के कारण पड़ोसी एशियाई देशों से सस्ते आयातों के कारण है।"

ड पाटन मार्जिन की गणना की विधि एवं बाजार अर्थव्यवस्था की जांच

ड.1 गैर बाजार अर्थव्यवस्था एवं सामान्य मूल्य

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतीकरण

28. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 पर निर्भर रहते हुए आवेदकों ने निवेदन किया है कि चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में विचार करना और सामान्य मूल्य का निर्धारण तदनुसार किया जाना अपेक्षित है, जब तक उपर्युक्त अनुबंध के पैरा-8 की शर्तों के अनुसरण में चीन के किसी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जाता।

29. आवेदकों ने यह भी निवेदन किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमतों के आधार पर किया जाए। आवेदकों ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में स्पेन और फ्रांस का प्रस्ताव किया और इसके समर्थन में कारण भी प्रस्तुत किए। आवेदकों ने उत्पादन प्रक्रिया में भिन्नता, क्षमताओं तथा प्रचालन के आकार तुलनात्मक न होने के आधार पर भूतेशिया को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे समुचित देश के रूप में चयन के एक्सडीआईपीएल के प्रस्ताव का विरोध किया।

30. जहां तक पैराग्राफ 8(3) की शर्तों के अनुसरण में एक्सडीआईपीएल द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे का प्रश्न है, घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का हकदार नहीं है, क्योंकि वह अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिसका उत्तरदायित्व निर्यातक का है। इसके अलावा एक्सडीआईपीएल राज्य के स्वामित्व की कंपनी है जिसमें अधिकांश निदेशक सरकार द्वारा नामित हैं। निर्यातक ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि इसमें राज्य का कोई उल्लेखनीय हस्तक्षेप नहीं है अथवा उत्पादक के कारक जैसे कच्चे माल की कीमतें, उपयोगी सुविधाएं आदि राज्य द्वारा प्रभावित नहीं होते। विश्व व्यापार संगठन के साथ अभिगमन संधि में चीन ने स्वीकार किया है कि कोयला बाजार में राज्य का हस्तक्षेप है और घाटे की स्थिति में इसे सब्सिडी दी जाती है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी निवेदन किया गया था कि चीन सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तथा अन्य सब्सिडियों की भी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए, जैसा कि पिछले मामलों में किया गया है। इसके अलावा यह तथ्य कि विनिमय दर काफी लंबी अवधि के लिए निर्धारित की जाती है, निर्यातकों के लिए प्रच्छल सब्सिडी का द्योतक है, जो चीन के बाजार की गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रदर्शित करता है।

ड.3 मैसर्स जिंगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स कं. लि. (एक्सडीआईपीएल) द्वारा प्रस्तुतीकरण

31. एक्सडीआईपीएल का गठन सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में 1997 में किया गया था। दिनांक 9 नवंबर, 2005 तक एक्सडीआईपीएल की शेयरधारिता निम्नानुसार थी: 64.78% ग्रुप कंपनी द्वारा धारित थे और 35.22% शेयर जनता द्वारा धारित थे। 35.22% शेयर स्टॉक एक्सचेंज में मुक्त रूप से व्यापार योग्य थे और ग्रुप कंपनी के 64.78% शेयरों का अंतरण, परक्रामण अंतरण के माध्यम से किया जा सकता था। माननीय डीजीएडी के प्रश्नों के उत्तरों में वर्णित पद्धति अर्थात् इक्विटी आवंटन सुधार को दिनांक 9 नवंबर, 2005 से प्रभावशील करते हुए ग्रुप कंपनी का होलिंग घटाकर 54.2% कर दिया गया और शेष 10.58% शेयरों का वितरण मौजूदा शेयरधारकों में कर दिया गया। हमारे उत्तरों में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधधीन एक्सडीआईपीएल के 54.2% शेयरों की खरीद-फरोख्त अब मुक्त रूप से शेनजेन स्टॉक एक्सचेंज के केन्द्रीयकृत बिलिंग कारोबार प्रणाली के माध्यम से की जा सकती थी।

32. यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि 64% शेयरधारक के रूप में और अब 54% शेयरों के धारक के रूप में कंपनी कानून के अनेक (क्षोपायों, स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और अपने स्वयं के संगठन अनुच्छेद के माध्यम से इस कंपनी के लिए एक्सडीआईपीएल के प्रचालन पर नियंत्रण करना निषिद्ध है। बाजार सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का स्वतंत्र कार्यचालन-सुनिश्चित करने के लिए इन उपबंधों द्वारा अधिकांश शेयरधारकों की शक्तियों में कटौती और उन्हें विनियमित कर दिया गया है।

33. यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक्सडीआईपीएल के अधिकांश शेयरधारक कंपनी पर नाजायक नियंत्रण न करें और एक्सडीआईपीएल आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रचालनरत रहे, सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में एक्सडीआईपीएल को कानून के अंतर्गत अनेक उपाय करने अपेक्षित हैं। प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं :-

- संगठन अनुच्छेद (एओए) में अपेक्षा की गई है कि नियंत्रक शेयरधारक द्वारा एक्सडीआईपीएल तथा अन्य शेयरधारकों के अधिकारों को क्षति न पहुंचाई जाए और इसमें सुसंगत प्रतिविधानों का भी प्रावधान है ।
- एओए में अपेक्षा की गई है कि हितबद्ध शेयरधारक तथा हितबद्ध निदेशक संबद्ध सौदे के लिए मतदान में भाग नहीं लेंगे ।
- कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति सुस्थापित की गई है, जिनकी संख्या निदेशकों की कुल संख्या की एक तिहाई से कम नहीं होगी । स्वतंत्र निदेशक कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों के रिश्तेदार नहीं होंगे और उन्हें महत्वपूर्ण संबद्ध सौदे जैसे मामलों के संबंध में वीटो का अधिकार प्रदान किया गया है ।
- महत्वपूर्ण संबद्ध सौदे के संबंध में, अर्थात् वह सौदा जिसमें कंपनी तथा संबद्ध व्यक्ति के बीच निष्पादित सौदे की कुल राशि 30 मिलियन आर एम बी युआन से अधिक हो और कंपनी के नवीनतम अंकेक्षण के अनुसार निवल परिसंपत्तियों का मूल्य 5% से अधिक हो तो ऐसे सभी सौदे निदेशक मंडल को विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व इन पर स्वतंत्र निदेशक की स्वीकृति अपेक्षित है । स्वतंत्र निदेशक द्वारा निर्णय लेने में सहायता करने के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरण जारी करने हेतु स्वतंत्र निदेशक किसी मध्यवर्ती संगठन की सेवाओं को किराए पर ले सकता है ।
- ए ओ ए के अनुच्छेद 109 में कंपनी के अनेक महत्वपूर्ण मामलों में स्वतंत्र निदेशक से स्वतंत्र अभिमत की अपेक्षा की गई है ।
- चीन के कंपनी कानून में कंपनी के शेयरधारकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे कंपनी अथवा किसकी अन्य शेयरधारक के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे । उनसे कंपनी के हित में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, न कि इसके शेयरधारकों के । चूक के मामले में ऐसे शेयरधारक को मुआवजा देना होता है ।
- स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की लिस्टिंग के नियंत्रण से संबंधित नियमावली के अध्याय-IX में यह प्रावधान है कि कोई संबंधी निदेशक, संबंधी पार्टी के सौदे से संबंधित विचार-विमर्श में शामिल नहीं होगा और कतिपय परिस्थितियों में ऐसे सौदे शेयरधारकों की मंजूरी के अधधीन होंगे । लिस्टेड कंपनियों को सभी संबंधित सौदों के अंशों के ब्यौरे उद्घाटित करने का अधिदेश है ।
- लिस्टेड कंपनियां नैगमिक अभिशासन आचार संहिता द्वारा भी नियंत्रित हैं । जिसमें विवेकपूर्ण पारदर्शी व्यवहार अधिदेशित है और अन्य पहलुओं के साथ यह भी विशिष्ट रूप से अधिदेशित है कि नियंत्रक शेयरधारक के लिए कंपनी के निर्णयों में दखलंदाजी करना निषिद्ध है और उसके लिए कंपनी की वित्तीय स्वतंत्रता का सम्मान करना भी निर्देशित है ।

34. उपर्युक्त के अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्रुप कंपनी के संगठन अनुच्छेद में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनमें अधिदेशित है कि ग्रुप कंपनी अनुषंगी कंपनियों के प्रचालनों में हस्तक्षेप नहीं करेगी । अनुच्छेद 16 के कुछ प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल है :-

- एक स्वतंत्र कानूनी सत्ता के रूप में अनुषंगी कंपनियों को अपनी संपत्तियों पर स्वतंत्र अधिकार है, नागरिक अधिकारों का लाभ उठाने, नागरिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने और अपने प्रचालन स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने का अधिकार है और कानून

के अनुसार राज्य के स्वामित्व की परिसंपत्ति का रखरखाव एवं उसमें वृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिकार है।

- अनुषंगी कंपनियों को नियोजन, भंडारण, बिक्री, मूल्य निर्धारण, मानव संसाधन, वितरण एवं संगठनात्मक ढाँचे तथा अन्य विषयों के बारे में निर्णय लेने और तीन स्तरीय सुधारों को जारी रखने, फिजूल मामलों के निपटान और कंपनी के सामाजिक कार्य के व्यवच्छेदन का अधिकार है।
- अनुषंगी कंपनियों के बीच संबंध का प्रबंधन बाजार के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है और कार्यकलाप हस्ताक्षरित करारों द्वारा विनियमित होते हैं।

35. यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्रुप कंपनी एक लाम में चलने वाला उद्यम है। ग्रुप कंपनी की लामप्रदता इसकी दिनांक 31 दिसंबर, 2005 के तुलनपत्र और आय विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों से सिद्ध होती है, जिनमें नकद राशि तथा एक्सडीआईपीएल की नकद के समतुल्य राशि *** मिलियन आर एम बी युआन, कुल परिसंपत्तियां *** मिलियन युआन तथा लाम *** मिलियन युआन बताया गया है।

36. एक्सडीआईपीएल ने आगे यह अनुरोध किया है कि केवल शेयरधारिता की प्रणाली को बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक संकेतक नहीं माना जा सकता। वस्तुतः भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे कई उपक्रम, जिनके पास सरकारी शेयरधारिता है, पूर्णतः बाजारी सिद्धांतों पर प्रचालन करते हैं। इसी प्रकार अधिकांश क्षेत्राधिकारों में कंपनियों को शासित करने वाले कानून में खासकर निजी कंपनियों के लिए शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध की अनुमति है और ऐसे प्रतिबंधों का बाजारी सिद्धांतों के आधार पर कंपनी के प्रचालन पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

37. कच्ची सामग्री की कीमतों के संदर्भ में यह अनुरोध किया गया है कि एक्सडीआईपीएल के पास कड़ी क्रय प्रणाली है और वह कच्ची सामग्री की खरीद कर उसकी आपूर्ति कीमतों की सावधानीपूर्वक तुलना करने और बातचीत करने के बाद और अक्सर सार्वजनिक बोली प्रणाली के जरिए चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं से अपने प्रचालनों के लिए अपेक्षानुसार की जाती है। कंपनी किसी प्रकार की कच्ची सामग्री के लिए किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर नहीं है। यह हमेशा कीमत की जाँच कर और बाजार में उत्पाद के कार्यों की तुलना कर 3 या 3 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं में से सर्वोत्तम आपूर्तिकर्ता का चुनाव करती है।

38. सबसे महत्वपूर्ण संकेतक जो एक्सडीआईपीएल अपने आपूर्तिकर्ताओं में देखती है वह उत्पाद की कीमत और उसके कार्य हैं। सर्वोत्तम आपूर्तिकर्ता की पहचान करने और उसे बरकरार रखने के लिए एक्सडीआईपीएल किसी अक्षम आपूर्तिकर्ता को दूर रखने के लिए बोली जैसे अनेक उपायों का उपयोग करती है। बोली के जरिए चुना गया आपूर्तिकर्ता सीमित समयावधि के लिए आपूर्ति की संविदा करता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे आपूर्तिकर्ता का चयन अगली बोली में कर लिया जाएगा। आपूर्ति की दीर्घावधि संविदा का

कोई आश्वासन नहीं होता है और कच्ची सामग्री के लिए कोई अनन्य आपूर्तिकर्ता नहीं है । कच्ची सामग्री की खरीद बोली प्रक्रिया के जरिए ही की जाती है ।

39. जहां तक उपयोगिताओं का संबंध है यह अनुरोध किया गया है कि एक्सडीआईपीएल बिजली की खरीद वाणिज्यिक दरों पर करती है जिससे यह सिद्ध होता है कि एक्सडीआईपीएल बिजली की वाणिज्यिक दरें अदा करती है । एक्सडीआईपीएल कोयले की खरीद प्रतिस्पर्धी दरों पर खुले बाजार से करती है । चीन की सरकार ने फिलहाल मेटालर्जिकल उपयोग हेतु कोयले एवं कोक की कीमतों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है । जहां तक निर्यात कोटे का संबंध है यह बताया गया है कि वर्ष 2005 में कोक का निर्यात कोटा 14,000000 मी.टन का था जबकि वास्तविक निर्यात 12000000 टन का हुआ था, इसलिए कोक के कोटे से निर्यात सीमित नहीं हुआ है । कोयले और कोक की कीमतों में मांग और आपूर्ति के साथ-साथ उतार-चढ़ाव आता है । उदाहरण के लिए वर्ष 2005 में बाजार कीमत में वर्ष 2003 की तुलना में 40% से अधिक की वृद्धि हुई । इसके अलावा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि चीन के घरेलू बाजार में कोक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के काफी समान है और कोक के निर्यात कोटे से निर्यात प्रभावित नहीं होते हैं ।

40. जहां तक चीन में विदेशी विनिमय दरों का संबंध है, यह अनुरोध किया गया है कि जुलाई, 2005 से पूर्व चीन में विदेशी विनिमय पद्धति प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली की थी । इस प्रणाली के अंतर्गत चीन का बैंक विदेशी विनिमय दरों के आधार पर विनिमय दर निर्धारित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विनिमय दर का रखरखाव स्थिर स्तर पर किया गया है । इस प्रकार चीन में स्थिति का सर्वोत्तम उल्लेख स्थिर स्थिति में रखरखाव करने के रूप में किया गया है न कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए स्तर के रूप में । 21 जुलाई, 2005 से जैसा कि कई अन्य देशों के मामले में हुआ है, चीन ने बाजार मुद्रा का संदर्भ देते हुए बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर प्रबंधित चल मुद्रा प्रणाली को अपनाया है । अतः बाजारी शक्तियां विनिमय दर के निर्धारण में अधिक भूमिका निभाती हैं ।

41. जहां तक प्रतिनिधि देश का संबंध है, एक्सडीआईपीएल ने "समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश" के रूप में स्पेन अथवा फ्रांस का चयन करने के घरेलू उद्योग के प्रस्ताव के बारे में इस आधार पर आपत्ति व्यक्त की है कि इन दोनों देशों और चीन के बीच आर्थिक विकास तुलनीय नहीं है । स्पेन में प्रमुख कच्ची सामग्रियों की लागत चीन की लागत से अधिक है । स्पेन के उत्पादक को ढलवां लोहे की खरीद करनी होती है और तत्पश्चात उसे पाइपों की ढलाई हेतु तरल लोहे में बदलना होता है जबकि एक्सडीआईपीएल के पास अपना खुद का गलाई संयंत्र है जहां तरल सामग्री को सीधे ही पाइपों में ढालने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में भेज दिया जाता है । स्पेन में श्रम और विद्युत की लागत चीन की लागत से काफी अधिक है । निर्यातक ने समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में मलेशिया का प्रस्ताव किया है ।

ड 4 मै. जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप कं. लि. द्वारा प्रस्तुत उत्तर की बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार की दृष्टि से जांच

42. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियम के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) के अनुसार इस अनुमान के आधार पर आगे कार्रवाई की है कि ऐसा कोई देश गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है जिसका पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अथवा डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में निर्धारण किया गया है या उसे ऐसा ही माना गया है। पिछले तीन वर्षों में ई.यू. तथा अमरीका जैसे डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। इस मामले में चीन जन.गण. की जांच गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में करने का प्रस्ताव था।

43. यथासंशोधित पाटनरोधी नियम के पैरा 8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर सूचना एवं पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराता है और इसके विपरीत सिद्ध करता है। चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले व्यवहार से संबंधित प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा 3 में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सके कि क्या:-

(क) कीमत, लागत तथा कच्ची सामग्री सहित निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम, उत्पादन, बिक्री की लागत तथा निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों के निर्णय आपूर्ति एवं मांग को प्रदर्शित करने वाले बाजारी संकेतकों के उत्तर में और इस संबंध में राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप के बिना लिए गए हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजारी मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन किया गया है ;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के संबंध में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से आई पर्याप्त विकृतियों के अधीन है ;

(ग) ऐसी फर्मों दीवालियापन एवं संपत्ति कानूनों के अधीन है जिनके तहत फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थायीत्व की गारंटी है; तथा

(घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजारी दर के अनुसार किए जाते हैं।

44. सामान्य मूल्य के निर्धारण प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने प्रश्नावलियों की प्रतियां समस्त ज्ञात निर्यातकों को भेजीं। एक उत्पादक/निर्यातक मै. जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप कं.

लि. (एक्सडीआईपीएल) से उत्तर प्राप्त हुआ है और कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार (एमईटी) का दावा किया है।

45. निर्यातक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मै. जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप कं. लि. (एक्सडीआईपीएल) चीन जनवादी गणराज्य के निगम कानूनों के अधीन संगठित तथा विद्यमान एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है। यह भी बताया गया है कि जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप (समूह) कंपनी ("समूह" कंपनी) एक्सडीआईपीएल की नियंत्रक कंपनी है। समूह कंपनी के पास इस समय एक्सडीआईपीएल के 54% शेयर हैं (सत्यापन के दौरान यह बताया गया था कि 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार उक्त समूह कंपनी द्वारा 50.04% शेयर धारित किए गए हैं।) आगे यह बताया गया था कि एक्सडीआईपीएल की 3 सहायक कंपनियां हैं अर्थात् (क) वुहु जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी (ख) हेबी जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी, तथा सिजिआझुआंग जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी। एक्सडीआईपीएल, समूह कंपनी, सिजिआझुआंग फैक्टरी तथा इंग्लिश रियल टाइप प्रोडैक्ट लि. के अलावा सहायक कंपनियों के पास भी शेयरधारिता है तथापि, अधिकांश शेयर एक्सडीआईपीएल धारित किए गए हैं। (सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि सिजिआझुआंग जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स कंपनी लि. को बंद कर लिया गया था। सत्यापन के बाद यह सूचित किया गया था कि उत्पादन की उच्चतर लागत के कारण कंपनी का विनिर्माण कार्यकलाप जून, 2006 से बंद कर दिया गया था।)

46. कंपनी समूह राज्य की स्वामित्व वाली एक कंपनी है इसकी देयता सीमित है। इसकी 100% शेयरधारिता राज्य के स्वामित्व वाले परिसंपत्ति पर्यवेक्षण एवं प्रशासन आयोग में निहित है। इस कंपनी समूह की स्थापना सेना रक्षोपाय उद्यम सुपुर्दगी एवं आधिपत्य कार्य समूह द्वारा प्रख्यापित सेना द्वारा अंतरित रक्षोपाय उद्यमों से संबंधित कार्यान्वयन योजना एवं समग्र निपटान अभिमत मुद्रण एवं कार्यान्वयन योजना के प्रख्यापन हेतु अधिसूचना (सी.जे.(2001)से. 4) और चायनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सामान्य संभारतंत्र विभाग द्वारा जारी "जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स (ग्रुप) कंपनी लि. के प्रचालन एवं प्रबंधन हेतु अनुमोदन" (एल.ए.(2001) सं. 368) के अनुसरण में 8 जनवरी, 1997 को की गई थी। तथा सेना आपूर्ति शाखा और सामान्य संभारतंत्र विभाग के क्विंग जांग आर्मी सर्विस स्टेशन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित उद्यमों तथा अन्य सैन्य आपूर्ति सत्ताओं को जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स (ग्रुप) कंपनी लि. को अंतरित कर दिया गया था जिसका नाम बदलकर उसी समय जिगजिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स ग्रुप कंपनी लि. कर दिया गया था। संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11 के अनुसार कंपनी के व्यापार कारोबार में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की सहायक कंपनियों एवं अनुषंगी कंपनियों का प्रचालन तथा प्रबंधन डक्टाइल आयरन पाइप्स, कंपाउंड पाइप तथा उसकी फिटिंग, इंजीनियरी मशीन और अन्य यांत्रिक उपकरण, वस्त्र, कपड़ा, चमड़ा तथा सुचर्म, का उत्पादन एवं बिक्री, उत्पादन एवं रबड़ उत्पाद का उत्पादन एवं बिक्री शामिल हैं।

47. चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद की राज्य के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के उपक्रमों की बिक्री के पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित अंतरित विनियम संख्या 378

("विनियम") के अनुच्छेद 2 के अनुसार ये विनियम अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों तथा राज्य की स्वामित्व वाली इक्विटी के उपक्रमों पर लागू होते हैं ।

48. विनियमों के अनुच्छेद 3 में "उद्यमों की राज्य स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों" पद को उद्यमों में राज्य के समस्त निवेशों तथा उससे सृजित इक्विटियों और राज्य द्वारा स्वामित्व के रूप में विधिक रूप से निर्धारित अन्य इक्विटियों के रूप में परिभाषित किया गया है । इन अनुच्छेदों में यह उल्लेख है कि ये विनियम "ग्रुप" कंपनी तथा एक्सडीआईपीएल दोनों पर लागू होते हैं । "ग्रुप" पर 100% स्वामित्व राज्य का है जबकि एक्सडीआईपीएल में 50% से अधिक की इक्विटी "ग्रुप" के जरिए राज्य द्वारा धारित है ।

49. मौके पर सत्यापन के दौरान निर्यातक द्वारा यह बताया गया था कि उपर्युक्त विनियम एक्सडीआईपीएल पर लागू नहीं होते हैं इसके बजाय इस कंपनी पर चीन जन.गण. का कंपनी कानून लागू होता है । तथापि, विनियम में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और राज्य की स्वामित्व वाली इक्विटी वाले उद्यमों पर लागू होते हैं । इस मामले में एक्सडीआईपीएल में 50% से अधिक की इक्विटी "ग्रुप" के जरिए राज्य द्वारा धारित है ।

50. यह भी तर्क दिया गया है कि "ग्रुप" कंपनी को कंपनी लॉ में अनक रक्षोपायों, स्टॉक एक्सचेंज के नियमों तथा उसके खुद के संस्था के अंतर्नियमों के जरिए एक्सडीआईपीएल के प्रचालन पर नियंत्रण रखने से निषिद्ध किया जाता है । इन उपबंधों से अधिकांश शेयरधारकों की शक्तियां कम हो जाती हैं और विनियमित होती हैं ताकि बाजारी सिद्धांतों पर कंपनी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके ।

51. तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विनियमों के अनुच्छेदों में से लिए गए निम्नलिखित संगत अनुच्छेदों में यह उल्लेख है कि राज्य द्वारा कंपनी के प्रबंधन का किस प्रकार पर्यवेक्षण किया जा सकता है और उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है और कंपनी को परिसमाप्त नहीं किया जा सकता है :-

अनुच्छेद 11..... निवेशक उद्यमों को कानून के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले परिसंपत्ति पर्यवेक्षण एवं प्रशासन प्राधिकारण द्वारा किए गए पर्यवेक्षण और प्रशासन को स्वीकार करना होगा और वे उद्यमों तथा अन्य निवेशकों की राज्य की स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के स्वामियों को मिले विधिसम्मत अधिकारों और हितों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे ;

अनुच्छेद 13.....(4) निवेशक उद्यमों के जिम्मेदार व्यक्तियों की नियुक्ति करना अथवा उन्हें हटाना तथा सांविधिक प्रक्रियाओं के अनुसार उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर पुरस्कार प्रदान करना या दंड लगाना;

(6) उद्यमों की राज्य की स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के पर्यवेक्षण और प्रशासन के संबंध में नियम एवं प्रणालियां तैयार करना ।

अनुच्छेद 14..... (1) राज्य की अर्थव्यवस्था के लेआउट और संरचना का समायोजन करना;

(6) राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का मार्गदर्शन और समन्वयन करना;

अनुच्छेद 16..... उद्यमों के जिम्मेदार व्यक्तियों का चयन और उनकी नियुक्ति करना तथा ऐसे प्रोत्साहनों एवं प्रतिबंधों का तंत्र तैयार करना जो आधुनिक उद्यम प्रणाली की जरूरतों को पूरा करता हो ।

अनुच्छेद 17..... अपने निवेशित उद्यमों के जिम्मेवार व्यक्तियों की नियुक्ति करना या उन्हें हटाना;

(3) निदेशक मंडल के लिए अभ्यर्थी को नामित करना

(4) कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशक मंडल के लिए अभ्यर्थी या राज्य की स्वामित्व वाली इक्विटी की कंपनी से संलग्न किए जाने हेतु पर्यवेक्षक को नामित करना ।

अनुच्छेद 18..... उद्यमों के जिम्मेवार व्यक्तियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना

अनुच्छेद 19..... पारिश्रमिक, पुरस्कारों या लगाये जाने वाले जुर्माने का निर्धारण करना ।

अनुच्छेद 21..... राज्य के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति के पर्यवेक्षण एवं प्रशासन संबंधी प्राधिकरण द्वारा विखंडन/विलय, दिवालियापन, संस्था भंग, पूंजी वृद्धि या कमी, पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यमों के कंपनी बाँडों को जारी करने जैसे प्रमुख मामलों पर निर्णय लेता है ।

अनुच्छेद 22..... शेयरधारकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति अपनी राय जाहिर करना तथा राज्य के स्वामित्व वाले परिसंपत्ति पर्यवेक्षण तथा प्रशासन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार मताधिकार का प्रयोग करना ।

अनुच्छेद 26..... पारिश्रमिक प्रणाली के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना

52. कंपनी से निदेशकों के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए कहा गया था । यह बताया गया था कि एक्सडीआईपीएल के 9 निदेशक हैं जिनमें से 3 की संस्तुति "समूह" द्वारा की गई है, 3 सार्वजनिक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 स्वतंत्र निदेशक हैं । सभी निदेशकों का चयन सामान्य बैठक (जीबीएम) द्वारा किया जाता है । यह भी स्पष्ट किया गया था कि पिछले निदेशक मंडल ने जीबीएम में चयन हेतु जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 निदेशकों के नामों की संस्तुति की थी । 6 निदेशकों ने 3 स्वतंत्र निदेशकों के नामों की संस्तुति की थी । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चोटी के 10 सार्वजनिक शेयरधारक अलग-अलग 1% से अधिक शेयर धारित करते हैं । 1% से कम की शेयरधारिता वाले शेयर

धारक निदेशकों के लिए किसी अभ्यर्थी को नामित नहीं कर सकते हैं। रोचक तथ्य यह है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक 2000 से लेकर 2006 तक बदले नहीं गए हैं। एक्सडीआईपीएल की वार्षिक रिपोर्ट से यह भी देखा गया है कि कंपनी के अनेक निदेशक एक ही साथ "ग्रुप", एक्सडीआईपीएल तथा सहायक कंपनियों में पदाधिकारी रहे थे। चयन प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त निदेशक या तो "ग्रुप" के नामित हैं या फिर उन्हें "ग्रुप" नामित निदेशकों द्वारा नामित किया गया है। कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार "समूह" तथा "जनता" का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 निदेशक कार्यकारी निदेशक हैं। कंपनी के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक के पद का कार्य "ग्रुप" का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों द्वारा किया जाता है। 6 कार्यकारी निदेशकों के अलावा 9 अन्य पदाधिकारियों को विभागाध्यक्ष के रूप में दर्शाया गया था लेकिन उनके पदनामों और पदक्रमों को स्पष्ट नहीं किया जा सका। सत्यापन के बाद कुछेक पदाधिकारियों की नियुक्ति को दर्शाने वाले सत्यापन कागजातों के साथ-साथ एक दस्तावेज भेजा गया था। तथापि, उनके पदनाम और पदक्रम में अभी भी अस्पष्ट बने हुए हैं।

53. कंपनी से निर्यात एवं घरेलू बिक्री हेतु कीमत निर्धारण के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। न तो ऐसी किसी प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सका और न ही सत्यापन दल को कार्यवृत्त के रूप में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किया गया था।

54. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, 2005 में किए गए उल्लेख के अनुसार कंपनी को निर्यात सब्सिडी प्राप्त हुई है। इस सब्सिडी का उल्लेख कंपनी की शेयरधारक सहायक कंपनी, वुहु जिगजिंग द्वारा प्राप्त वित्त औद्योगिक पुरस्कार निधि से अर्जित आय और इस आधार पर प्राप्त आय के रूप में किया गया है कि वुहु सरकार और अधिक क्षमता के साथ सीमलैस लोहे के पाइपों के आर एंड डी हेतु वुहु जिगजिंग को प्रोत्साहित करती है। मौके पर सत्यापन के दौरान वुहु स्थित कंपनी की एक सहायक कंपनी में ऐसा कोई आर एंड डी केन्द्र नहीं देखा जा सका।

55. वर्ष 2005 की वार्षिक रिपोर्ट से यह देखा गया था कि "ग्रुप" को पर्याप्त राशि का भुगतान किया जाना है। यह स्पष्ट किया गया था कि यह राशि "समूह" को देय दीर्घावधि भुगतान हो और "इन बकाया राशियों के लिए वित्तीय प्रभार अदा करने की कोई जरूरत नहीं है।"

56. कोक की कच्ची सामाग्री सरकार के निर्यात नियंत्रण के अधीन है। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में चीन सरकार अभी भी कोटा पर निर्यात कोर लगाती है तथापि, चूंकि चीन के घरेलू बाजार में कोक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कीमत की समतुल्य है, इसलिए कोक पर निर्यात कोटा से निर्यात प्रभावित नहीं होता है। यह उल्लेख किया गया है कि 2005 में कोक का निर्यात कोटा 14,000,000 मी० टन था जबकि वास्तविक निर्यात 12,000,000 मी. टन का हुआ था। यह भी उल्लेख किया गया है कि धातुकर्मीय उपयोग के लिए 2005 में कोयला एवं कोक के बाजार कीमत में 2003 के मूल्य की तुलना में 40% से ज्यादा की वृद्धि हुई और 2005 में चीन जनवादी गणराज्य से लगभग 140-150 अमरीकी डालर प्रति टन सी.आई.एफ. मूल्य का कोक का निर्यात किया गया था।

57. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने में निर्यातक ने जीडीआर पेशकश में उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है जिसमें इलेक्ट्रो स्टील ने उल्लेख किया है कि 2003 से 2005 में एलएएमसी की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में कीमत 166.4 प्रति मी० टन अमरीकी डालर थी जबकि 2005 में कीमत 354.8 प्रति मी. टन अमरीकी डॉलर थी तथापि गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को खंडन करने के क्रम में निर्यातक ने घरेलू उद्योग के इस दावे का खंडन किया है कि चीन में चीन की सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माताओं को मेट कोक 80-100 प्रति मी. टन अमरीकी डॉलर की दर से बेचा जा रहा था जबकि कोक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रति मी० टन 400 अमरीकी डालर से ऊपर थी।

58. प्राधिकारी मानते हैं कि कोटा के निर्यात कोर की दृष्टि से चीन में धात्विक कोक की कीमत बाजार सिद्धांत के अनुसार कीमत प्रदर्शित नहीं कर सकती है। (वर्तमान में भारत एवं चीन जनवादी गणराज्य के मेट कोक पर पाटनरोधी शुल्क हैं)

59. समूह में लागू उल्लिखित विनियमन के प्रावधानों तथा एक्स डी आईपीएल के संबंध में राज्य का हस्तक्षेप, निदेशकों की चयन प्रक्रिया, बाजार सिद्धान्तों के अनुरूप कीमतों के संबंध में निर्णय लेने में साक्ष्य का अभाव, निर्यात सहायता प्रमुख कच्ची सामग्री पर निर्यात नियंत्रण की ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि एक्सडीआईपीएल के गैर बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का खंडन नहीं किया गया है।

5.5 सामान्य कीमत

60. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का खंडन करने के लिए सहयोगी निर्यातक की असफलता के दृष्टिकोण से प्राधिकारी चीन के निर्यातक के लिए सामान्य कीमत के निर्धारण हेतु अनुच्छेद 1 से 6 के अनुबंध-1 में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू करने में असमर्थ है। इसलिए, चीन जनवादी गणराज्य के सभी निर्यातक/उत्पादकों के लिए सामान्य कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 7 के अनुबंध-1 में यथा निहित गैर बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित नियमावली के अनुसार किया जाता है।

61. पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 7 के अनुबंध-1 के अनुसार प्राधिकारी को तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत के आधार पर अथवा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित दूसरे देशों की कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है अथवा समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप में अदा किए गए मूल्य अथवा अदा की जाने वाली कीमत सहित किसी दूसरे उचित आधार पर सामान्य कीमत का निर्धारण करना अपेक्षित है।

62. जांच के समय घरेलू उद्योग ने सामान्य कीमत निर्धारण के लिए स्पेन और फ्रांस के उपर्युक्त तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की थी। सहयोगी निर्यातक और आयातक ने स्पेन और फ्रांस की तृतीय देश के उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चयन का अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विरोध किया कि चीन जनवादी गणराज्य और स्पेन एवं फ्रांस का विकास तुलनीय नहीं है। सहयोगी निर्यातक ने इसके स्थान पर मलेशिया

को तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में लेने का सुझाव दिया । प्राधिकारी ने तृतीय देश की उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मलेशिया का चयन किया तथा मलेशिया के उत्पादकों को (निर्यातक एवं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादकों के नाम सुझाए गए थे) मलेशिया में सामान्य कीमत के निर्धारण के लिए सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था । मलेशिया के किसी निर्यातक ने प्राधिकारी के पत्रों का उत्तर नहीं दिया तथा कोई सूचना नहीं दी । इसलिए प्राधिकारी तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं है ।

63. जांच अवधि के दौरान दूसरे देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं हुआ है इसलिए तृतीय देश से भारत की निर्यात कीमत भी उपलब्ध नहीं है । इसलिए किसी अन्य विकल्प के अभाव में प्राधिकारी ने किसी अन्य उचित आधार पर पद्धति को अपनाकर सामान्य कीमत का निर्धारण किया है ।

ड 6 चीन के लिए सामान्य कीमत मूल्य

64. परिस्थिति के अधीन, प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर डीआई पाइप्स के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, सहयोगी निर्यातक के खपत मानदंड उपयोगिता, एवं घरेलू उद्योग की अन्य लागतों पर विचार करके सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है । सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए 5% की दर से उचित लाभ भी जोड़ा गया है । उपर्युक्त उपलब्ध सूचना के आधार पर, जांच अवधि के दौरान 1 अमरीकी डॉलर = 44.27 के औसत विनिमय दर पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य की गणना ***/ मी. टन अमरीकी डॉलर दी गई है ।

ड 7 मै. जिनसिंग डक्टाइल आइरन पाइरस के लिए निर्यात मूल्य ।

65. निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि डीआई पाइप्स की बिक्री ग्रेड ()@ वार होती है क्योंकि निश्चित ग्रेड के पाइप्स का उपयोग कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है । छोटे और बड़े ग्रेड के डीआई पाइप्स के उत्पादन लागत में काफी अंतर होता है । यह भी बताया गया है कि एक्स डीआईपीएल ने उन सभी ग्रेडों का जिसका वह उत्पादन करता है, निर्यात नहीं किया है तथा निर्यात कुछ ग्रेड नामतः डी एम 250, 300, 350, 450, 500 और 600 तक सीमित रखा गया है । यह तर्क दिया गया है कि पाटन मार्जिन की गणना पहले ग्रेड वार किया जाए । इस संबंध में प्राधिकारी ने एक्स डीआई पीएल द्वारा किए गए निर्यात की प्रति एकक कीमत की जांच की है । व्यास के आधार पर प्रति इकाई कीमत में काफी अंतर है, तथापि भार के एकक के रूप में, औसत कीमत में 1% ज्यादा या कम का अंतर है चूंकि उत्पाद के भार के रूप में प्रति इकाई कीमत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए सभी निर्यातकों के भारित औसत निर्यात मूल्य का निर्धारण किया गया है ।

66. निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए दो निर्यात सौदों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है । एक सौदा सीधे भारत में निर्यातक मै. जे वी गोकल एवं कंपनी को किया गया है दूसरे निर्यात सौदे में, निर्यातक द्वारा लदान सीधे भारत भेजा गया है, तथापि

निर्यात बीजक में किंग्सबर्ग एक्सपोर्ट्स लि. हांगकांग के नाम पर बनाया गया था । मै. किंग्सबर्ग एक्सपोर्ट्स लि. ने बदले में आयातक मै. जे वी गोकल एवं कंपनी के लिए बीजक बनाया था । मै. जिनसिंग से किंग्सबर्ग का एवं किंग्सबर्ग से आयातक का निर्यात कीमत समान है । मै. जिनसिंग ने बताया है कि किंग्सबर्ग के बीच सौदा मूल से मूल आधार पर किया गया था ।

67. निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर देने के क्रम में निर्यातक ने एक संविदा करार पेश किया था जिसमें मै. किंग्सबर्ग एक्सपोर्ट्स लि., हांगकांग ने पक्के कागज पर भारत के प्राधिकारी को बताया था कि वह भारत में मै. जिनसिंग डीआई पाईप्स (समूह) पीआरसी का एकमात्र अधिकृत एजेंट है । निर्यातक को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि कैसे मूल से मूल आधार पर सौदा किया गया था जबकि आपूर्तिकर्ता ने भारत में प्राधिकारी के समक्ष यह बताया था कि वह निर्यातक के लिए अधिकृत एजेंट है । उत्तर में यह बताया गया था कि किंग्सबर्ग ने बिना उनकी जानकारी के तर्क दिया था । तथापि निर्यातक ने न तो एक मात्र अधिकृत एजेंट होने के संबंध में मै. किंग्सबर्ग के दावे को निरस्त करने वाला कोई दस्तावेज दिखाया और न ही किंग्सबर्ग को भारत में उनके एक मात्र अधिकृत एजेंट के दावे को सीमित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज दिखाया गया है । यह भी नोटिस किया गया है कि निर्यातक भारत में आयातक मै. जे वी गोकल एवं कंपनी के कार्यालय से परिचालन कर रहा है । निर्यातक द्वारा यह भी बताया गया है कि आयातक को भारत में उनकी सुविधा का उपयोग करने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

68. उपलब्ध दस्तावेज के दृष्टिकोण से प्राधिकारी निर्यातक के इस दावे को कि किंग्सबर्ग को मूल से मूल आधार पर सौदा विशेषकर बिक्री कीमत जिस पर मै. किंग्सबर्ग ने समान मै. जे वी गोकल एवं कंपनी को निर्यात किया था, का एक्सीडी आईपीएल से उसकी खरीद कीमत के बराबर होने को ध्यान में रखकर किया था, स्वीकार करने में असमर्थ है, किंग्सबर्ग के माध्यम से भारत में निर्यात सौदा किया गया है, इसलिए कारखाना पूर्व निर्यात कीमत निर्धारण करने के लिए इस सौदे को भी 5% की दर से कमीशन घटाकर लिया गया है ।

69. निर्यात बिक्री के लिए तत्काल सत्यापन के दौरान, निर्यातक ने घरेलू भाड़ा, एजेंट भेजने, उपस्कर, विदेशी भाड़ा, विदेशी बीमा ऋण लागत, गुणवत्ता जांच से संबंधित खर्चों के संबंध में कोई मूल दस्तावेज नहीं दिखलाया । घरेलू बिक्री सौदों लिए मूल्य दस्तावेज से एक भी सौदे का सत्यापन नहीं किया जा सका । बाद में घरेलू बिक्री के कुछेक बीजक दिए गए थे जिससे एक्सीडीआईपीएल और चीन के दूसरे पाइप उत्पादकों की बिक्री कीमतों की तुलना प्रदर्शित होती है, तथापि, इन बीजकों को मूल रिकार्ड से सत्यापित होने पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

70. भारत औसत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए सौदावार विवरण पर भरोसा किया गया है । कारखाना पूर्व भारत औसत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए देशीय भाड़ा, बीमा, विदेशी भाड़ा, वैट भुगतान के कारण

अंतर और उपष्करों के मूल्य पर हुए खर्च को समायोजित कर दिया गया है । कारखाना पूर्व भारत औसत कीमत की गणना *** प्रति मी. टन अमरीकी डॉलर किया गया है ।

ड 8. चीन के असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत ।

71. असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य से, आईबी आई एल द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे वार विवरण पर विश्वास किया गया है । कारखाना पूर्व निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए सहयोगी निर्यातकों द्वारा दावा किए गए खर्च के समायोजन पर विश्वास किया गया है । प्रकटीकरण विवरण (ई-प्रति) के साथ समायोजन से संबंधित व्ययों संबंधी गणना भी निर्यातक को अग्रेषित की गई थी, जिसमें वैट के समायोजन की गणना निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों (ई-प्रति) के आधार पर की गई थी । प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करने के बाद यह ध्यान में लाया गया कि वैट के संबंध में समायोजन गलत तरीके से किया गया है । तथापि, गलत तरीकों को दर्शाते हुए प्राधिकारी को कोई गणना नहीं भिजवाई गई है । यह स्पष्ट नहीं है कि गलत गणना कैसे की गई, जब गणना करने के लिए निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है । अतः कारखाना द्वारा निर्यात कीमत की गणना हेतु पहले की गई गणना जिसे निर्यातक को भिजवाया गया था, पर विचार किया गया है ।

72. जांच अवधि के दौरान निर्यात कीमत का सीआईएफ मूल्य *** प्रति मी. टन अमरीकी डॉलर था। देशी भाड़ा और बीमा को *** / मी. टन अमरीकी डॉलर महानगरीय भाड़ा और बीमा को *** / मी टन अमरीकी डॉलर उपष्कर को *** मी. टन तथा वैट भुगतान के कारण अंतर को *** मी. टन लेते हुए समायोजन करने के बाद कारखाना पूर्व निर्यात कीमत की गणना *** / मी. टन अमरीकी डॉलर किया गया है । जांच अवधि के दौरान (1 अमरीकी डॉलर = 44.27

ड 9. पाटन मार्जिन

73 ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया :

पाटन मार्जिन

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य अमरीकी डॉलर/मी.टन	निर्यात कीमत अमरीकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन अमरीकी डॉलर मी. टन
जिनसिंग डक्टाइल आयरन क. लि.	***	***	*** 49.11%
चीन जनवादी गणराज्य के अन्य निर्यातक	***	***	*** 53.44%

उपर्युक्त निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम है ।

(च) क्षति निर्धारण की पद्धति और कारणात्मक संबंधों की जांच ।

क्षति विश्लेषण संबंधी तर्क

(च) 1. घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

आयात की मात्रा

74. यह प्रस्तुत किया गया है कि पूरी जांच अवधि के दौरान चीन से आयात दो भिन्न श्रेणियों के तहत हुआ है । दिनांक 11.11.97 की सीमाशुल्क अधिसूचना स. 84/1997 के तहत पर्याप्त मात्रा में शुल्क मुक्त आयात हुआ है । इस सीमा शुल्क अधिसूचना को लाभ विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे एशियाई विकास बैंक/विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना को दिया जाता है । ऐसे परियोजनाओं की तुलना में मांग अनियमित है । इससे यह स्पष्ट होता है कि 2004-05 में मांग में उद्योग में क्यों तेजी से वृद्धि प्रदर्शित हुई जो अपने सामान्य स्तर से नीचे आ गया । ऐसे संगठनों से वित्त पोषित कोई परियोजना नहीं थी । यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना हुए आयात को हटाना उपर्युक्त समझ सकती है ।

75. यह भी तर्क दिया गया है आयातों की मात्रा का आकलन जांच अवधि के अंदर लदान के लिए पहले ही सभी निविदाओं में दर्ज आयातों तथा भारत पहुँचे आयात की मात्रा को लेकर किया जाए । इसके अलावा, सभी निविदाओं में आयातों की मात्रा जिसके लिए जांच अवधि में लदान नहीं किया गया था लेकिन जांच अवधि के बाद आपूर्ति की गई है, सभी निविदाओं में दर्ज आयातों की मात्रा जिसके लिए लदान नहीं किया गया था लेकिन नियत समय में आपूर्ति कर दी जायेगी, सभी निविदाओं में दर्ज आयातों की मात्रा जिसके लिए आदेश को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन चीन के उत्पादक द्वारा पहले ही कम कीमत लगाई गई है तथा समान प्राप्त करने की संभावना है, सभी निविदाओं में दर्ज आयातों की मात्रा जिसके लिए अभी तक आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया है है और बोली लगाने वाले के साथ कीमत पर बातचीत चल रही है ।

76. यह भी तर्क दिया गया है कि निर्यात कीमत का परिकलन जांच अवधि के दौरान आयातों की वास्तविक मात्रा और वैसे प्रेषित माल की कीमत जिसके लिए जांच अवधि के दौरान अनुबंध पूरा कर लिया गया है तथा वैसे अनुबंध को भी जिसके लिए चीन के निर्यातक ने अपने कोटा की पेशकश की है, को लेने के बाद करना चाहिए ।

77. यह तर्क दिया गया है कि डीआई पाईप्स का बाजार कीमत और सुपुर्दगी अनुसूची के रूप में विचित्र है । निविदा बातचीत आदेश देने की तारीख और अंतिम सुपुर्दगी के समय में काफी अंतर होता है । घरेलू उद्योग ने पहले ही दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट होता है कि आदेश की तारीख और अंतिम सुपुर्दगी के प्ररूपी समय बिलम्ब 6 से 12 महीने के बीच है । इसलिए इस तथ्य का कि जांच अवधि के दौरान वास्तविक आयात में पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में आंशिक कमी हो सकती है, का पर्याप्त महत्व नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेज साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जांच अवधि के दौरान चीनी वस्तुओं के लिए तथा जांच अवधि के बाद आपूर्ति के काफी आदेश दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी को क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों पर दृष्टिकोण अवश्य लेना चाहिए। जांच अवधि के दौरान चीनी पाइपों के लिए दिए गए काफी आदेशों की वास्तविकता पर्याप्त संभावित आयातों तथा क्षति के भय का भी संकेतक है।

78. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने चीन के निर्यातकों से अनेक अनुबंध खो दिया है। अनेक मामलों में, चीनी उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमत भारतीय उत्पादकों द्वारा पेश कीमतों से कम थी। इसके बाद, ऐसे कुछ मामलों में इन आदेशों को प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं को कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा कीमत कम करने बावजूद, याचिकाकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के आदेश नहीं दिए गए हैं और यह समझा जाता है कि या तो चीनी उत्पादकों ने पहले ही कीमत कम कर दी है अथवा उनके साथ बातचीत जारी है। याचिकाकर्ता को भय है कि वे इनमें से कुछ बिक्रियों को खो सकते हैं।

79. ईसीएल के वैश्विक न्यासी प्राप्ति (जीडीआर) के लिए यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान जांच जांचाधीन उत्पाद तक सीमित है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि क्षति निर्धारण अनुबंध-11 के तहत पूरे घरेलू उद्योग के लिए न कि घरेलू उद्योग के घटकों में से किसी एक के लिए है। उन्होंने दावा किया कि याचिका जो पूरे घरेलू उद्योग के लिए दायर की गई थी तथा जीडीआर. एवरमेंटस केवल ईसीएल से संबंधित था और वह भी पूरी कंपनी के लिए न कि जांचाधीन उत्पाद लिए। इसलिए, घरेलू उद्योग के अनुसार जिंगसिंग प्राधिकारी को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहा था क्योंकि इसने अतुलनीय की तुलना करने का प्रयास किया। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया कि जीडीआर पेशकश दस्तावेज में दिए गए विवरण ईसीएल के समग्र प्रचालन के लिए था न कि सिर्फ जांचाधीन उत्पाद के लिए। जीडीआर पेशकश दस्तावेज सार पर जिंगसिंग का विश्वास भी भ्रमक है क्योंकि स्वयं जीडीआर पेशकश दस्तावेज अस्पष्ट रूप में 31 मार्च 2005, से पहले की अवधि की सूचना देता है न कि जांच अवधि की जीडीआर पेशकश दस्तावेज वर्तमान जांच के लिए चुनी गई जांच अवधि में जिंगसिंग द्वारा आयात मात्रा अथवा मूल्य अथवा आपूर्ति किए गए सम्बद्ध वस्तुओं के संबंध में कोई विवरण उद्धरण दिया गया है अथवा उल्लेख किया गया है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि एक्स डीआईपीएल के विषय में उसमें निहित विवरण को जांच अवधि नहीं माना जा सकता। यह व्यक्त्य कि ईसीएल के अनुभव को प्रतियोगी द्वारा आसानी से दोहराया नहीं जा सकता है। क्षति के संबंध में दोहराया नहीं जा सकता है, क्षति के संबंध में नहीं बल्कि उत्पादकों का भारत में प्रचालन शुरू करने के संबंध में दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी को और अनुचित प्रतिस्पर्धा सामना करने के दृष्टिकोण का संकेत नहीं है।

कारणात्मक संबंध

80. जांच अवधि के दौरान चीनी वस्तुओं के लिए काफी आदेश दिए गए हैं तथा जांच अवधि के बाद आपूर्ति के लिए आदेश दिए गए हैं, जो काफी संभावित आयात तथा क्षति के भय का भी सूचक है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि उनके उद्योग का मामला लुब्रीजोल (भारत) प्रा.लि., बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामलों में माननीय सेस्टेट के निर्णय जिसका संबंधित सार नीचे फिर से दिया गया है, से पूरी तरह समर्थित है।

* निविदा, जिसे आईओसी द्वारा प्रारंभ किया गया था, को जांच अवधि के दौरान 19.7.2001 को खोला गया। निर्यातक द्वारा संबद्ध उत्पादों के 5200 मी. टन की खरीदारी के लिए उद्धृत निर्यात कीमत, एन आईपी तथा घरेलू उद्योग द्वारा पेश कीमत से बहुत कम थी। चूंकि निविदा को जांच अवधि के दौरान खोला गया था। जिसमें पाटित कीमतें, जिस पर निर्यातक समानों को देने के लिए वचनबद्ध है, से प्रकट होता है कि घरेलू उद्योग को केवल अनुबंध टूटने के कारण ही क्षति नहीं हुई थी बल्कि वास्तविक क्षति का भी खतरा उत्पन्न हुआ जिसे नियमावली के अनुबंध 11 के प्रारंभिक भाग में यथा परिभाषित क्षति के रूप में विचार किया जाना है। चूंकि ऐसी क्षति का खतरा वास्तविक हो गया, निर्यातकों, द्वारा निविदा में क्षति रहित कीमत से नीचे फर्म की पेशकश को दृष्टिकोण से, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में अन्य सम्बद्ध घटकों के साथ अनुच्छेद च (6) (iii) के पहलू पर भी विचार किया।

81. जांच अवधि के दौरान भारतीय बाजार में 26000 मी. टन से ज्यादा चीनी पाइपों की आपूर्ति की पर्याप्त पेशकश की गई थी, जो अंततः उनके पास पराकाष्ठा पर थी।

82. क्षति जांच की पूरी अवधि के दौरान चीन का भारत में कुल आयात का हिस्सा 100% था। यह चीनी निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में आधार बनाने के लिए अपनाई जा रही आक्रमक कीमत नीति का सूचक है। शुल्क मुक्त आयातों को शामिल करने अथवा छोड़ने पर प्रवृत्ति समान है।

83. कुल मांग और घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन के आयात हिस्से में भी वृद्धि हुई है। कुल घरेलू मांग की तुलना में पाटित आयातों पर भुगतान किए गए शुल्क का हिस्सा भी बढ़ा है।

84. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कुल उत्पादन की तुलना में चीन से आयात पर अदा किए गए शुल्क का अनुपात भी बढ़ा है।

85. जहां वर्ष 2002-03 की तुलना में जांच अवधि के दौरान प्रति मी टन बिक्री बढ़ा है, प्रति मी. टन लागत में काफी ज्यादा है जिससे संकेत मिलता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत को समाप्त कर दिया गया है।

86. जहाँ घरेलू उद्योग की लागत एवं परिमाणी कीमत में बढ़ोत्तरी हुई, आयातों के पहुँच मूल्य में गिरावट प्रदर्शित हुई है।

87. जांच अवधि के दौरान काफी कीमत कटौती तथा कीमत हास हुआ है।

88. बिक्री मूल्य में परम पूर्ण रूप में वर्ष 2004-05 में वृद्धि हुई है तथा उसके बाद जांच अवधि में कमी आई है।

89. जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है।

90. जंहा उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है, इस वृद्धि से उद्योग के बढ़ते बाजार में जहां पाटित आयातों के परिणामस्वरूप बिक्री मूल्य भी कम हो रहे हैं, उद्योग में अपना बाजार हिस्से को खोने के प्रसंग में भी देखा जाना है।

91. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में काफी कमी आई है। वर्ष 2002-03 के आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ एक तिहाई तक घट गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन के आयात से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता गंभीर प्रकार से प्रभावित हुई है, जो वास्तविक क्षति का एक प्रमुख सूचक है।
92. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) में भी लगभग 1/5 भाग तक की सशक्त कमी प्रदर्शित होता है।
93. क्षति जांच अवधि में घरेलू उद्योग की औसत सम्पत्ति सूची में पूर्ण रूप में तथा दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा नकद प्रवाह की स्थिति में भी ह्रास हुआ है, जिससे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
94. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार, पर्याप्त पाटन मार्जिन हुआ है।
95. दूसरे कारकों जैसे वृद्धि और पूंजी जुटाने की क्षमता से भी प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
96. घरेलू उद्योग ने अनेक दस्तावेज पेश किये हैं जिससे संकेत मिलता है कि जांच अवधि के दौरान और जांच अवधि के पूर्व की अवधि में अनुबंध खत्म होने की अनेक घटनाएँ हुई हैं। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को एल एंड टी और सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्किटिंग लि. के माध्यम से केरला वाटर अथॉरिटी (के डब्ल्यू ए) को किए जाने वाले 26238 मीटन आपूर्ति का विशाल अनुबंध खत्म हो गया। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजीय साक्ष्य के अनुसार यह अनुबंध चीनी निर्यातकों द्वारा केवल कम कीमत पेश करने के कारण नष्ट हुआ। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि चीनी निर्यातकों को पर्याप्त मात्रा में अनुबंध खोने के अलावा वे आगे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) के साथ दर अनुबंध भी खत्म हो गया। चीनी निर्यातकों के साथ भी (जे वी गोकल एंड कंपनी के माध्यम से) खत्म हो गया।
97. काफी अनुबंध के नष्ट होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को दूसरे अनुबंध के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे और ज्यादा अनुबंध नहीं खोते हैं यद्यपि इससे उद्योग को पर्याप्त घाटा होता है, अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
98. चीन के निर्यातक द्वारा उठाए गए इस तर्क पर कि घरेलू उद्योग आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित हो रहा है, के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि जे एस एल की बिक्री को जोड़ने के बाद भी, पूरे घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से बिक्री में कमी हुई है। इसलिए घरेलू उद्योग की क्षति को आंतरिक प्रतिस्पर्धा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ निविदाओं के संबंध में घरेलू उद्योग ने दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जिससे प्रदर्शित होता है कि जांच अवधि के दौरान एक्स डीआईपी एल द्वारा अथवा उसकी ओर से पर्याप्त पेशकश की गई थी। इन दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि निःसंदेह घरेलू उद्योग को चीनी कीमतों के समतुल्य रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

च. 2. एक्सडीआईपीएल के तर्क

क्षति के संबंध में तर्क

99. घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में कि एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजनाओं के लिए सभी आयातों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे दुर्लभ हैं और उनकी मांग अनियमित है। इस संबंध में यह कहा गया है कि यह दावा जीडीआर और एफसीसी बी पेशकश दस्तावेज के वक्तव्य के विपरित है जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं द्वारा शुरू की गई अनेक अवसंरचना विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप मांग अथवा कंपनी के डीआई पाइप उत्पादों में वृद्धि हुई है। यह भी तर्क दिया गया है यदि याचिकाकर्ता यह मांग कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए आयातों को क्षति विश्लेषण के लिए हटाया जाए, इसका यह भी अर्थ है कि वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए पाइपों की आपूर्ति से उन्हें क्षति नहीं हो रही है। इसके अलावा जैसा कि उपर्युक्त तर्कों से संकेत मिलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पोषित परियोजनाओं के निर्यातों से भी घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

100. इसीएल ने वैश्विक न्यासी प्राप्ति (जीडीआर) और विदेशी निवेशकों को प्रदान की गई साथ में जीडीआर पेशकश दस्तावेज जारी करने का प्रकटन नहीं किया है। यह क्षति के आरोप की जड़ में वास्तविक तथ्य है और इसीएल ने डीजीएडी से यह महत्वपूर्ण दस्तावेज जानबूझकर छुपाया क्योंकि इससे निःसंदेह यह स्थापित होता है कि इसीएल को जांच अवधि के दौरान सामान्यतः चीन से और विशेषकर जिंगसिंग से किसी प्रकार की क्षति हो रही थी।

101. यह उल्लेख किया गया है कि जीडीआर दस्तावेज में अनेक वक्तव्य दिए गए हैं जबकि इसीएल ने बार-बार यह उल्लेख किया है कि वह बाजार में अग्रणी है और उसे घरेलू अथवा विदेशी किसी स्रोत से कोई खतरा नहीं है।

102. इसीएल ने विशेष रूप से जिंगसिंग का उल्लेख किया है और अपने निवेशक को आश्वस्त किया है कि भारत में जिंगसिंग के आयात इसीएल के बिक्रियों पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने में समर्थ नहीं है। इसका सार नीचे दिया गया है :-

➤ घरेलू बाजार के संबंध में, जिंगसिंग ने 31 मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में लगभग 10,000 टन डीआई पाइप्स की आपूर्ति की लेकिन उसने अभी तक भारतीय बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला है।

➤ कंपनी का यह विश्वास है कि इसके प्रबंधन के व्यापक अनुभव और भारत में स्पर्ण पाइप के विनिर्माताओं के रूप में 45 वर्ष के इतिहास को प्रतिस्पर्द्धी अथवा घरेलू बाजार में नए आगुंतक द्वारा आसानी से नहीं दोहराया जा सकता है।

103. इसीएल के अपने व्यापक पूंजी खर्च को वित्त पोषित करने के लिए इश्यू जीडीआर को जारी करके 38.32 मि. अमरीकी डॉलर जुटाने को दृढ़ था। तथापि इसने 40 मि. अमरीकी डॉलर जुटाया। यहां इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या कोई कंपनी जो घाटा में है, किसी निवेशक को इसमें निवेश करने में तथा ऐसे निवेश से 40 मि. अमरीकी डॉलर जुटाने का विश्वास दिला सकती है। यह भी खेदजनक है कि अपने जीडीआर निर्गम के

जरिए 40 मि. अमरीकी डॉलर जुटाने के बाद, ईसीएल ने याचिका में यह आरोप लगाता है कि वह पूंजी जुटाने में असमर्थ है।

104. यह उल्लेख किया गया है कि याचिका की बिक्री कम होने का आंकड़ा अविश्वसनीय है। जिगसिंग के आयात के कारण को याचिकाकर्ता के लाभ में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है तथा यह पूर्णतः कच्ची सामग्री की कीमत में क्षणप्रभ वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जीडीआर पेशकश दस्तावेज यह बताता है कि कंपनी का डीबीडीआई टीएम (ह्रास के पहले लाभ, ब्याज और करारोपण मार्जिन) 31 मार्च, 2005 2004 और 2003 के लिए क्रमशः 18.3%, 20.0% और 25.7% था। यह आगे उल्लेख करता है कि मुख्यतः कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण वित्तीय वर्ष 2003 से 2005 की अवधि के दौरान पीबीडी आईटीएम में कमी हुई है जो कि डीआई पाइप उत्पादन से अलग समूह द्वारा प्राप्त बड़ी मार्जिन को प्रभावशाली बनाया है।

105. कच्ची सामग्री की लागत में इतनी वृद्धि हुई कि यह पिछले वर्ष की तुलना में 2004-05 में 50% बढ़ गई। कोकिंग कोयला एक प्रमुख कच्ची सामग्री है तथा गूनयेला कठोर कोकिंग कोयले की कीमत 46 अमरीकी डॉलर से बढ़कर 126 अमरीकी डॉलर हो गई जो 173% की वृद्धि की है। इसी प्रकार लौह अयस्क की कीमत में 2003 में 18 डॉलर से बढ़कर 2005 में 36 डॉलर हो गई। जून 2005 को समाप्त तीन महीनों में इसकी कीमत 48 डॉलर थी। कंपनी ने एस एम स्क्रेप और विद्युत की कीमतों में वृद्धि का भी अनुभव किया। कंपनी स्वयं यह मानती है कि गिरावट की यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से कच्ची सामग्रियों की लागत में वृद्धि के कारण हुई है।

106. यह उल्लेख किया गया है कि ईसीएल के रिकार्ड से यह प्रदर्शित होता है कि ईसीएल ने कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के प्रत्युत्तर में कीमत में वृद्धि की तथापि डीआई पाइप्स की कीमत में यह वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसे 2004-05 और 2003-04 के वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है जिसे नीचे फिर से दिया गया है :-

वार्षिक रिपोर्ट 2004-05 के पृष्ठ संख्या 14 पर

" इस वर्ष आयातित कोक की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ जिसका लाभ मार्जिन पर व्यापक प्रभाव था।

" बिक्री में वृद्धि के अलावा कोक की कीमत में असामान्य वृद्धि को आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति के लिए बिक्री मूल्य में वृद्धि के कारण कारोबार बढ़ा है।

2003-04 के वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 15 पर

" आपकी कंपनी ने डीआई पाइप्स की कीमत में वृद्धि की है लेकिन यह वृद्धि आयातित कोक की कीमत में वृद्धि को निष्प्रभावित कर देती है। जब तक कृत्रिम वृद्धि कम होकर वास्तविक स्तर तक नहीं आ जाती है। कीमत में तुरंत कमी होने की आशा ने निराश कर दिया है और इस संदर्भ में वर्तमान में कोई संकेत नहीं है।

जीडीआर पेशकश दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 69 पर

वर्ष 2003 से 2005 के वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान पीबीडी आईटीएम में कमी हुई है। गिरावट की यह प्रवृत्ति मुख्यतः कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण है, जिसने डीआई पाइप उत्पादन से अलग समूह द्वारा प्राप्त बड़े मार्जिन को प्रभावशाली बनाया है चूँकि कच्ची सामग्री से संबद्ध लागत में वृद्धि को समूह में तैयार उत्पादों में संगत वृद्धि द्वारा नहीं दर्शाया गया है, उनका समूह की लाभप्रदता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

107. क्षमताओं की वृद्धि के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि ईसीएल ने 2005 में 5 संयंत्रों को शुरू किया तथा विस्तार इतना व्यापक था कि ईसीएल को मार्च 2006-07 को समाप्त वर्ष में प्रति वर्ष 3 बिलियन और 100 मिलियन का पूंजीगत खर्च किया गया। यह भी कोटुहल उत्पन्न करने वाला है कि याचिकाकर्ताओं ने अधिकांश उत्पन्न करने वाला तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं ने अधिकांश अपने संयंत्र जांच अवधि के दौरान संस्थापित किए। केवल इसी लक्ष्य से यह स्थापित होता है कि चीन से आयातों से याचिकाकर्ताओं की व्यापक वृद्धि पर किसी प्रकार से रूकावट नहीं हुई है अथवा याचिकाकर्ताओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है।

108. वर्ष 2002-03 से 2004-05 में घरेलू उद्योग के डीआई पाइप्स के उत्पादन में सतत रूप से वृद्धि हुई है। उत्पादन में कथित कोई कमी लघु भट्टी के बंद होने के लिए उत्तरदायी है।

109. स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा से यह सिद्ध होता है कि चीन से हुए आयात में पूर्णतया तथा उत्पादन और खपत के संबंध में भी दोनों रूप में कमी हुई है। बाजार हिस्से में आयात का योगदान नगण्य है क्योंकि कुल बाजार हिस्से में इसका योगदान केवल 2.56% है। आयातों का बाजार हिस्सा घटकर उत्पादन का 2.56% हो गया है, इसी समय जिंदल का उत्पादन 30% तक बढ़ गया है, और याचिकाकर्ता का बाजार हिस्सा 92% से घटकर 67% हो गया इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में कमी जिंदल के बाजार में प्रवेश के साथ शुरू हुई है। चीनी आयातों के बाजार हिस्से में कमी तथा इसी समय जिंदल के बाजार में हिस्से के वृद्धि से यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ताओं के कथित किसी प्रकार की क्षति के लिए आयात उत्तरदायी नहीं है।

अनुबंध समाप्त होना

110. इलेक्ट्रो स्टील : केरल वाटर एथोरिटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध समाप्त होने के रूप में झूठा संकेत दिया है। जहाँ इलेक्ट्रोस्टील ने इस तथ्य पर कि एक्स डीआईपीएल ने केडब्लूए परियोजना के लिए एल एंडी टी और सुभाष से 25,000 मी. टन डीआई पाइप्स की आपूर्ति करने का एक आदेश प्राप्त किया, के संबंध में काफी उल्लेख किया है, वह यह उल्लेख करना भूल गया कि उसने भी उसी परियोजना के लिए 30,000 मी. टन डीआई पाइप्स की आपूर्ति की। उनकी निविदकों भी जांच अवधि के दौरान खोला गया था, इसलिए वे यह भी जानते थे कि वे आने वाले वर्ष में वे के डब्लू ए को 30,000 मी. टन डीआई पाइप्स की आपूर्ति करेंगे। इस परिदृश्य में कैसे अनुबंध टूटा हुआ है।

111. इसके अलावा कोई दावा कि इलेक्ट्रो स्टील को एक्स डी आई पी एल को 30,000 मी. टन की आपूर्ति के लिए अपनी कीमत कम करनी पड़ी, गलत है क्योंकि एक्स डी आई पी एल ने "स्थानीय प्रतिस्पर्द्धी बोली लगाने वाले" निविदाओं के लिए ठेकेदारों को कीमत की बोली भी नहीं प्रस्तुत की। इस प्रकार इलेक्ट्रो स्टील यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एक्स डी आई पीएल प्रतियोगिता में भी नहीं है इन पाइपों की बोली लगाई तथा आपूर्ति की।

112. एल एंड टी और सुभाष का एक्स डीआईपी एल से पाइन खरीदने का एक मात्र कारण उनका तेजी से सुपुर्दगी समय (इलेक्ट्रो स्टील के 18 माह की तुलना में 9 माह) है तथा एक्सडीआईपीएल ने अनुबंध में कीमत वृद्धि उपबंध का अभाव होना है। इस प्रकार एक्सडीआईपीएल को अनुबंध मिला क्योंकि इलेक्ट्रोस्टील समय पर पाइप की आपूर्ति नहीं कर सकता है जोकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित सभी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण जरूरत है।

113. समाप्त अनुबंध के मुद्दे पर, एक्स डीआईपीएल यह बताना चाहेगा कि इलेक्ट्रो स्टील ओर लोको ने जांच अवधि के दौरान या तो खोले गए अथवा दिए गए दूसरे संविदाओं से संबंधित सूचना को जान बुझकर छुपाया, जो इलेक्ट्रोस्टील और लोको को दिया गया और जिससे सिद्ध होता है। उनके अनुबंध समाप्त होने के दावे कोई जान नहं है। ऐसी निविदाओं की सूची नीचे उपलब्ध कराई गई है।

- 1 पीआरईडी, जी निर्मल प्रोजेक्टस-बिजापुर जिला (मात्रा- 5318 मी. टन)
- 2 केरल वाटर अथोरिटी (मात्रा-3122 मी. टन)
- 3 मंगलौर मुनिसिपल कारपोरेशन (मात्रा- 1137 मी. टन)
- 4 बी डब्लू, एसएसबी, 7 सीएमसी और 4 टीएमसी प्रोजेक्ट(मात्रा- 9000 मी. टन)
- 5 केरल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज (मात्रा- 30410 मी. टन)
- 6 बी डब्लू एसएसबी 7 सीएमसी प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (मात्रा- 18589 मी. टन)
- 7 कर्नाटक लैंड आर्मी कार्पो, कोपाल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट (मात्रा- 4500 मी. टन)
- 8 राजस्थान बीकानेर प्रोजेक्ट (मात्रा- लगभग 35000 मी. टन)
- 9 कर्नाटक रूरल वाटर सप्लाई (मात्रा- 2500 मी. टन)
- 10 झारखंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनीटेशन, रांची (मात्रा- 2700 मी. टन)
- 11 पीएचईडी, पटना बिहार (मात्रा- 2300 मी. टन)
- 12 जी डब्लू एसएस बी, गुजरात (मात्रा- 7300 मी. टन)
- 13 जे एंड के इकोनोमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी जे एंड के(मात्रा- 4500 मी. टन)
- 14 पीएच ई डी, राजस्थान (मात्रा- 4500 मी. टन)

वर्तमान वास्तविक क्षति के लिए प्राचल के लिए संभावित आयात

114 याचिकाकर्ताओं ने लुब्रीजोल में निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि डीजीएडी को जांच अवधि के दौरान खोली गई संविदा को लेना चाहिए यद्यपि वे जांच अवधि बाद पाइपों की आपूर्ति के लिए था। इसका अर्थ यह है कि वैसे आयात जो जांच अवधि के 6 महीने बाद आयात किए गए थे पर विचार करना चाहिए जैसे कि वह जांच अवधि के दौरान किया गया था। यह पूर्वसर्ग पाटनरोधी संबंधी डब्लू टीओ करार के सिद्धान्तों के विरुद्ध गलत है तथा लुब्रीजोल निर्णय के गलत पठन के जरिए इस बिंदु पर फिर से नियम लिखने की आवश्यकता है।

कारणात्मक संबंध

115. किसी प्रकार का शुल्क लगाने के लिए यह अपेक्षित है कि आयात और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच स्पष्ट संबंध होना चाहिए तथा यह तथ्य निःसंदेह व्यापित होना चाहिए कि सिर्फ आयात से न कि किसी अन्य घटकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

116. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तिथि से यह प्रदर्शित होता है कि जांच अवधि के दौरान आयात में 2004-05 के स्तर से कमी हुई और इसका बाजार में हिस्सा मामूली 2.5% था । इसी अवधि में जिंदल के बाजार में हिस्सा में 30% की वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता का बाजार हिस्सा 92% से घटकर 67% हो गया ।

117. जांच अवधि के दौरान आयात में कमी आयात और याचिकाकर्ताओं को हुई किसी कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को अलग करता है ।

118. माननीय डीजीएडी को दिनांक 30 सितम्बर, 2005 अर्थात् जांच अवधि के बीच में जीडीआर पेशकश दस्तावेज में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए व्यक्तव्य को भी याद करना चाहिए कि जिगसिंग का अभी बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है । इस व्यक्तव्य से अपने आप यह सिद्ध होता है कि याचिका आधारहीन है तथा इसे सभी न्यायसंगत प्रतिस्पर्द्धा को विफल करने के दुर्भावपूर्ण इरादे से दायर किया गया है ।

119. डीजीएडी को यह नोट करना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं को क्षति के किसी मानदंडों पर क्षति नहीं हुई है । जीडीआर पेशकश दस्तावेज और दोनों कंपनियों में वार्षिक रिपोर्टों से यह स्थापित होता है कि उत्पादन मात्रा बिक्रियां, शुद्ध बिक्रियां, प्राप्ति, क्षमता विस्तार, नकद प्रवाह, मजदूरी, रोजगार, मालसूची, वृद्धि और उत्पादकता सभी में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है तथा आगे यह संकेत है कि कंपनियाँ प्रमुख रूप से विस्तार के लिए अग्रसर हैं ।

120. यदि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण वास्तव में वास्तविक क्षति हुई है यह पूंजी जुटाने तथा विस्तार के कारण हुई है तथापि, जैसाकि रिकार्ड बतलाता है कि इलेक्ट्रो स्टील और लोको दोनों निवेश और विस्तार के लिए जिस प्रकार की योजना बना रहे हैं वह क्षति होने के विरुद्ध है । इलेक्ट्रो स्टील ने न सिर्फ जीडीआर निर्गम के जरिए 40 मिलियन सफलतापूर्वक जुटाये, यह अब दूसरे जीडीआर इश्यू3/ एफ़सीसीबी की योजना बना रहा है जिसमें यह अपने कोयला खान तथा सिंटर संयंत्र के अधिग्रहण की पेशकश कर रहा है ।

121. माननीय डीजीएडी को क्षति विश्लेषण करने में अन्य घटकों पर भी विचार करना चाहिए :-

(क) एक्स डी आईपीएल डीआई पाइप उत्पादन प्रौद्योगिकी के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित 33 पेटेंटों का धारक है जो अपरिमित स्तर का उत्पादन करते हैं जो भारत में किसी भी उत्पादकों के सदृश नहीं हो सकता है । प्रतिवादी का प्रौद्योगिकी गुणवत्ता युक्त डीआई पाइप

का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में तथा कच्ची सामग्री के विभिन्न श्रेणियों का उपयोग करने में भी समर्थ बनाता है। भारत में घरेलू उद्योग को तुलनीय प्रौद्योगिकी तथा प्राप्त करने की विधि का अभाव है और इसलिए उनमें उत्पादन प्रक्रियाओं में स्वभाविक कठिनाइयाँ हैं।

(ख) इलेक्ट्रो स्टील ने भी एक्सडी आई पीएल के उत्कृष्ट मूल्य के प्रौद्योगिकी को माना है और विगत में इसे एक्सडीआईपीएल से खरीदा भी है। विशेषकर 1999 में, एक्सडीआईपीएल और इलेक्ट्रो स्टील एक पूर्ण डीआई फिटिंग संयंत्र की आपूर्ति और संस्थापना के लिए एक करार किया। इसके बाद एक्सडीआई पीएल ने प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की और एक्सडी आई पीएल से प्रक्रिया जाना एवं उससे लाभान्वित हाकर अब डीजीएडी के पास निराधार याचिका दायर कर अब उसे बाजार से हटाने का प्रयास कर रहा है।

(ग) याचिकाकर्ताओं को 1998 से उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगे होने के कारण कोक की ऊँची कीमत का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं को कोकिंग कोयले की जरूरत मुख्यतः चीन और आस्ट्रेलिया के आयातों से पूरा होता है। जैसा कि डीजीएडी जानते हैं, अगस्त 1998 से चीन से मेट कोक के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है, जिसे जनवरी, 2004 में निर्णायक समीक्षा के दौरान बढ़ा दिया गया था। इसलिए इस समय शुल्क लगा हुआ है और इस पर जनवरी, 2008 में समीक्षा की जायेगी। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लगाने के फलस्वरूप मेट कोक जोकि डीआई पाइप्स के विनिर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संघटक है की कीमत में वृद्धि हुई है और इस प्रकार दूसरा कच्ची सामग्री की लागत बढ़ाने में योगदान रहा।

(घ) इसके अलावा 200 से डीआई पाइप्स को मूलभूत सीमाशुल्क जो उस समय 35% था, में सतत कमी हो रही है, मूलभूत सीमाशुल्क कम होकर 2004 में 20% तथा उसके बाद 2005 में 15% हो गया। वर्तमान में यह शुल्क 12.5% है।

(ङ) सीमाशुल्क का कम होना इस तथ्य का भी संकेतक है कि भारत सरकार भारत में पानी आपूर्ति की समस्या के लिए डीआई पाइप्स के महत्व को जरूरी समझती है और उसने वर्षों के दौरान सीमा शुल्क को लगातार कम करके आयातों को सुकर बनाना आवश्यक समझा है।

122. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी आंकड़े और सूचना से वास्तविक क्षति अथवा घर से आयोग को आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध प्रदर्शित नहीं होता है और यह भी स्थापित होता है कि याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी करार और नियमावली के तहत अपना दायित्व पूरा नहीं किया है।

123. उपरोक्त के दृष्टिकोण से डीजीएडी को क्षति के किसी परिणाम अथवा कारणात्मक संबंध को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसके अलावा डीजीएडी को जीडीआर पेशकश दस्तावेज जिसमें ईसीएल का निवेशक के समक्ष दावा की गई वास्तविक स्थिति का उल्लेख है,

जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को छुपाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। पेशकश दस्तावेज के सार को प्रकट नहीं करना तथा अपर्याप्त एवं निराधार सूचना के आधार पर क्षति का आरोप लगाना गलत निरूपण है और माननीय प्राधिकारी को इस कार्रवाई पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

124. यह तर्क दिया गया है कि ज़िंदल सा. लि. ने कुछ गोपनीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, यह सूचना जांच के उद्देश्य से अस्वीकार्य है, क्योंकि इसे पाटनरोधी नियमावली का स्पष्टतः उल्लंघन करके प्रस्तुत किया गया है क्योंकि नियम 7 के अनुसार सभी सूचना को उसके अगोपनीय विवरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। इस मामले में ज़िंदल ने अगोपनीय विवरण को देने से मना कर दिया। इसलिए आंकड़े पूरी तरह से अस्वीकार करने लायक हैं। तथापि यह तर्क दिया गया है कि एक्सडीआईपीएल एक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है जिससे स्थापित होता है कि ज़िंदल सां. पर अनावश्यक व्यय का विस्तार था और पूरी जांच अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई। इस संबंध में सीएन-बीसी-टीवी 18 कंपनी के उपाध्यक्ष श्री इन्द्रेक्ष बत्रा का साक्षात्कार और 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट को भी उद्धृत किया गया है जिसमें उल्लेख है कि 2005-06 कंपनी का सबसे लाभदायक वर्षों में से एक रहा है।

च. 3. मै. लार्सन एंड टूब्रो ल. द्वारा दिए गए तर्क

125 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए दिनांक 11.11.97 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 84/1997 के तहत शुल्क मुक्त आयात किए जाते हैं और इसलिए इसे क्षति विश्लेषण के लिए हटा देना चाहिए, आधारहीन और किसी गुण अथवा कानूनी आधार पर संचित है इससे यह भी अर्थ है कि वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए पाइपों की आपूर्ति से उन्हें क्षति नहीं हो रही है।

126. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ज़िंदल सां. का डीआई पाइप्स के क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले इलेक्ट्रो स्टील और लांसों, डीआई पाइपों के केवल दो उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता थे। वास्तव में 2004 तक जब मांग में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रो स्टील और लांसों पूरा नहीं कर सका, ठेकेदारों को जल परियोजनाओं की आपूर्ति के लिए पाइपों की आपूर्ति करनी पड़ी। इलेक्ट्रो स्टील और लांसों भारत में सभी जल परियोजनाओं का एक मात्र आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत में डीआई पाइपों की मांग में उछाल को देखकर ही ज़िंदल सां. ने डीआई पाइप्स के उत्पादन में प्रवेश किया और जांच अवधि के दौरान अपना उत्पादन शुरू किया। जांच अवधि वह अवधि है जिसमें ज़िंदल सां. ने न सिर्फ अपना उत्पादन प्रचालन शुरू किया बल्कि भारत में डीआई पाइपों की काफी मात्रा में बिक्री की और उत्पादन के 9 महीनों के अंदर घरेलू बाजार के हिस्सा में काफी बड़ा भाग अर्थात् 30% (लगभग) प्राप्त करने में समर्थ रहा।

127. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ज़िंदल सां. के आने के पहले इलेक्ट्रोस्टील का भारत में डीआई पाइप्स के विनिर्माण एवं आपूर्ति में एकाधिकार रहा है। इसे कुछ वर्षों में थोड़ा प्रतिस्पर्द्धा लोको कलहस्ती से था जो बाजार में 2001 में आया। डीआई पाइप बाजार में लोको के आने से इलेक्ट्रोस्टील के लाभ पर 25% की जोरदार गिरावट हुई जिससे स्पष्टतः

प्रदर्शित होता है कि कैसे इलेक्ट्रोस्टील अपने एकाधिकार स्थिति का दुरुपयोग कर रहा था। अपनी एकाधिकार स्थिति को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रो स्टील लोको का मुख्य शेयर धारक बन गया और आज इसका कंपनी पर 48% तक का नियंत्रण है। आज लोको इलेक्ट्रो स्टील की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है। तथापि जिंदल के आने से घरेलू उद्योग के हिस्से में तेजी से कमी हुई और याचिकाकर्ता एवं जिंदल सां के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा फिर से शुरू हो गई। यह स्पष्ट संकेत है कि दो पक्षों के बीच से प्रतिस्पर्धा से कीमते कम हुई और घरेलू बाजार हिस्से में परिवर्तन हुआ। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में इतनी कमी का कारण प्रतिस्पर्द्धी कीमते हैं जिस पर जिंदल सां ने अपने सामानों की भारतीय बाजार के पेशकश की है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को अपने लाभ मार्जिन को अनुचित उच्च स्तर से कम के उचित स्तर पर लाना पड़ा।

128. घरेलू उद्योग द्वारा यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादी/ आयातक मै. लार्सन एवं टूब्रो लि. में इसीएल को आदेश देने के बदले जांचाधीन वस्तु की जरूरत को चीन से मंगाकर पूरा किया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसीएल और ए एवं टी के बीच डीआई पाइपों के मंगाने से संबंधित समझौता ज्ञापन किया गया था। उक्त समझौता ज्ञापन 1.10.2005 को किए गए थे। जिसमें इसीएल ने 5 केरल जल आपूर्ति के लिए एंड डी को डीआई पाइपों की आपूर्ति के लिए कीमत लगाई थी जिसके लिए एल एंड टी ने बोली लगाई थी। निविदा/उत्पाद जिसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जांच अवधि के लिए नहीं था और वर्तमान मामले के लिए अमूर्त है। उक्त निविदा को जांच अवधि के दौरान कभी भी नहीं खोला गया और इसलिए जांच अवधि के दौरान कथित संविदा समझौता ज्ञापन के लिए कोई आदेश देने की बात कभी नहीं उठी। उक्त संविदा को एल एंड टी को मई, 2006 के पहले जांच अवधि में काफी पहले दिया गया था। इसके अलावा जांच अवधि के दौरान जांचाधीन वस्तु का कोई आयात आयातक द्वारा नहीं किया गया है घरेलू उद्योग के दावा को गलत ठहराता है क्योंकि एल एंड टी अपने चीन के जांचाधीन वस्तु की जरूरत को घरेलू उद्योग की वस्तु से प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है।

129 जांच अवधि के दौरान आयात में काफी कमी हुई है, आयात मते तेजी से कमी होने के कारण भारतीय बाजार में नए भारतीय उत्पादक अर्थात् जिंदल सां लि. का आना था। घरेलू मांग जो घरेलू उद्योग से वस्तुओं की कम आपूर्ति के कारण पहले आपूर्ति दबाव का सामना कर रहा था, को चीन से वस्तुओं का आयात करना पड़ता था लेकिन भारतीय बाजार में नए उत्पादक के आने से आयात में काफी कमी हो गई। न सिर्फ आयातों में काफी कमी हुई बल्कि जिंदल सां जो अपेक्षाकृत भारतीय बाजार में नए हैं, घरेलू उद्योग और आयात का काफी बाजार हिस्सा ले लिया है।

130. क्षति अवधि के दौरान सभी मानदंड जैसे क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियां और स्टॉक में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। घरेलू उद्योग की बिक्रियां जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कमी आई है का कारण चीन से आयात को नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि चीन से आयात में भी कमी आई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में कमी भारतीय बाजार में नए उत्पादक के आने से हुई है।

131 उपरोक्त की दृष्टि से चीन जनवादी गणराज्य से डीआई पाइपों के आयात के कारण इन मानकों पर घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है ।

132 यह प्रस्तुत किया गया है कि न सिर्फ घरेलू उद्योग की बिक्रियों में काफी वृद्धि हुई है बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी काफी बढ़ी है जो घरेलू उद्योग को क्षति दिलवाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई कीमत दबाव के सिद्धान्त को स्पष्टतः नकारता है । घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि उसकी बिक्री कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कमी हुई है, तथापि यह देखा जा सकता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में काफी जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में भी कमी हुई है । आगे यह भी नोट करने योग्य है कि चीन से अधिकतम आयात होने के समय घरेलू उद्योग की कीमत भी उच्चतम था जिससे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि आयात और घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में कोई सह संबंध नहीं है ।

133. घरेलू उद्योग को सर्वाधिक लाभ 2004-05 में हुआ जब आयात उच्चतम स्तर पर था जिससे स्पष्टतः यह वास्वविकता स्थापित होती है कि चीन के आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

134. चीन से आयात के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी नहीं हुई है क्योंकि जांच अवधि के दौरान आयात में काफी कमी हुई है । इसलिए आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है ।

135. यह हमारे संदेह से परे है कि आयातों में इतनी तीव्र गिरावट से घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो सकती है । पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान आयातों में 60% की गिरावट आई । इन वर्षों में सीमाशुल्क में कमी के बावजूद आयातों के पहुंच मूल्यों में वृद्धि होती रही है । पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान पहुंच मूल्य में 2% की कमी के बावजूद आयातों में वृद्धि होने के बजाए 60% की कमी भी आई है ।

136. मै. जिंदल सॉ लि. ने डक्टाइजल लोहे के पाइपों के उत्पादन के लिए बाजार को लाभकारी पाया क्योंकि घरेलू उद्योग मै. जिंदल सॉ लि. के प्रवेश से पूर्व भारी मुनाफा कमा रहा था । यदि जिंदल सॉ लि. ने बाजार को चीन से आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार को लाभकारी नहीं पाया होता तो कंपनी ने डी आई पाइपों के उत्पादन में प्रवेश नहीं किया होता ।

137. इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा धारित बाजार हिस्से में गिरावट चीन से हुआ आयातों के कारण नहीं आई है अपितु, यह गिरावट भारतीय बाजार में अन्य उत्पादकों के प्रवेश और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा के कारण आई है । घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार में एकाधिकार था जिसे अन्य उत्पादक ने चुनौती दी है ।

138. घरेलू उद्योग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग अधिकतम कीमत प्राप्त करने में समर्थ था और उसने 2004-05 में अधिकतम बिक्री दर्ज की है जबकि आयात भी इसी अवधि के दौरान अधिकतम रहे हैं। अतः घरेलू उद्योग ने आयातों में कमी के साथ-साथ उनकी बिक्री कीमत में गिरावट के बजाए अधिकतम आयातों की मौजूदगी में बेहतर निष्पादन किया है।

139. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है जो भारतीय बाजार में अन्य उत्पादक के प्रवेश की वजह रही है।

140. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिंदल सॉ द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की जा रही है और घरेलू उद्योग जिंदल सॉ की कीमतों के अनुसार अपनी कीमतों की बेंच मार्क करने के लिए बाध्य हुआ है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है, जिंदल सॉ का बाजार बढ़ा है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है।

141. डी आई ने दावा किया है कि उसे किसी आधार के बिना चीन जन.गण. से निर्यातों के अनेक ठेके गंवाने पड़े हैं। यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप चीन से आयात हुए। भारतीय बाजार में एक नए उत्पादन अर्थात् जिंदल सॉ लि. के प्रवेश के साथ मांग और आपूर्ति का अंतर एक बार पट जाने के कारण चीन से होने वाले आयातों में भारी गिरावट आई जिससे चीन से हुए आयातों के हिस्से को कम किया अपितु घरेलू उद्योग के एक बड़े बाजार हिस्से को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया।

च. 4 प्राधिकारी द्वारा जांच

पाटित आयातों की मात्रा

142. डीसीआईएस के आयात संबंधी सौदेवार आंकड़ों में वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान डी आई पाइपों का आयात नहीं दर्शाया गया है। तथापि, जांच अवधि के दौरान आयातों के कुछ सौदों की सूचना दी गई है। आईबीआईएस के सौदेवार आंकड़ों में वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा जांच अवधि में आयात दर्शाए गए हैं। आयातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में भी पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए आयात दर्शाए गए हैं। यह प्रतीत होता है कि डीजीसीआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात के आंकड़ों में आयातों के सभी सौदे शामिल नहीं हैं और इसलिए आईबीआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आंकड़ों पर विश्लेषण हेतु भरोसा किया गया है।

संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा

(कुल आयातों का %)

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल 05- दिसंबर 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
संबद्ध देश से आयात (मी.ट.)	0	2867	13412	4644	6192
कुल आयात (मी.ट.)	0	2867	13412	4644	6192
% हिस्सा	0	100%	100%	100%	100%

143. आंकड़ों से यह पता चलता है कि संबद्ध वस्तु का आयात केवल संबद्ध देश से ही किया गया था और इसलिए संबद्ध देश से आयात कुल आयातों के 100% बनते हैं। वर्ष 2002-03 में आयात शून्य रहे थे। वर्ष 2003-04 में 2867 मी.टन के आयात हुए जो 2004-05 में बढ़कर 13,412 मी.टन हो गए और जांच अवधि में घटकर 6192 मी.टन (वार्षिक) हो गए। रुझान से यह पता चलता है कि आयातों में 2004-05 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच अवधि में गिरावट आई। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 2004-05 में आयातों में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में आयातों द्वारा पर्याप्त कटौती हुई है।

144. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि समूची क्षति जांच अवधि के दौरान आयात 2 विशिष्ट श्रेणियों में हुए हों। पर्याप्त मात्रा में आयात 11.11.1997 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 84/1997-सी.शु. के तहत शुल्कमुक्त हुए हैं। शुल्कमुक्त तथा शुल्क संदत्त आयातों का ब्यौरा निम्नानुसार है जिसे आईबीआईएस सौदेवार आंकड़ों से लिया गया है :-

वर्ष	शुल्क-संदत्त	शुल्क मुक्त	कुल मात्रा मी.टन में
2002-03	शून्य	शून्य	शून्य
2003-04	584	2283	2867
2004-05	6952	6460	13412
जांच अवधि	4644	शून्य	4644
जांच अवधि (वार्षिक)	6192	शून्य	6192

145. घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि उपर्युक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत शुल्कमुक्त आयात किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ए डी बी/विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा परियोजनाओं का विशेष रूप से वित्तपोषण किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए मांग अलग-अलग रही है जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उद्योग ने 2004-2005 में मांग में वृद्धि क्यों देखी जो उस समय उसके

सामान्य स्तर से भी कम हो गई जब एडीबी/विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किसी परियोजना का वित्तपोषण नहीं किया गया था। ऐसे आयातों के अनियमित और अलग-अलग स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क के भुगतान के बिना बिए गए आयातों को अलग करने पर विचार करना उचित समझा जाए।

146. अन्य हितपक्ष पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि "यदि याचिकाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्तपोषित परियोजना के लिए किए गए आयातों को क्षति विश्लेषण हेतु अलग रखने की मांग कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वह यह स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए प्राइमों की आपूर्ति से उन्हें क्षति नहीं हो रही है।"

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में आयात उक्त विशिष्ट अधिसूचना के अंतर्गत हुए थे जिसके तहत विशिष्ट आयातों को सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। यह भी देखा गया है कि वर्ष 2003-04 और 2004-05 में पर्याप्त मात्रा में आयात ऐसी परियोजनाओं के लिए किए गए थे जबकि 2002-03 के दौरान कोई आयात नहीं किया गया है जो कि क्षति जांच अवधि का आधार वर्ष है और न ही जांच अवधि के दौरान उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत कोई आयात किया गया है।

148. प्राधिकारी की राय यह है कि शुल्कमुक्त आयातों को अलग करके आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक आयातों का रुझान एक समान रहा है।

कुल मांग तथा घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन से आयातों का हिस्सा

(कुल मांग का प्रतिशत %)					
	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल 05- दिसं. 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
कुल मांग (मी.ट.)	152193	168187	203355	168933	225244
प्रवृत्ति	100	111	134	111	148
चीन का हिस्सा %	0.00%	1.70%	6.60%	2.75%	2.75%

149. आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 48% की वृद्धि हुई। वर्ष 2003-04 में संबद्ध वस्तु की मांग में हिस्सा 1.70%, 2004-05 में 6.60% तथा जांच अवधि में 2.75% रहा था। प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि संबद्ध देश का हिस्सा 2002-03 से 2004-05 तक बढ़ा है जब यह कुल मांग का 6.60% रहा था, लेकिन जांच अवधि में घटकर 2.75% हो गया था।

(घरेलू उत्पादन के अनुपात में)

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल 05- दिसं. 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
सभी घरेलू उत्पादकों का कुल उत्पादन (मी.ट.)	201976	218579	240549	222574	296765
चीन से आयात (मी.ट.)	0	2867	13412	4644	6192
घरेलू उत्पादन का अनुपात	0	1.31	5.6	2.1	2.1

150. आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में आयात वर्ष 2002-03 में 0%, 2003-04 में 1.21%, 2004-05 में 5.6% और जांच अवधि में 2.1% रहे थे। आधार वर्ष की तुलना में प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि यह 0% से बढ़कर 2004-5 में 5.6% हो गई लेकिन जांच अवधि में घटकर 2.1% रह गई।

घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है तथापि, इसी समय घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में भी वृद्धि हुई है। बिक्री लागत में यह वृद्धि बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से काफी अधिक है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभ में पर्याप्त घाटा हुआ है। निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रति मी.टन बिक्री कीमत में जांच अवधि के दौरान वर्ष 2002-2003 की तुलना में लगभग 34% की वृद्धि हुई है, इसी अवधि के दौरान प्रति मी.टन लागत में लगभग 54% की वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की लागत एवं परिणामी कीमत में वृद्धि हुई है तथापि आयातों के पहुंच मूल्य में अधोगामी प्रवृत्ति देखी गई है। इससे इस बात का स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत का ह्रास हुआ है।

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल 05- दिसं. 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
चीन से पहुंच मूल्य रु./इकाई	-	32841	30945	30171	30171
घरेलू बिक्री कीमत रु./इकाई	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	118	142	136	136
लागत/इकाई	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	115	146	154	154

कीमत कटौती

152. सहयोगी निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया था कि कीमत कटौती तथा पाटन मार्जिन की जांच ग्रेडवार की जानी चाहिए लेकिन विभिन्न ग्रेडों के निर्यातक के भार के अनुसार कीमतों की जांच करने पर यह पाया गया था कि अनुमानित जमा-घटा 1% का अंतर है। इसलिए प्राधिकारी ने सभी ग्रेडों के भारित औसत आयातों द्वारा कटौती की जांच की है।

153. घरेलू उद्योग की भारित निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित रिबेट, छूट तथा कमीशन और सर्वोत्तम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रिबेट दी गई है।

154. कीमत कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री प्राप्ति के साथ करके किया गया है। इस प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की संगणना 1% हैंडलिंग प्रभार तथा लागू मूल सीमाशुल्क को संबद्ध देश से आयात कीमतों के आईबीआईएस आंकड़ों में सूचित मूल्य में जोड़कर की गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से कीमत कटौती 2-10% के बीच रही है।

	कीमत कटौती
घरेलू बिक्री कीमत	***
पहुंच मूल्य	30171
कीमत कटौती	***
कटौती (%)	5.49%

155. घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित करने के लिए उदाहरण दिए हैं कि चीन के निर्यातकों द्वारा पाटित आयातों और कटौती के कारण उन्हें अपनी कीमतों को कम करना पड़ा था। इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कीमतों में इस तथ्य के मद्देनजर कटौती करनी पड़ी थी कि उनके ग्राहकों को चीन के निर्यातक द्वारा कम कीमतों की पेशकश की जा रही थी। घरेलू उद्योग तथा एल एंड टी एवं घरेलू उद्योग तथा सुभाष प्रोजेक्ट्स के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों से यह देखा जा सकता है कि कीमतों को चीन के निर्यातक द्वारा प्रस्तावित कीमतों की बराबरी करने के लिए कम करना पड़ा था। यह तथ्य कि संविदाएं अंतिम रूप से घरेलू उद्योग को नहीं दी गई थीं कीमतों में पर्याप्त कटौती का स्पष्ट साक्ष्य है।

कम कीमत पर बिक्री

156. कम कीमत पर बिक्री के निर्धारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत की तुलना जांच अधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के साथ की गई है। इससे यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री 10-25% के बीच रही है। मैं जिंदल सॉ. लि. ने कुछ आंकड़े उपलब्ध कराने के बाद आगे सहयोग नहीं किया। नवीनतम लागत लेखा रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े लेखांकन वर्ष 1-10-2004 से 30-9-2005 से संबंधित थे, परंतु इन पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इस जांच से संबंधित जांच अवधि 1-4-2005 से 31-12-2005 तक थी। अतः क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए मै. इलेक्ट्रोस्टील कार्स्टिंग लि. और मै. लेंको इंडस्ट्रीज लि. के आंकड़े लिए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ कच्चे माल की लागत और उसकी खपत उपयोगी वस्तुओं की लागत, श्रम की लागत, मूल्यहास की लागत, बिक्री एवं प्रशासकीय व्यय, लगाई गई पूंजी पर ब्याज एवं समुचित लाभ पर विचार किया गया है। तुलना से ज्ञात होता है कि जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री 10% से 25% के बीच थी।

	कम कीमत पर बिक्री
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	***
पहुंच मूल्य/मी.टन	30171
कम कीमत पर बिक्री	***
कम कीमत पर बिक्री %	17.02%

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि चीन से हुए पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव

157. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम के अनुबंध-2 के अनुसार विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों का विश्लेषण करते हुए घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की आगे जांच की थी।

घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. जिंदल सां लि. ने जांच अवधि के दौरान बिक्री की है और इसलिए विश्लेषण समस्त उत्पादकों की मात्रा को शामिल करके किया गया है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान समस्त उत्पादकों की बिक्री मात्रा में 44% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 48% की वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-0 में 9%, 2004-05 में 25% और जांच अवधि में 9% की वृद्धि हुई है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि इसी अवधि के दौरान मांग में वृद्धि के अनुरूप सभी उत्पादकों की बिक्री की समग्र मात्रा में 44% की वृद्धि हुई है।

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल -दिसं. 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
सभी उत्पादकों की बिक्री (मी.टन)	152193	165320	189943	164289	219052
प्रवृत्ति	100	109	125	108	144
डी आई वी बिक्री (मी.ट.)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	109	125	109	109

घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल -दिसं. 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री (मी.ट.)	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री (मी.ट.)				***	***
संबद्ध देश से आयात (मी.ट.)	0	2867	13412	4644	6192
कुल मांग (मी.ट.)	152193	168187	203355	168933	225244
घरेलू उद्योग का हिस्सा	100%	98.30%	93.40%	73.50%	73.50%
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	0%	0%	0%	23.75%	23.75%
सभी उत्पादकों का हिस्सा	100%	98.30%	93.40%	97.25%	97.25%
संबद्ध देश का हिस्सा	0%	1.70%	6.60%	2.75%	2.75%

159. आंकड़ों से यह पता चलता है कि सभी उत्पादकों का हिस्सा 2002-03 में 100%, 2003-04 में 98.03%, 2004-05 में 93.40% और जांच अवधि में 97.25% था। आधार वर्ष से घरेलू उद्योग का हिस्सा 100% से घटकर जांच अवधि में 97.25% हो गया। संबद्ध देश का हिस्सा 2003-04 में 1.70% था जो 2004-05 में बढ़कर 6.60% हो गया और जांच अवधि में घटकर 2.75% हो गया।

उत्पादन, क्षमता तथा क्षमता उपयोग

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल 05-दिसं. 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
घरेलू उद्योग की क्षमता (मी. ट.)	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों की क्षमता (मी.ट.)				***	***
सभी उत्पादकों की कुल क्षमता	260000	290000	290000	367500	490000
प्रवृत्ति (सूचीकृत)	100	112	112	141	188
घरेलू उद्योग का उत्पादन (मी.टन)	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों का उत्पादन (मी.टन)	***	***	***	***	***
कुल उत्पादन (मी.टन)	201976	218579	240549	222574	296765

प्रवृत्ति	100	108	119	110	147
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग (%)	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों का क्षमता उपयोग (%)	***	***	***	***	***
कुल क्षमता उपयोग (%)	78%	75%	83%	60.56	60.56

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी उत्पादकों की क्षमता जांच अवधि के दौरान बढ़कर 490000 मी.टन हो गई अर्थात् आधार वर्ष के दौरान 260000 मी.टन की तुलना में 88% की वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान सभी उत्पादकों के उत्पादन में 47% की वृद्धि हुई। तथापि, सभी उत्पादकों का क्षमता उपयोग आधार वर्ष में 78% से घटकर जांच अवधि में 61% हो गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता उपयोग में गिरावट बाजार में नए प्रवेशकर्ता द्वारा जांच अवधि के दौरान क्षमता में नई वृद्धि के कारण आई है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान सभी उत्पादकों के उत्पादन में 47% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 33% की वृद्धि हुई है।

लाभप्रदता

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल -दिसं. 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
लाभ/हानि (रु/इकाई)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	128	123	54	54
लाभ/हानि (लाख रु.)	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	139	154	44	58

161. आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2002-03 में 100 (सूचीकृत) के आधार से लाभ प्रति मी.टन 2003-04 में बढ़कर 128 हो गया, 2004 में घटकर 123 और जांच अवधि के दौरान 54 हो गया। इससे यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को लाभ में पर्याप्त घाटा हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाभप्रदता में गिरावट 2004-05 में शुरू हुई परंतु जांच अवधि में लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई। समग्र रूप में लाभ 100 से बढ़कर 154 हो गए और तत्पश्चात् इसी अवधि के दौरान तेजी से घटकर 44 हो गए।

लगाई गई पूंजी से आय (लगाई गई पूंजी)

162. घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय (आर ओ सी ई) वर्ष 2002-2003 में 19.42% से अभूतपूर्व गिरावट प्रदर्शित करते हुए जांच अवधि के दौरान मात्र 4.79% रह गई। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि यह गिरावट 2004-05 में शुरू हुई लेकिन भारी गिरावट जांच अवधि के दौरान आई जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तव में पाटित आयातों के कारण नुकसान हुआ है।

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल 05 - दिसं. 05 जांच अवधि
लगाई गई पूंजी (लाख रु. में)	***	***	***	***
- नियम परिसंपत्तियां	***	***	***	***
- निवल कार्यशील पूंजी	***	***	***	***
ब्याज पूर्व लाभ	***	***	***	***
आर ओ सी ई (%)	***	***	***	***

नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव

163. घरेलू उद्योग के वित्तीय आंकड़ों की जांच से यह पता चलता है कि पाटित आयातों का घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा जांच अवधि के दौरान लाभ जमा मूल्य ह्रास में उतनी ही गिरावट आई है। नकदी प्रवाह संबंधी आंकड़े निम्नलिखित विवरण में दिए गए हैं :-

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	अप्रैल 05- दिसं. 05 जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक)
लाभ:हानि	***	***	***	***	***
मूल्यह्रास	***	***	***	***	***
नकदी प्रवाह	***	***	***	***	***
नकदी प्रवाह/इकाई	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	140	155	56	75

उत्पादकता

164. क्षति जांच अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः उत्पादकता घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं है क्योंकि उत्पादकता वर्ष 2002-03 में सूचीकृत 100 प्रति कर्मचारी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 108 हो गई है।

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	जांच अवधि (वार्षिक)
उत्पादन(मी.ट.)	***	***	***	***
कर्मचारी	***	***	***	***
उत्पादन प्रति कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	103	118	120

रोजगार तथा मजदूरी

165. क्षति की जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्षति जांच अवधि की तुलना में प्रति कर्मचारी मजदूरी में वृद्धि हुई है जो घरेलू उद्योग के अनुसार संविदागत/कानूनी दायित्वों को ध्यान में रखते हुए हुई है।

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	जांच अवधि (वार्षिक)
कर्मचारियों की संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	105	101	99
कुल मजदूरी (लाख रुपए)	***	***	***	***
मजदूरी /कर्मचारी (रु.)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	168	207	180

मालसूची

166. क्षति जांच अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में समग्र रूप में और दिनों की संख्या के रूप में वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग की क्षति का स्पष्ट रूप से पता चलता है। औसत स्टॉक 2002-2003 में 12397 मी.टन (100) से घटकर जांच अवधि के दौरान 12111 मी.टन (98 वार्षिकीकृत) रह गया है। बिक्री के दिनों की संख्या भी इसी अवधि के दौरान 29.32 (100) से बढ़कर 52.67 दिन (180) हो गई है।

	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	अप्रैल 04 से मार्च 05	जांच अवधि
औसत स्टॉक (मी.टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	112	89	98
औसत स्टॉक (दिनों की संख्या)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	103	71	90

पाटन मार्जिन की मात्रा

167. घरेलू उद्योग तथा सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह देखा गया है कि जहां तक चीन से हुए आयातों का संबंध है, पाटन मार्जिन की पर्याप्त मात्रा 40.47% रही है।

वृद्धि

168. आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तु की मांग, उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है तथापि, लाभ, लाभप्रदता एवं लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में इसमें गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

169. घरेलू उद्योग का दावा है कि लाभप्रदता, बाजार हिस्सा और आर ओ सी ई में गिरावट के मद्देनजर उनके लिए व्यापार में किसी नई पूँजी को जुटाना व्यवहार्य नहीं होगा। कार्रवाई के दौरान निर्यातक ने ईसीएल के जीडीआर प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज का भी उल्लेख किया है जो उनके अनुसार इस बात की संदेहातीत पुष्टि करेगा कि ईसीएल सामान्यतः चीन से और मुख्यतः जिंगजिंग से जांच अवधि के दौरान क्षति महसूस नहीं कर रहा था। घरेलू उद्योग ने अपने प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोधों में यह दावा किया है कि वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। उन्होंने आगे यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति निर्धारण अनुबंध-2 के अंतर्गत समग्र रूप से किया गया है न कि घरेलू उद्योग के संघटकों में से किसी एक के संबंध में। उन्होंने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए दायर की गई याचिका समग्र रूप से और जी डी आर अभिकथनों के लिए दायर की गई थी जो ई सी एल से ही संबंधित थी और जो समग्र कंपनी से संबंधित है न कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित। आगे यह अनुरोध किया गया था कि उल्लिखित जी डी आर दस्तावेज जांच अवधि से संबंधित नहीं है। संबंधित पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने पर जांच करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि उनका दायित्व समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए और न कि उसके अलग-अलग संघटकों के लिए अनुबंध-2 के अंतर्गत क्षति की जांच करने का है। इसी के साथ-साथ घरेलू उद्योग ने यह सटीक उल्लेख किया है कि जी डी आर प्रस्ताव दस्तावेज में दिए गए विवरण ईसीएल के समग्र प्रचालनों से संबंधित है न कि केवल विचाराधीन उत्पाद और जांच अवधि के संबंध में। जिंगजिंग का जी डी आर प्रस्ताव दस्तावेज के उद्धरणों पर भरोसा भी अप्रमाणित है क्योंकि जीडीआर प्रस्ताव दस्तावेज में 31 मार्च, 2005 से पूर्व की सूचना का उल्लेख है और जून, 2005 तक की कुछ असंपरीक्षित सूचना निहित है न कि संपूर्ण जांच अवधि की। इसके मद्देनजर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें जिंगजिंग के बारे में निहित विवरण पर जांच अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण हेतु भरोसा नहीं किया जा सकता है।

170. यह कथन कि ईसीएल के अनुभव को प्रतिस्पर्धियों द्वारा दोहराया नहीं जा सकता, क्षति के संबंध में दिया गया एक कथन है न कि भारत में प्रचालनों की स्थापना करने वाले उत्पादकों के संदर्भ में। इसके अलावा, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कंपनी का मत यह है कि वह अनुचित प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर सकती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य से यह पता चलता है कि वस्तु का भारत में पाटन किया गया है जिससे यह पता चलता है कि निर्यातक अनुचित प्रतिस्पर्धा का सहारा ले रहा था। किसी जांच का उद्देश्य घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क को लगाकर निष्पक्ष व्यापार की बहाली करना है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी निर्यातक द्वारा इस संबंध में दिए गए किसी तर्क में कोई गुण नहीं पाते हैं।

गंवाई गई संविदाओं का साक्ष्य

171. घरेलू उद्योग ने चीन के आपूर्तिकर्ता और घरेलू उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा के कई उदाहरण देते हुए सूचना प्रस्तुत की है जिससे यह पता चलता है कि जांच अवधि और जांच

अवधि से पूर्व की अवधि में कीमत में कटौती हुई थी। यह इन दस्तावेजों से देखा जा सकता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने केरल वॉटर अथॉरिटी (के डब्ल्यू ए) को एल एंड टी तथा सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लि. के जरिए की जाने वाली 26238 मी.टन की आपूर्तियों के बड़े ठेके को गंवाया है। प्राधिकारी ने केरल वॉटर अथॉरिटी तथा ठेके में शामिल अन्य पार्टियों के साथ पत्राचार भी किया। केरल वॉटर अथॉरिटी ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन के निर्यातक को उक्त परियोजना के एक अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में जोड़ा गया है। निर्यातक ने यह कहा है कि चीन के आपूर्तिकर्ता ने भारतीय आपूर्तिकर्ता का स्थान इसलिए लिया क्योंकि आपूर्तिकर्ता का स्थान डिलीवरी अनुसूची के कारण लिया न कि कीमतों के कारण। तथापि, घरेलू उद्योग एवं ठेकेदार के बीच हुए पत्राचार से इस बात का स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि बातचीत कीमतों के संबंध में थी न कि डिलीवरी अनुसूची के संबंध में। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 26238 मी.टन की आपूर्ति की उपर्युक्त आपूर्ति के आर्डर चीन के निर्यातक के खाते में चले गए। यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त ठेका चीन के निर्यातक द्वारा प्रस्तावित कम कीमतों के कारण ही गंवाया गया था।

172. निर्यातक ने ऐसे अनेक ठेकों का उल्लेख किया है जिन्हें निर्यातक घरेलू उद्योग को प्रदान किए जाने का दावा करता है। यह भी बताया गया है कि घरेलू उद्योग ने ठेकों के संबंध में प्राधिकारी से सूचना छिपाई है। घरेलू उद्योग ने बताया कि ये ठेके जांचावधि और जांचावधि के बाद की अवधि से संबंधित हैं और इनमें से अनेक उदाहरणों के बारे में प्राधिकारी को सार्वजनिक सुनवाई के बाद किए गए अनुरोधों में सूचित किया जा चुका है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित ठेके के उदाहरण चीन के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिस्पर्धा और कीमत कटौती के संदर्भ में थे। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को प्रदत्त सभी ठेकों को घरेलू उद्योग के लिए सूचित करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह जांच निर्यातक द्वारा कीमत कटौती और पाटन के कारण घरेलू उद्योग द्वारा गंवाए गए एककों से संबंधित है।

173. गंवाए गए पर्याप्त ठेकों के मद्देनजर पूर्व में बताए गए अनुसार घरेलू उद्योग को अन्य ठेकों के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूर किया गया था कि वे आगे और ठेकों को न गंवाए भले ही इनसे उद्योग की लाभप्रदता का पर्याप्त घाटा होता हो। इसे क्षति अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग की कीमत प्रवृत्ति के संदर्भ में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग ने चीन के निर्यातकों के लिए पर्याप्त ठेके गंवाए हैं और उसे कीमत में कमी के कारण भारी घाटा भी हुआ है। ठेकों का गंवाया जाना घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा में भी प्रदर्शित होता है।

च. 5 क्षति से संबंधित निष्कर्ष

174. संबद्ध वस्तु की मांग में आधारवर्ष से लेकर जांच अवधि तक 48% की वृद्धि हुई है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात जांच अवधि के दौरान 0 मी.टन से बढ़कर 6192 मी.टन हो गए हैं, सभी उत्पादकों की घरेलू बिक्री में 44% की वृद्धि हुई है और इसी अवधि के दौरान सभी उत्पादकों के उत्पादन में 47% की वृद्धि हुई है।

175. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत वर्ष 2003-04 में बढ़कर 15%, 2004-05 में 46% और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बढ़कर 55% हो गई है। बिक्री कीमत से संबंधित प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि बिक्री कीमत में 2003-04 में 18%, 2004-05 में 42% और इसी अवधि के दौरान जांच अवधि में 36% की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में प्रति इकाई लाभ में 2003-04 में 28%, 2004-05 में 23% की वृद्धि हुई और जांच अवधि में आधार वर्ष की 54% की गिरावट आई। आंकड़ों से यह पता चलता है कि बिक्री लागत में आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक वृद्धि होती रही जबकि 2004-05 में बिक्री कीमत में मामूली गिरावट आई लेकिन जांच अवधि में इसमें तेजी से गिरावट आई। लगाई गई पूंजी पर आय में ऐसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। इसमें 2003-04 में वृद्धि हुई, 2004-05 में मामूली गिरावट आई किंतु जांच अवधि में तेजी से गिरावट आई। ठेके गंवाए जाने के साक्ष्य से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग निर्यातक द्वारा कटौती के कारण कीमत में कमी करके ही उत्पाद को बेचने की स्थिति में था। गंवाए गए ठेकों के कारण मात्रा के नुकसान वास्तव में जांच अवधि के बाद ही हुआ होगा।

176. उपर्युक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि यद्यपि आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक आयातों में वृद्धि हुई थी तथापि, 2004-05 की तुलना में आयात 13412 मी.टन से समग्र रूप से घटकर जांच अवधि के दौरान 6192 मी.टन (वार्षिक) हो गए हैं। आवेदक घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में 2004-05 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच अवधि में इसमें गिरावट आई। सभी घरेलू उत्पादकों की बिक्री से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। आंकड़ों से यह पता चलता है कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयातों में गिरावट आई लेकिन संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के अनुरूप सभी घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि हुई।

177. आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक बिक्री लागत में वृद्धि होती रही, जांच अवधि में गिरावट से पूर्व 2004-05 तक बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। प्रति इकाई लाभ/हानि संबंधी आंकड़ों से यह पता चलता है कि यह गिरावट 2004-05 में शुरू हुई लेकिन तत्काल पूर्ववर्ती और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में तेजी से गिरावट आई। लगाई गई पूंजी पर आय में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी गई। विश्लेषण से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के अनुरूप उत्पादन और बिक्री की लेकिन घरेलू उद्योग लाभप्रदता तथा लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में जांच अवधि के दौरान भारी दबाव में बना रहा जिससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चलता है।

178. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को चीन से हुए पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है और यह कि जांच अवधि के दौरान निर्यातक को प्राप्त भारी मात्रा के आर्डर के कारण क्षति होने का आसन्नवर्ती खतरा भी बना हुआ है।

च. 6 अन्य ज्ञात कारक

179. प्राधिकारी ने अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो को अलग करने के लिए नियमों में यथानिर्धारित कारणात्मक संबंध तथा अन्य अहेतुक कारकों के मुद्दे की भी जांच की गई है। इस संबंध में नियमों में यथानिर्धारित निम्नलिखित संकेतकों की जांच की गई है।

(i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा एवं कीमत

180. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूची क्षति अवधि के दौरान अन्य देश से कोई आयात नहीं हुआ था इसलिए इस संकेतक पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है।

(ii) अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रतिस्पर्धा

181. मै. जिंदल सॉ लि. ने जांच अवधि के दौरान बाजार में प्रवेश किया। निर्यातक एवं आयातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति मै. जिंदल सॉ लि. द्वारा दी गई प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक घरेलू उद्योग को क्षति की मात्रा बाजार में नए प्रवेशकर्ता के संदर्भ में हुई है। यह भी बताया गया है कि मै. जिंदल सॉ लि. को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। इसीलिए उसे मौजूदा उत्पादकों की तुलना में कीमत का लाभ हासिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार में नए उत्पादक के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी लाजिमी थी। तथापि, जब संबद्ध वस्तु की मांग में भारी वृद्धि हुई थी तो बाजार में नए प्रवेशकर्ता के हिस्से के जरिए बिक्री समग्र रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में इकाई स्थापित करने के प्रयोजनार्थ मै. जिंदल सॉ लि. को उत्पाद शुल्क छूट दी गई थी। उत्पाद शुल्क में छूट सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की हानि को समायोजित करने के लिए प्रदान की गई थी।

182. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2004-05 में मै. जिंदी सॉ लि. की अनुपस्थिति में घरेलू उद्योग उत्पादन की बढ़ती हुई लागत के अनुपात में कीमत में वृद्धि नहीं कर सका। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2004-05 में आयातों के पहुंच मूल्य से बिक्री कीमत में कटौती की जा रही थी जिससे यह पता चलता है कि चीन जन.गण. से पाटित आयातों द्वारा कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन लागत के अनुपात में अपनी कीमत बढ़ाने से वंचित हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनकी लाभप्रदता प्रभावित हुई। चूंकि चीन जन.गण. से कीमत कटौती जांच अवधि के दौरान जारी रही इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि जांच अवधि के दौरान मै. जिंदी सॉ लि. के प्रवेश के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

(iii) मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

183. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु में भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कुल मांग में 48% की वृद्धि हुई है। घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का हेतु माना जा सकता है।

(iv) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार एवं प्रतिस्पर्धा

184. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग में ऐसा कोई प्रतिबंधात्मक व्यवहार प्रचलित नहीं है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सकता है।

(v) प्रौद्योगिकी विकास

185. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः किसी अन्य प्रौद्योगिकी के विकास को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

(vi) निर्यात निष्पादन

186. उत्पादन, क्षमता उपयोग के प्रयोजनार्थ निर्यात उत्पादन को हिसाब में लिया गया है लेकिन बिक्री कीमत, लाभप्रदता, लाभ एवं लगाई गई पूंजी पर आय के लिए घरेलू उद्योग से संबंधित आंकड़ों को हिसाब में लिया गया है। अतः निर्यात निष्पादन के प्रभाव से घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री से संबंधित विश्लेषण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए इस कारक को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(vii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता

187. क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इसलिए इसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

188. घरेलू उद्योग को संभावित रूप से क्षति पहुंचाने वाले किसी अन्य कारक को प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया है।

च. 7 कारणात्मक संबंध

189. संबद्ध वस्तु की मांग में 48% की वृद्धि हुई, आयातों में यद्यपि आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक समग्र रूप में वृद्धि हुई तथापि, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वास्तव में गिरावट आई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2004-05 में आयातों में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ संबद्ध देश से आयातों द्वारा बिक्री कीमत में पर्याप्त कटौती हुई। सभी घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 100 से घटकर जांच अवधि के दौरान 97.25% हो गया। इसी अवधि के दौरान संबद्ध देश का हिस्सा 0% से बढ़कर 2.75% हो गया लेकिन संबद्ध देश का हिस्सा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में 6.60% से घटकर जांच अवधि में 2.75% हो गया। सहयोगी निर्यातक द्वारा यह

तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को मात्रा के संबंध में नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि संबद्ध देश के हिस्से में वास्तव में गिरावट आई है। यह भी तर्क दिया गया है कि अक्टूबर घरेलू उद्योग द्वारा मात्रा मा नुकसान वस्तुतः उस नए उत्पादक के कारण हुआ है जिसने जांच अवधि के दौरान बाजार में प्रवेश किया है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को मात्रा के रूप में नुकसान नहीं हुआ है लेकिन घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसने निर्यातक द्वारा कीमत कटौती के कारण जांच अवधि के दौरान ठेका गवाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ठेके के कारण मात्रा का नुकसान उस अवधि में वास्तव में हुआ है जिस अवधि में वस्तु की वास्तविक डिलीवरी हुई होगी लेकिन पाटित आयातों द्वारा कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग पाटित आयातों के साथ अपनी कीमतें बराबर नहीं कर पाने की स्थिति में मात्रा के घाटे के निरंतर भोग में रहा होगा।

190. तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमत तथा लाभप्रदता में तीव्र गिरावट दर्शायी है जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यातक की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। आयातित वस्तु के पहुंच मूल्य में इसी अवधि के दौरान गिरावट और गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी गयी है। बिक्री कीमत में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के लिए इस बात को ध्यान में रखकर बिक्री कीमत में कमी करने का कोई कारण नहीं था कि उसे आयातों की कीमत के साथ अपनी कीमत को बैचमार्किंग करना पड़ा था। निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नए प्रवेशकर्ता मै. जिंदल साँ लि. को उत्पाद शुल्क को छूट का लाभ प्राप्त था इसलिए उन्होंने आवेदक घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा देने के लिए कीमत में कमी की जिसके पारेणामस्वरूप नए प्रवेशकर्ता के कारण आवेदक को मात्रा संबंधी नुकसान हुआ था। यह नोट किया गया है कि 2004-05 में घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं की। उसने यह उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग आयातों के साथ अपनी कीमतों की बैचमार्किंग कर रहा था। (पूर्ववर्ती वर्ष में मै. जिंदल साँ लिमिटेड बाजार में नहीं था और यह मौजूदा उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा नहीं दे सका)। प्राधिकारी यह मानते हैं कि मै. जिंदल साँ लि. ने बाजार में प्रतिस्पर्धा सृजित की है तथापि घरेलू उद्योग आयातों के साथ अपनी कीमतों की बैचमार्किंग भी कर रहा था जैसा कि आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट से पता चलता है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि जांच अवधि के दौरान निर्यातक को घरेलू उद्योग द्वारा ठेकों के नुकसान से स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग बाजार में अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए कीमतें कम करने हेतु निर्यातक के दबाव में था। निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ठेकों के नुकसान से जांच अवधि के बाद भी घरेलू उद्योग पर वास्तव में प्रभाव पड़ा होगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्रकार के उत्पाद में जहां निविदा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, निविदाएं जारी करने और वस्तु की वास्तविक आपूर्ति के बीच समयंतराल होता है, लेकिन निर्यातक द्वारा कीमत कटौती तब दृष्टिगोचर हुई थी जब निविदा खोली गई थी और ठेकेदार कीमतें कम करने के लिए उत्पादक पर दबाव बना रहे थे। उपलब्ध दस्तावेजों में किए गए उल्लेख के अनुसार निर्यातक द्वारा वास्तव में आपूर्ति की जा रही वस्तु से स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि मात्रा का नुकसान जांच अवधि से आगे की अवधि में भी वास्तव में हुआ होगा, लेकिन कीमत प्रभाव जांच अवधि के दौरान ही दिखाई दिया है।

191. उपर्युक्त के भूतनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच अवधि पाटित आयातों के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने मात्रा के रूप में तुरंत नुकसान नहीं उठाया है तथापि, उद्योग बाजार में हिस्सा बरकरार रखने के लिए कीमत में कटौती करनी पड़ी है और लाभप्रदता तथा लगाई गई पूंजी पर आय का नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा ठेके के नुकसान और घरेलू उत्पादक का स्थान निर्यातक द्वारा लिए जाने से जिसके लिए जांच अवधि के बाद आपूर्तियां की जानी हैं वह सिद्ध होता है कि संभावित आयातों तथा घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन के बीच करपात्मक संबंध है।

छ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

192. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः ऐसे पाटन को समाप्त करना है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है और भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति बहाल करना है जो देश के सामान्य हित में है ।

193. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तु अथवा संबद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है । तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों के लागू किये जाने से पाटन की पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी । अनुषंगी उद्योग पर प्रभाव को कम करने की दृष्टि से प्राधिकारी ने पाटन तथा क्षति मार्जिनों से कम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित समझा है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों के लागू होने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

ज. निष्कर्ष

194. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-

- (क) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है ;
- (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ;
- (ग) यह क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

झ. सिफारिशें

195. संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझा जाता है । तदनुसार प्राधिकारी डीआई पाइपों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

196. पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है जिसे यदि लागू किया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी । आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के साथ भी की गई है । इस मामले में क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन से कम है, तदनुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क को केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	73030030 तथा 73030090	डी आई पाइप	चीन जन. गण.	ग्रीन जन. गण.	मै. जिगजिग डक्टाइल आयरन पाइपस कं. लि.	कोई	127.40	मी. टन	अम. डॉ.
2.	वही	वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	उपरोक्त के अलावा कोई अन्य	कोई	139.79	मी. टन	अम. डॉ.
3.	वही	वही	चीन जन. गण.	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	कोई	कोई	139.79	मी. टन	अम. डॉ.
4.	वही	वही	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	ग्रीन जन. गण.	कोई	कोई	139.79	मी. टन	अम. डॉ.

197. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2007

Final Findings

Subject : Anti-dumping investigations involving imports of DI Pipes originating in or exported from China PR

No. 14/14/2005-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof:

2. Whereas M/s Electrosteel Castings Ltd. and M/s Lanco Industries Ltd. (herein after referred to as the Applicants) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules), alleging dumping of DI pipes (herein after referred to as subject goods), originating in or exported from China PR (herein after referred to as subject country) and requested for initiation of Anti Dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods. The Authority notified the Embassy of China PR about the receipt of dumping allegation in accordance with sub rule 5(5) of Rules.

3. WHEREAS, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 24.2.2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with the sub-Rule 6(1) of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the antidumping duty.

A. Procedure

4. Procedure described below has been followed with regard to this investigation after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigations by the Authority.

- (i) The Designated Authority sent copies of initiation notification dated 24th February 2006 to the Embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country, importers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- (ii) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and to the Embassy of China PR in accordance with Rule 6(3) supra.
- (iii) The Embassy of the People's Republic of China in India, was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. Copies of the letters and questionnaire sent to the exporters were also sent to them, alongwith the names and addresses of the exporters.
- (iv) A questionnaire for according market economy treatment was forwarded to all the known exporters and the Embassy of the Peoples' Republic of China and Bureau of Fair Trade China (BOFT) China PR. While, for the purpose of initiation, the normal value in China PR was considered based on the constructed cost of production of the subject goods in China PR, the authority informed the known exporters that it proposed to examine the claim of the applicant in the light of para (7) & (8) of Annexure-I of the Anti-Dumping Rules as amended. The concerned exporters / producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish necessary information / sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to enable the Designated Authority to consider whether market economy treatment could be granted to cooperating exporters / producers who could demonstrate that they satisfied the criteria stipulated in the said paragraph.
- (v) The Authority sent a questionnaire, to elicit relevant information to the known exporters in China PR in accordance with Rule 6(4):
 - a. In response to the Initiation Notification, M/s Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. (XDIPL) provided information on exporter's questionnaire for determination of dumping and information for rebutting Non-Market Economy Treatment.
- (vi) Exporters who have not provided the information in the investigation have been treated as non-cooperating exporters.
- (vii) Questionnaires were sent to known importers and Consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4). In response to the notification, following importers provided information:

- a) M/s Larsen & Toubro Ltd., Chennai
- b) M/s J V Gokal & Co. Ltd., Mumbai
- c) M/s Gammon India Ltd., Mumbai
- d) M/s Engineering (Projects) India Ltd., New Delhi

The data shows that only M/s J V Gokal & Co., Mumbai had imported subject goods during the POI.

- (viii) Importers/users who have not provided information in this investigation have been treated as non-cooperating importers/users.
- (ix) The Authority held a Public Hearing on 8.8.2006 to hear the interested parties. The parties attending the Public Hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The Designated Authority considered the submissions as received from the interested parties in the findings.
- (x) The Authority verified the information provided by the domestic industry to the extent considered necessary.
- (xi) The Authority also verified the information provided by the cooperating producer/exporter to the extent considered necessary.
- (xii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigations;
- (xiii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file (duly indexed) kept open for inspection by the interested parties. The acknowledgements of interested parties inspecting files and taking copies of the record have been kept in the public file.
- (xiv) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- (xv) In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received thereon have also been duly considered in the findings.
- (xvi) *** in this Notification represents information furnished by the applicant on confidential basis and so considered by Authority under the Rules.
- (xvii) Investigation was carried out for the period starting from 1.4.2005 to 31.12.2005(POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from April 2002-March 2003, April 2003-March 2004, April 2004- March 2005 and the POI.

B. Product Under Consideration

5. The product under consideration is Ductile Iron Spun Pipe as defined under clause 3.1 and 3.2 of International Standard, ISO 2531 (for water and gas) and ISO 7186 (for sewage applications). These are often also described as Spheroidal Graphite Iron Pipes or Ductile Cast Iron Pipes or Ductile Iron Spun Pipes. These are classifiable within 73030030 and 73030090 of the Customs Tariff Act.

6. DI Pipes performs the function of transporting liquid object at long distances at high pressure. It is primarily used for transporting water or sewerage disposal and gas, transmission of domestic and industrial effluent, fire-fighting systems on shore and off-shore. The various applications of DI Pipes are:

1. Transmission of raw, potable and sea water at high pressures.
2. Distribution of potable water and gas.
3. Disposal of domestic and industrial effluent.
4. Fire-fighting systems on shore and off shore.

The production technology adopted for manufacturing DI Pipes is centrifugal casting.

B. 2. Product Exported by 'XDIPL'

7. The specifications of XDIPL's products exported to India are the same as the product sold in the domestic market of India. The product involved in the investigation is produced pursuant to the international standard ISO 2531 push-in joint, with the effective length of 6 meters, and the size of DN 80mm-DN 2600mm. The product is mainly used to transport drinking water, sewage and all kinds of gas.

8. The product exported by XDIPL uses the standard coating. The inner cement of the product is in accordance with standard ISO 4179. The outer zinc coating and bitumen coating of the product is in accordance with standard ISO 8179. The grade of thickness of the pipes is K9.

B.3. Like Article

9. Domestic industry manufactures DI pipes in various sizes from 80mm to 1100mm dia. Larger size pipes can also be made.

10. DI Pipes product by the domestic industry and imported from China are comparable in terms of characteristics such as product properties, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods.

11. No argument has been raised by any interested party on like article. The Authority, in view of above, holds that the DI pipes manufactured by the domestic industry and imported from China is like article as per section 2(d) of the Anti-dumping Rules.

C. Domestic Industry and Standing

12. The application for anti-dumping investigation was filed by M/s Electrosteel Castings Ltd. and M/s Lanco Industries Ltd. After initiation of the investigation, M/s Jindal Saw Ltd. expressed its support for investigation. The applicants and the supporter account for 100% of the production of DI pipes, therefore, the applicants have the desired 'standing'. The applicants account for 81% of the total production of Indian producers during POI, therefore, constitute domestic industry as per rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.

13. The exporter has argued that for the purpose of injury analysis, M/s Jindal Saw Ltd. constitutes a 'significant' player, therefore, the domestic industry should gather the data with reference to Jindal to provide correct and substantive analysis of the impact, if any, of Chinese imports. The Authority notes that the applicant domestic industry accounts for 81% of the total production during the POI and constitute domestic industry within the meaning of the Rules. M/s Jindal Saw Ltd. began its production only during POI. The company expressed its support to the investigation and provided some information, however, it did not cooperate further by replying to queries of the Authority and providing non-confidential version of the confidential data already provided. The Authority has option of discarding the data, however, the data relating to capacity, production and sales in volume terms have been relied on for assessing the demand and capacity utilisation. The data relating to other aspects has not been taken into account. Moreover, the exporter itself has objected to the use of data provided by M/s Jindal Saw Ltd.

D. Other issues

D.1. Issue of Memorandum of Understanding between ECL and XDIPL

Submissions by XDIPL

14. It has been submitted that XDIPL group had been supplying patented technology and equipment to Electrosteel since 1999. In February 2006, Electrosteel also entered into a contract to procure technology and equipment of a sinter plant from an associate company of XDIPL. In April 2006, Electrosteel officials visited XDIPL's factory and signed a MOU on their own free will and volition. In the said MOU, Electrosteel admitted to the following:

1. That XDIPL has not indulged in dumping and that XDIPL is a highly transparent company.
 2. That Electrosteel would report "the truth" to the Indian Government and "cancel" the anti-dumping investigation against XDIPL as soon as possible.
15. Electrosteel further sought XDIPL's assistance in setting up its new steel plant by supplying "advanced technology and equipment". The MOU was signed by Umang Kejriwal and Uddhav Kejriwal. It is also important to note that Electrosteel has not disputed the existence of the MOU and has admitted to the contents thereof. It has been further submitted that despite extensive submissions that DGAD should terminate the investigation under Rule 14, however, DGAD has not done so. It has been further stated that DGAD should nonetheless take note of contents of MOU as it establishes that petition was initiated without any basis and in bad faith.

16. The Authority notes that after the initiation of investigation on DI Pipes, XDIPL brought to the notice of the Designated Authority that there existed a Memorandum of Understanding (MOU) between ECL and XDIPL stating that XDIPL has not indulged in dumping and Electrosteel would report 'the truth' to the Indian Government and 'cancel' the anti-dumping investigations against XDIPL as soon as possible. XDIPL requested the Authority to terminate the investigation on the basis of MOU. The exporter also filed a writ petition in Delhi High Court seeking termination of investigation on the same ground.

17. The Authority after taking into account submissions made by the domestic industry and XDIPL observed that the termination of investigation was possible under

Rule 14(a) of the Rules where a request in writing has to be made by the domestic industry in this regard. As there was no expressed request from the domestic industry for termination of the investigation, therefore, the Authority decided to continue with the investigation. It was also informed to the interested parties that the investigation may be terminated during the course of investigation under sub rule (b), (c), (d) and (e) Rule 14 or any other provision of the Rules depending upon the facts and circumstances. The Delhi High Court dismissed the writ petition on the ground that the domestic industry had not made any request under Rule 14(a) of the Anti-dumping Rules.

18. Now it has been contended that the Authority may take into account the content of the Memorandum of Understanding. In this regard, the Authority holds that after initiation of the investigation, for taking any decision, the Authority has to take into account submissions of all the interested parties. The Authority is also of the view that agreement or content of MOU between two private parties cannot be considered as findings of the Authority. Further, the Authority has not gone into the circumstances under which the MOU was signed between the two private parties particularly when the domestic industry has kept on insisting for continuation of investigation. Therefore, the findings concerning dumping and market economy status are issued on the basis of appraisal of required facts as per Anti-dumping Rules.

D.2. Issue of Internal Competition between producers of the domestic industry

19. Interested parties have raised the issue that M/s Jindal Saw Ltd. has not joined the investigation. It has also been pointed out that loss market share of the domestic industry is on account of entry of M/s Jindal Saw Ltd. during the period of investigation. It has been argued that M/s Jindal Saw Ltd. enjoy the benefit of excise duty exemption, therefore, it has given the competition to the applicant domestic industry.

20. The Authority notes that with the entry of new producer in the market, the competition among the producers would have increased. It may have affected the financial performance of the existing producers. However, the present investigation is against the unfair trade on account of dumped imports from the subject country. The Authority further notes that in 2004-05, M/s Jindal Saw Ltd. was not producing the DI pipes so there could not have been internal competition between Jindal Saw and other domestic producers. In that year the domestic industry did not increase the selling price proportionate to increase in cost of production. The landed value of imports were undercutting the selling price of the domestic industry indicating that the domestic industry was benchmarking their prices with the imports. Subsequently in 2005-06 when Jindal Saw began its production of DI pipes, the competition *inter se* domestic producers must have been created. However, the landed value of imports during POI as well was undercutting the selling price of the domestic industry again indicates that the domestic producers were benchmarking their selling price with the imports. The Authority holds that as per the Anti-dumping Agreement, if the injury, if any, has been caused to the domestic industry by the dumped imports then it is not necessary to segregate injury caused by internal competition.

21. It has also been stated that because of exemption of excise duty to M/s Jindal Saw Ltd., the company was in a position to give competition to the existing domestic producers by offering competitive selling price. The Authority in this regard notes that the excise exemption to M/s Jindal Saw Ltd. was given by the Government to offset

the disadvantages of setting up the industry in a particular region. It is also pertinent that M/s Jindal Law Ltd. has expressed support to the anti-dumping investigation even though the company has not fully cooperated in the investigation.

D.3. Issue of Statement made in the GDR document

22. It has been pointed out by the cooperating exporter that the ECL has raised fund through the GDR issue and it has also been pointed out that how the company which has been making losses can have the confidence to convince the investors to invest in it and raise the fund of US\$40 million. It has further been pointed out that in the GDR offer document, the performance of the company on various parameters are inconsistent with the performance as submitted to DGAD for injury purpose. The decline in profitability of the company has been explained as rising cost of the raw materials. From the GDR offer document, the text has been quoted wherein the ECL had stated "With regard to the domestic market, XDIPL supplied approx. 10,000 tons of DI pipes to India during the financial year ended 31st March 2005 but has yet to make a significant impact on the Indian market. The company believes that the extensive experience of its management combined with its 45 year history as a spun pipe manufacturer in India cannot be easily replicated by competitors or new entrants in the domestic market." It has also been pointed out that in Electrosteel Castings Ltd. in offering memorandum for FCCB dated 11.5.2006 has also made same statement that "with regard to the domestic market, XDIPL supplied approx. 10,000 tons of DI pipes to India during the financial year ended 31st March 2005 but has yet to make a significant impact on the Indian market."

23. The Authority notes that through the GDR offer the fund has been raised by one of the producer and data quoted in offer document relates to period up to 31.3.2005 and some unaudited data up to June'05 however it does not cover complete period of the investigation. The GDR document refers to the performance of the company as a whole and not for the product under anti-dumping investigation, whereas the injury analysis by the Authority is restricted to only for the product under investigation and for a specific period of investigation for domestic industry as a whole and not for individual company.

24. Regarding claim of the company about its extensive experience in management is an expression of their strength and confidence to face the competition in the market. The statement in no way refers to the unfair competition by way of dumping from the other country. Concerning the statement that imports from China by XDIPL yet to make a significant impact on the Indian market, the Authority notes that Electrosteel Castings Ltd. in its annual report 2004-05 stated that "*the main threat to company is cheap imports from neighbouring Asian countries with the opening of the economy and continued reduction in imports duty*". The Authority further notes that the statement in context of international competitors in offer memorandum for FCCB dated 11.5.2006 though made after initiation of the anti-dumping investigation, is same statement as had been made in the GDR offer document as it refers to imports made up to March 2005. In view of the statements of the company made in different contexts, the Authority holds that the findings in the investigation are based on actual appraisal of facts and cannot be based on statements made in different contexts. Moreover, the statement made in different contexts cannot be bar to any company to seek investigation against unfair trade in the form of dumping.

D.4. Statements of the domestic industry in Annual Reports and GDR offer document regarding rising cost of raw materials impacting the profitability of the Domestic Industry

25. The exporter has argued that performance of the domestic industry as stated in the annual reports and GDR offer documents shows good performance and had indicated optimistic picture for the future. The Authority notes that the performance of the companies as indicated in the annual reports and GDR offer document relates to company as a whole and not restricted to subject goods under investigation for period relating to period of investigation. The data relating to the performance of the

company cannot be considered as performance about the subject goods and, therefore, cannot be relied upon for injury analysis. The Authority has relied on verified data relating to subject goods for period of investigation for the purpose of injury analysis.

26. It has been argued by the exporter that the cost of major raw materials increased abnormally as indicated in the annual reports of the domestic industry and GDR offer documents. The domestic industry increased the selling price to counter the effects of abnormal prices of raw material, but the increase was not sufficient to neutralise the abnormal rise in the prices of raw materials. It has also been stated that to control the rise in prices, the domestic industry had gone in for investment in plant as a measure towards backward integration. It has been argued that it was *"the combined effects of rise in prices internationally which was further exacerbated by anti-dumping duty on met coke that has resulted in the abnormal purchase prices that the domestic manufactures of Domestic Industry pipes have had to pay. This has lead to increased costs of manufacture and consequently slightly decreased profit margins."* It has further been argued that *"in fact the petitioners do not even mention imports as a cause for the decrease in profits in any of their published documents and are attributing injury as a result of imports for the first time in their petition before the DAGD."*

27. The Authority notes that M/s Jindal Saw Ltd. was not manufacturing the D I Pipes in the period referred in the annual reports and GDR offer documents. In absence of any competition, there was no reason for the domestic industry to not to pass the increased cost of manufacturing to the consumer except that the domestic industry was benchmarking their selling price with that of imports, therefore, the domestic industry could not increase the selling price in proportion to the increase in cost of production indicating very clearly that prices were suppressed because of the low priced imports. XDIPL has argued that the domestic industry had not indicated about imports as cause of concern, however, the Authority notes that Electrosteel Castings Ltd. in its annual report 2004-05 stated that *"the main threat to company is cheap imports from neighbouring Asian countries with the opening of the economy and continued reduction in imports duty"*.

E. Methodology for calculation of dumping margin and examination of market economy

E.1. Non-Market Economy & Normal Value

E.2. Submissions by the Domestic industry

28. After placing reliance on para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the Applicants submitted that China is required to be considered as non-market economy country and the normal value be determined accordingly unless any Chinese exporter is granted market economy status in terms of para 8 of the said Annexure.

29. The Applicants further submitted that the normal value be determined on the basis of the prices in the third country market economy. The Applicants proposed Spain and France as appropriate third country market economy and provided

reasons in support thereof. The Applicants also opposed the proposal of XDIPL to select Malaysia as the appropriate third country market economy on the grounds of difference in the production process, incomparable capacities and size of operations.

30. With regard to the claim of market economy status by XDIPL in terms of paragraph 8(3), it has been submitted by the domestic industry that the said exporter is not entitled to MES as they have failed to substantiate their claim the onus of which is on the exporter. Further, XDIPL is a State owned company where majority of the directors are government nominees. The exporter has not produced any evidence that there is no significant state interference or that the factors of production like raw material prices, utilities, etc. are not influenced by the State. In the Accession Treaty with the WTO, China has accepted that there is State interference in the coal market which is also being subsidized against losses. It was also submitted by the domestic industry that the Designated Authority should investigate the social security system and other subsidies being offered by the Chinese government, as has been done in the past cases. Further, the fact that the exchange rate is fixed over considerable period of time is also indicative of hidden subsidies to the exporters demonstrating non-market economy status of the Chinese market.

E.3. Submissions by M/s Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. (XDIPL)

31. XDIPL was constituted in 1997 as a public listed company. Till November 9, 2005, the shareholding of XDIPL was as follows: 64.78% was held by the Group Company and 35.22% of the shares were held by the public. The 35.22% were freely tradable at the stock exchange, and 64.78% of the Group Company's shares could be transferred through negotiated transfers. On November 9, 2005, in giving effect to the equity allocation reform- a practice described in our replies to the Hon'ble DGAD's queries, the Group Company's holding was reduced to 54.2%, and the balance 10.58% of its shares were distributed among the existing shareholders. The 54.2% of the shares of XDIPL can now be freely traded through the Centralised billing transaction system of Shenzhen Stock Exchange, subject to certain conditions discussed in our reply.

32. It is of importance to note that as a shareholder of 64%, and now 54% of the shares, the Group Company is prohibited from exercising control over the operation of XDIPL, through several safeguards in the Company Law, the Rules of the Stock Exchange and its own Articles of Association. These provisions curtail and regulate the powers of the majority shareholders, in order to ensure independent functioning of the company on market principles.

33. As a public listed company, XDIPL is required to undertake several measures under law in order to ensure that its majority shareholder does not exercise undue control over the company and that XDIPL operates independently on economic principles. The key provisions are as under:

- The Articles of Association (AOA) requires the controlling shareholder to refrain from undermining the rights of XDIPL and other shareholders, and provides relevant remedies.
- The AOA require that an interested shareholder and interested director shall not participate in respect of voting for affiliated transaction.

- The company sets up the position of independent directors, the number of which shall be no less than one third of the total number of directors. The independent directors shall not bear any relation to the company's major shareholders, and has been endowed with veto in respect of the matters such as a significant affiliated transaction.
- In respect of a Significant Affiliated Transaction, i.e., one in which the total transaction amount reached between the company and the affiliated person is over RMB 30 million Yuan, and over 5% of the value of net assets of the latest auditing of the company. All such transactions are required to be recognised by the independent director before being submitted to the board of directors for discussion. The independent director may hire an intermediate organisation to issue independent financial statements for enabling a decision by the independent director.
- Article 109 of the AOA requires an independent opinion from the independent director on several significant matters of the company.
- The Company Law of China requires that shareholders of a company shall not abuse their rights to injure the interests of the company or of other shareholders. They are required to act in the interests of the company, and not its shareholders. In case of default such shareholder is liable to pay compensation.
- Chapter IX of the Rules governing Listing of Shares at the Stock Exchange provides that no related director shall be a party to the discussions involving a related party transaction and that under certain circumstances these transactions shall be subject to the approval of the shareholders. Listed companies are also mandated to disclose the details of all related part transactions.
- Listed companies are also governed by the Code for Corporate Governance, which mandate prudent transparent behaviour, and specifically mandate, among other aspects that the controlling shareholder is also forbidden from interfering in the decisions of the company and is also directed to respect the financial independence of the company.

34. In addition to the above, it is also important to note that the Articles of Association of the Group Company has several provisions mandating that the Group Company shall not interfere in the operations of the subsidiaries. Some key provisions in Article 16 include the following:

- As independent legal persons, the subsidiaries have independent rights over its properties, enjoy civil right, assume civil liability, and operate independently and ensure the maintenance and increment of state owned asset in accordance with laws.
- The subsidiaries are entitled to make decisions on plan, stocking, sale, pricing, human resource, distribution and organisation set up and other and carry on three system reformations, settle superfluous stuff and cut off the social function of the company.
- The relation among the subsidiaries is managed in accordance with the principles of market and the activities are regulated by signed contracts.

35. It is also important to note that the Group Company is a profitable venture. The Group Company's profitability is clearly borne out in the data presented in its

balance sheet and income statements on December 31, 2005, where the cash and cash equivalents of XDIPL Group is stated to be RMB *** million Yuan, total assets is *** million Yuan and the profit is *** million Yuan.

36. XDIPL further submits that mere shareholding pattern cannot be considered an indicator of market economy status. In fact, many of India's public sector undertakings that have state shareholding, operate on pure market principles. Similarly, the law governing companies in most jurisdictions allow for restrictions on transferability of shares, especially for private companies, and such restrictions do not impact the operation of the company on market principles.

37. With reference to raw material prices it has been submitted that XDIPL has a strict purchasing system, and purchases all raw materials and supplies required for its operations from suppliers selected after careful comparison of prices, and negotiations, and often through a public bidding system. The company does not depend on any one supplier for any kind of raw material. It always chooses the best supplier from among three or more than three suppliers by inquiring the price and comparing the functions of the product in the market.

38. The critical factors that XDIPL looks for in its suppliers is price and functions of the product. In order to identify and retain the best supplier, XDIPL uses many measures, such as bidding to eliminate any incompetent supplier. The supplier selected through bidding enters into contract of supply for a limited period of time, and there is no guarantee that such supplier will be selected under the next bid. There is no assurance for a long time contract of supply, and no exclusive supplier for any raw material. Purchase of raw material is strictly done only through the bidding process.

39. Regarding utilities, it has been submitted that XDIPL purchases electricity at commercial rates which establishes that XDIPL pays commercial rates for electricity. XDIPL procures coal from the open market at competitive rates. The Chinese government currently does not have restrictions on the prices of coal and coke for metallurgical use. Regarding export quota it has been stated in 2005 the export quota for coke was 14,000,000 metric tonnes while the actual export was 12,000,000 tonnes, therefore, the quota for coke have not restricted exports. The prices of coal and coke fluctuate along with the demand and supply. For instance, the market price in 2005 increased more than 40% compared with that in 2003. Moreover, it is important to note that the price of coke in Chinese domestic market is very similar to that of international market and the export quota for coke does not affect the exports.

40. Regarding foreign exchange rates in China, it has been submitted that the foreign exchange practice in China prior to July 2005 was that of a managed exchange rate regime. Under this system the Bank of China would determine the exchange rate based on the foreign currency rates, and ensure that the exchange rate was maintained at a steady level. Thus, status in China is best described as being maintained at a steady state, rather as being fixed by the Government. From July 21, 2005 as has been the case with many other countries, China adopted a managed floating currency regime based on market demand and supply by referencing the market currency. Market forces therefore play a greater role in determining the exchange rate.

41. Regarding surrogate country, XDIPL has raised objection about the proposal of the domestic industry to choose Spain or France as 'an appropriate market economy third country' on the ground that the economic development between these two countries and China are not comparable. Cost of key raw materials in Spain are higher than that of China. Spanish producer has to buy pig iron and then convert it into liquid iron for casting of the pipes whereas XDIPL has its own melting plant from where the liquid material is directly transferred to blast furnace for casting it into pipes. Cost of labour and electricity in Spain is much higher than that of China. The exporter has proposed Malaysia as an appropriate market economy third country.

E.4. Examination of Market Economy Treatment of Response submitted by M/s Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd.

42. The Designated Authority, as per para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules for the purpose of assessing the normal value proceeded with the presumption that any country that has been determined to be or has been treated as a non-market economy for the purposes of anti-dumping investigations by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three years period preceding the investigation is a non-market economy country. In the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by WTO members such as EU and USA. In the instant case China PR was proposed to be investigated as a non-market economy country.

43. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

44. The Authority sent copies of the questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value. Response has been received from

one producer/exporter M/s Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. (XDIPL) and the company has claimed Market Economy Treatment (MET).

45. It has been stated by the exporter that Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. (XDIPL) is a joint stock company organised and existing under the Corporation Laws of People's Republic of China. It has also been stated that Xinxing Ductile Iron Pipes (Group) Company ('Group' company) is a holding company of XDIPL. The Group company currently holds 54% shares of XDIPL (during the verification it was pointed out that as on 31.12.2006, 50.04% of shares were held by the Group company.) Further it was stated that XDIPL has three subsidiaries namely (a) Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes Co., (b) Hebei Xinxing Ductile Iron Pipes Co. and (c) Shijiazhuang Xinxing Ductile Iron Pipes Co. In the subsidiaries apart from XDIPL, Group company, Shijiazhuang factory and English Realtime Profits Ltd. also hold shares, however, majority shares are held by XDIPL. (During the verification it was found that Shijiazhuang Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd was closed. After the verification it was informed that because of higher cost of production the manufacturing activity of the company was stopped from June 2006.)

46. The Group company is a state-owned company with limited liability. 100% of its shareholding vests in the State-owned Assets Supervision and Administration Commission. The Group company was established on Jan. 8, 1997 in pursuant to *Notification for Printing & Promulgating the Implementation Planning and the Overall Disposal Opinion concerning the Safeguard Enterprises Transferred by the Army* (C.J.[2001] No.4) promulgated by the joint meeting of the army safeguard enterprises hand-over and take-over affaires group, and the "Approval for the Operation and Management of Xinxing Ductile Iron Pipes (Group) Co. Ltd." (L.A. [2001] No.368) issued by the General Logistics Department of the The Chinese People's Liberation Army, the enterprises and the other military supply entities directly managed by the military supply branch and the Qingzang army service station of the General Logistics Department were transferred to Xinxing Ductile Iron Pipes (Group) Co. Ltd., whose name, at the same time, was changed into Xinxing Ductile Iron Pipes Group Co. Ltd.. As per Article 11 of Article of Association the business scope of the company *inter alia* include operation and management of the subsidiaries and the affiliates of the company and production and sale of ductile iron pipes, compound pipe and its fittings, engineering machine and other mechanical equipment, textile, clothes, leather and shoe leather, production and sale of rubber product.

47. As per Article 2 of the Interim Regulations on Supervision and Management of State-owned Assets of Enterprises Decree of the State Council of the People's

48. Republic of China No.378 ('Regulations'), the 'Regulations' is applicable to *inter alia* State-owned holding enterprises and enterprises with the State-owned equity. The Article 3 of the Regulations define the term "State-owned assets of enterprises" as all forms of State investments in enterprises and the equities generated therefrom, as well as other equities which are legally determined to be owned by the State. These Articles indicate that the above mentioned regulations apply to both the 'Group' company and XDIPL. 'Group' is 100% owned by the State whereas XDIPL more than 50% of equity is held by the State through 'Group'.

49. During on the spot verification, it was stated by the exporter that the above said Regulations is not applicable to XDIPL instead the Company Law of China PR is

applicable to the company. However, the regulations very clearly state that it is applicable to State-owned enterprises and enterprises with the State-owned equity. In this case in XDIPL more than 50% equity is held by the State through 'Group'.

50. It has also been argued that 'Group' company is prohibited from excising control over operation of XDIPL through several safeguards in the company law, the rules of the stock exchange and its own Article of Association. These provisions curtail and regulate the powers of majority shareholders, in order to ensure independent functioning of the company on market principles.

51. The Authority, however, notes that followings relevant excerpts of Articles from Articles of Regulations indicate how State can supervise and interfere in the management of the company and company cannot be liquidated:-

Article 11 - The invested enterprises shall accept the supervision and administration conducted by the State-owned assets supervision and administration authority according to law, and shall not harm the legitimate rights and interests enjoyed by the owner of State-owned assets of enterprises and other investors.

Article 13 -(4) appoint or remove the responsible persons of the invested enterprises and evaluate their performance in accordance with the statutory procedures, and grant rewards or impose punishments based on the evaluation results;

(6) formulate rules and systems on State-owned assets supervision and administration of enterprises.

Article 14 - (1)..... propel the adjustment of the layout and structure of the State economy;

(6).....offer guidance and coordination to State-owned enterprises

Article 16 - selecting and appointing the responsible persons of enterprises and the mechanism of incentives and restraints that meet the requirements of modern enterprise system.

Article 17 - to appoint or remove, the responsible persons of its invested enterprises

(3) nominate the candidate for the director of the board

(4) nominate the candidate for the director of the board or supervisor to be dispatched to a company with State-owned equity according to the company's articles of association.

Article 18 -establish a system for evaluating the performance of the responsible persons of enterprises

Article 19 -determine the remuneration of, grant rewards to or impose punishments

Article 21 – The state-owned assets supervision and administration authority decides such major matters as the division/merger, bankruptcy, dissolution, capital increase or decrease, or issue of company bonds of wholly State-owned enterprises or wholly

Article 22 -appoint representatives of shareholders.voice their opinions and exercise the right to vote according to the instructions of the State-owned assets supervision and administration authority

Article 26 -guideline for the remuneration system

52. The company was asked to explain the selection process of the Directors. It was informed that in all there are 9 directors of XDPL of which 3 are recommended by the 'Group', 3 represent the public shareholders and 3 are independent directors. All directors are elected by general body meeting (GBM). It was also explained that the outgoing board of directors recommend the names of 3 directors to be represented by the public for election in the GBM. The 6 directors recommend the names of 3 independent directors. The Authority also notes that the top 10 public shareholders hold less than 1% shares individually. Shareholders holding less than 1% of shares cannot nominate any candidate for directors. Interestingly, the directors representing the public did not change from 2000 to 2006. It has also been observed from Annual Report of XDPL that many directors of the company were simultaneously functionaries in 'Group', XDPL and subsidiaries. From the selection process it is apparent that all the directors are either nominee of the 'Group' or nominated by nominee directors of the 'Group'. As informed by the company, the 6 directors representing the 'Group' and 'public' are functional directors. The post of Chairman and General Manager of the company are discharged by directors representing the 'Group'. In addition to 6 functional directors, 9 more functionaries were shown as heads of departments, however, their designations and hierarchies could not be explained. After the verification, a document was sent along with the verification papers showing appointment of some functionaries. However, their designations and hierarchies still remain unclear.

53. The company was asked to explain the decision-making process regarding pricing for exports and home sales. Neither such a process could be explained nor any documentary evidence in the form of minutes was shown to the verification team.

54. The company has received export subsidies as indicated in their Annual Report 2005 of the company. The subsidy has been explained as an income sourced from the finance industrial award fund received by the company's shareholding subsidiary, Wuhu Xinxing and income obtained on the basis that the Wuhu Government encourages Wuhu Xinxing for the R&D of seamless iron pipes with larger calibre. During the on the spot verification, at the company's subsidiary at Wuhu, no such R&D centre could be seen.

55. It was noticed from the annual report for the year 2005 that a substantial amount was payable to the 'Group'. It was explained that this amount was long term amount payable to the 'Group' and there was 'no need to pay the financial charges for these outstandings'.

56. Raw material Coke is under the export control of the Government. In this regard it has been explained that at present the Chinese government still imposes export quotas for coke. However, since the price of coke in Chinese domestic market is very similar to that of international market, the export quotas for coke does not affect the export. It has been explained that in 2005, the export quotas for coke was 14,000,000MT, while the actual export was 12,000,000MT. It has also been explained that the market price of Coal & Coke for metallurgical use in 2005 increased more than 40% compared with that of 2003 and the price of coke exported from China PR in 2005 was about US\$140-150 per tonne c.i.f.

57. While analysing the injury to the domestic industry the exporter has relied on the information provided in GDR offer wherein Electrosteel has stated that the prices of LAMC has increased considerably from 2003 to 2005. In 2003, the price was US\$ 166.4/MT whereas in 2005 the price was US\$354.8/MT. However, while disputing the non-market economy claim the exporter has disputed the claim of the domestic industry that Met Coke was being sold by the Chinese Government to the domestic manufacturers in China at US\$80-100 per MT whereas international price of coke was above US\$ 400 per MT.

58. The Authority holds that in view of the export quota for Coke the prices of Metallurgical coke in China cannot reflect the prices as per the market principles. (At present there is an anti-dumping duty in India on Met Coke from China PR)

59. Keeping in view the provisions of the above mentioned 'Regulations' applicable to 'Group' and XDIPL concerning interference by the State, selection process of directors, lack of evidence about decision making about prices in accordance with market principles, export subsidies, export control on key raw material, the Authority holds that the presumption of non-market economy by XDIPL has not been rebutted.

E.5. Normal Value

60. In view of the failure of the cooperating exporter to rebut the presumption of non-market economy, the Authority is unable to apply the principles set out in paragraph 1 to 6 of Annexure 1 for determination of normal value for the Chinese exporters. Therefore, the normal value in respect of all exporters/producers from China PR is determined as per Rules relating to non-market economy as contained in para 7 of Annexure 1 of AD Rules.

61. As per para 7 of Annexure 1 of AD Rules, the Authority is required to determine normal value on the basis of 'price or constructed value in the market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product.'

62. At the time of initiation, the domestic industry had proposed Spain and France as appropriate market economy third country for determination of normal value. The cooperating exporter and importer opposed the selection of Spain and France as appropriate market economy third country on grounds *inter alia* development of China PR and Spain and France are not comparable. The cooperating exporter suggested

instead Malaysia as appropriate market economy third country. The Authority selected Malaysia as appropriate market economy third country and requested producers in Malaysia (names of producers were suggested by the exporter and domestic industry) to provide information for determination of normal value in Malaysia. No producer from Malaysia responded to the letters of Authority and provided any information. The Authority, therefore, is not in a position to determine normal value in market economy third country.

63. The imports from other country for the subject goods is nil during the period of investigation, therefore, the export price from third country to India is also not available. The Authority, therefore, in absence of any other option, has determined the normal value by resorting to method 'any other reasonable basis'.

E.6. Normal Value for China

64. Under the circumstances, the authority has constructed the normal value by considering the raw materials for manufacture of D I Pipes at the international prices, the consumption norms of the cooperating exporter, utility and other costs of the efficient producer of the domestic industry. A reasonable profit @ 5% has been added for determination of normal value. Based on above information available, the normal value has been calculated USD ***/MT. by considering the average exchange rate during POI of 1USD=44.27

E.7. Export Price for M/s Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd.

65. It has been contended by the exporter that DI pipes are sold grade-wise as a pipe of certain grade is used for some specific purpose. The cost of production differs significantly between smaller and larger grade of DI pipes. It has also been stated that XDIPL has not exported all grades that it produces and exports have been restricted to certain grades namely, DM 250, 300, 350, 450, 500 and 600. It has been contended that dumping margin first be calculated grade-wise. In this regard, the Authority has examined the per unit prices of the exports made by XDIPL. The per piece price differs significantly depending upon the diameter, however, in terms of unit of weight, variation of the average prices ranges plus-minus 1%. As there is no significant difference in the per unit prices of the product in terms of weight, therefore, the weighted average export price has been determined of all exports.

66. The exporter has provided information about two export transactions to India during the period of investigation. One transaction has been sent directly to India to importer M/s J V Gokal & Co. In the second export transaction, the shipment has been sent directly by the exporter to India, however, the export invoice was made in the name of M/s Kingsburg Exports Ltd., Hong Kong. M/s Kingsburg Exports Ltd. has in turn made the invoice for importer M/s J V Gokal & Co. The export price by M/s Xinxing to Kingsburg and from Kingsburg to importer are same. M/s Xinxing stated that transaction between and Kingsburg were on principal to principal basis.

67. The exporter while filing response to Exporter's Questionnaire had submitted a contract agreement in which M/s Kingsburg Exports Ltd., Hong Kong had stated, on stamp paper, to an Authority in India that it is the sole authorised agent for M/s Xinxing DI Pipe (Group) PRC in India. The exporter was asked to explain how a transaction

was made on principal to principal basis when the supplier had submitted before an Authority in India that he is an authorised agent for the exporter. In reply, it was stated that the submission by Kingsburg was made without their knowledge. However, no document disputing the claim of M/s Kingsburg about his being sole authorised agent was shown by the exporter nor any other documents have been shown restraining Kingsburg from claiming it to be their sole authorised agent in India. It has also been noticed that the exporter is operating in India from the office of importer M/s J V Gokal & Co. It has also been stated by the exporter that no payment etc. are being made to importer for using their facility in India.

68. The Authority in view of the documents available is unable to accept the claim of the exporter that the transaction to Kingsburg was made on principal to principal basis particularly keeping in view the sale price at which M/s Kingsburg had exported the goods to M/s J V Gokal & Co. being the same as that of its purchase price from XDIPL. The transaction of export through Kingsburg has been made to India, therefore, this transaction has also been taken into account by deducting commission @5% to determine the ex-factory export price.

69. During on the spot verification, for export sales, the exporter had not shown any original documents relating to expenses concerning domestic freight, forwarding agent, accessories, overseas freight, overseas insurance, credit cost, quality inspection. For home sales transactions, not even a single transaction could be verified from the original records. Subsequently, certain invoices of home sales were submitted showing the comparison of sales prices of XDIPL and other Chinese pipe producers. However, these invoices cannot be considered to have been verified from the original records.

70. The transaction-wise details have been relied upon to determine weighted average export price. The expenses on account of inland freight, insurance, overseas freight, difference on account of VAT payment and value of accessories as provided by exporter has been adjusted to determine the ex-factory weighted average export price. The ex-factory weighted average export price has been calculated as US\$*** per MT.

E.8. Export Price for China for Non-cooperating Exporters

71. For the purpose of determining export price for non-cooperating exporters, the transaction-wise details provided by IBIS has been relied upon. The adjustment for expenses as claimed by the cooperating exporter has been relied upon to determine the ex-factory export price. With the disclosure statement (e-copy), calculation pertaining to expenses for adjustments was also forwarded to the exporter in which adjustment for VAT was calculated on the basis of data (e-copy) provided by the exporter. After the disclosure statement, it was pointed out that wrong adjustment pertaining to VAT has been taken, however, no calculation has been sent to the Authority pointing out the mistake. It is not clear how the wrong calculation has been made when data provided by the exporter has been relied upon for making the calculation. Therefore, the calculation made earlier and sent to the exporter has been relied upon for calculating the ex-factory export price.

72. During POI the CIF value of export price was US\$***/MT. After making adjustments on account of inland freight and insurance as US\$***/MT, ocean freight and insurance as US\$ ***/MT, accessories as US\$ ***/MT and difference on account of VAT payment as US\$ ***/MT the ex-factory export price has been calculated as US\$ ***/MT (1 US\$ = Rs.44.27/- during the POI).

E.9. Dumping Margin

73. Based on the normal value and export price as determined above, the Authority determined the dumping margin as under:

Dumping Margin

Exporter/Producer	Normal Value USD/MT	Export Price USD/MT	Dumping Margin USD/MT
	***	***	***
Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd	***	***	49.11%
Other Exporters from China PR	***	***	53.44%

The above determined dumping margin is more than *de minimis*.

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINKS**Submissions on Injury Analysis****F.1. Views of the domestic industry****Volume of Imports**

74. It has been submitted that imports from China have come under two distinct categories during the entire injury investigation period. Substantial quantities of imports have come duty free under Custom Notification No.84/1997 dated 11.11.97. The benefit of this custom notification is specifically granted to project financed by international organisations like ADB/World Bank. The demand against such projects is sporadic. This explains as to why the industry saw spurt in demand in 2004-05 which came down to its normal level. There was no project financed by such organisations. It has been requested that Authority may consider appropriate to exclude the imports made without payment of custom duties for the purpose of injury analysis.

75. It has also been submitted that volume of imports may be assessed by taking into account volume of imports reported in all tenders for shipment have already been made and reached India within investigation period. In addition to that, volume of imports of all tenders for which shipment were not made within POI but supply have been made after the POI, volume of imports reported in all tenders for which shipment were not made but supplies would be made in due course, volume imports reported in all tenders for which orders have not been finalised as yet, but Chinese producers have already quoted lower prices and are likely to receive the orders, volume imports reported in all tenders for which orders have not been finalised as yet and price negotiations are in process with bidders.

76. It has been submitted that export price should be computed after taking into account the actual physical imports during the period of investigation as well as the

prices of those consignments for which the contracts have been completed during the POI and also the contracts for which the Chinese exporters have offered their quotes.

77. It has been submitted that market for DI pipes is peculiar in terms of pricing as well as the delivery schedule. There is a considerable gap between the time of the tender negotiation, date of placement of the orders and the final deliveries. The domestic industry has already submitted documents which indicate that the typical time lag from the date of the order and the final delivery varies between 6 to 12 months. Therefore, the fact that the actual imports during the POI may have marginally dropped over the preceding period is not of much significance. It is clear from the documentary evidence submitted by the domestic industry that substantial orders have been placed for the Chinese goods during the POI and for supplies after the POI. In such a situation, the Authority must take an overview of the imports during the injury investigation period. The fact of significant orders having been placed for Chinese pipes during the POI is indicative of significant potential imports and also threat of injury.

78. It has been submitted that Domestic Industry has lost a number of contracts to the exporters from China. In a number of cases, prices offered by the Chinese producers were lower than the prices offered by the Indian producers. Consequently, in some of these cases, the petitioners have been forced to lower the prices in order to get these orders. However, in spite of domestic industry lowering prices, orders for supply of material have not been given to the petitioners and it is understood that the Chinese producers have either already lowered the prices or negotiations are underway with them. Petitioner is afraid it is likely to lose some of these sales.

79. In respect of the Global Depository Receipts (GDR) of ECL, it has been submitted that the present investigations are restricted to product under consideration. They have further submitted that the injury determination is for the domestic industry as a whole under Annexure II and not in respect of any one of the constituents of the domestic industry. They claimed that petition that was filed was for the domestic industry as a whole and GDR averments were relating to ECL only that too for the company as a whole and not for product under consideration. Hence, according to the domestic industry Xinxing was attempting to mislead the Authority it attempted to compare incomparable. They further pointed out that the statements made in GDR offer document were in respect of ECL's overall operations and not for the product under consideration alone. Xinxing's reliance on the extract from the GDR offer document is also misplaced as the GDR offer document itself in unambiguous terms refers to information prior to 31st March 2005 and not for period of investigation. No details about the import quantity or value or price of subject goods supplied by Xinxing have been quoted or referred to in the GDR offer document for the period of investigation chosen for the present investigation. In view thereof, it is clear that the statement contained therein about XDIPL cannot be attributed to the period of investigation. The statement that the experience of ECL cannot be easily replicated by competitors is not a statement made in the context of injury but in the context of producers setting up operations in India. Further, there is no indication that the company is of the view that they can face even unfair competition.

. Causal Link

80. Substantial orders have been placed for the Chinese goods during the POI and for supplies after the POI, which is indicative of significant potential imports and also threat of injury. The domestic submitted that their case industry is fully supported by the decision of the Hon'ble CESTAT in the case of Lubrizol (India) Pvt. Ltd. Vs. Designated Authority, the relevant excerpts of which are reproduced below:

"The tender which was floated by the IOC was opened during the period of investigation on 19-7-2001. The export prices quoted by the exporters for procurement of 5200 MTs of the subject product were much lower than the NIP and the prices offered by the domestic industry. Since the tenders were opened during the period of investigation disclosing 'dumped' prices at which the exporters committed to offer the goods, the domestic industry was injured not only by loss of contract but there arose a real threat of material injury which also is to be considered as "injury", as defined in the opening part of Annexure II to the rules. Since such threat of injury became a real, in view of the firm offers made below the non-injurious price in the tenders by the exporters, the Designated Authority rightly took that aspect into consideration in paragraph F(6)(iii) of the final findings along with the other relevant factors."

81. Substantial offers were made to the tune of over 26000 MT for supply of Chinese pipes in the Indian market during the POI, which ultimately culminated in their favour.

82. China accounted for 100% of the total imports into India throughout the injury investigation period. This is indicative of the aggressive pricing policy being followed by the Chinese exporters to gain a foothold in the Indian market. The trend is the same whether the duty-free imports are included or excluded.

83. The share of imports from China in comparison to the total demand and domestic production has also increased. The share of duty paid dumped imports as compared to the total domestic demand has gone up.

84. The ratio of duty paid imports from China as compared to the total production, has also increased in the POI as compared to in the base year.

85. While the selling price per MT has gone up during the POI as compared to the year 2002-2003, the increase in costs per MT is much higher indicating that the domestic selling prices have been suppressed during the period of investigation.

86. While the costs and resulting prices of the domestic industry had been going up, the landed value of imports has been showing a downward trend.

87. There is significant price undercutting and price underselling during the period of investigation.

88. The sales value in absolute terms has gone up in the year 2004-2005 and then fallen in the POI.

89. The market share of the domestic industry has declined during the period of investigation.
90. While the production, capacity as well as the capacity utilization has also gone up this increase has to be seen in the context of the industry losing its market share in a growing market where selling prices are also falling as a consequence of dumped imports.
91. The domestic industry has suffered significant loss of profits during the POI. The profit of the domestic industry has fallen to one third during the POI as compared to the base year of 2002-2003. Thus, it is clear that the Chinese imports have affected the profitability of the domestic industry in a serious manner, which is an important indicator of material injury.
92. The Return on Capital Employed (ROCE) of the domestic industry has also shows a drastic decline to about on fifth in the POI compared to the base year.
93. The average inventories of the domestic industry in absolute terms as well as in terms of number of days have increased over the injury investigation period and the cash flow position has also deteriorated, clearly showing injury to the domestic industry.
94. According to the estimated provided by the Applicants, there is a significant dumping margin.
95. Other factors like growth and ability to raise capital also show injury to the domestic industry.
96. The domestic industry has submitted documents indicating several instances of lost contracts during the period of investigation as well as in the Pre-POI period. During the POI, the domestic industry lost a huge contract of 26238 MT for supplies to be made to Kerala Water Authority (KWA) through L&T and Subhash Projects & Marketing Ltd. This contract was lost only on account of the lower prices offered by the Chinese exporter as per the documentary evidence submitted by the domestic industry. The domestic industry has also submitted that besides losing contracts for substantial quantities to the Chinese exporters, they further lost the Rate Contract also with Maharashtra Jeewan Pradhikaran (MJP). The Rate Contract was also lost to Chinese exporters (through JV Gokal & Co.).
97. In the face of substantial loss of contracts, the domestic industry was compelled to reduce its prices for other contracts as well to ensure that they do not lose further contracts even though this meant a substantial loss of profitability to the industry.
98. With regard to the argument raised by the exporter from China that the domestic industry has been suffering on account of inter se competition, it has been submitted that even after the sales of JSL are added, the domestic industry as a whole has lost sales to the dumped imports. Therefore, the injury of the domestic industry cannot be attributed to inter se competition. The domestic industry has submitted documentary evidence relating to some of the tenders which show that

substantial offers were made by or on behalf of XDIPL during the POI. These documents prove beyond doubt that the domestic industry has been forced to match the Chinese prices.

F.2. Submissions by XDIPL

Submissions in respect of Injury

99. Regarding contention of the domestic industry that all imports for ADB and World Bank funded projects should be excluded as they are rare and demand sporadic. In this regard, it has been stated that this contention is contrary to statement in GDR and FCCB offer document where they have stated that "several infrastructure development projects initiated by international and multilateral development finance institutions such as the World Bank and the ADB have resulted in an increased demand for the company's DI pipe products." It has also been argued that if petitioners are demanding that imports for projects funded by international organisations be excluded from injury analysis, it also means that they admit that supplies of pipes for internationally funded projects are not injuring them. Further as the aforesaid submissions indicate, even exports for non-internationally funded projects are not injuring the domestic industry.

100. ECL has not disclosed the issuance of Global Depository Receipts (GDR) to and the accompanying GDR Offer Document provided to foreign investors. This is a material fact going to the root of the allegations of injury and ECL intentionally concealed this important document from the DGAD because it establishes beyond doubt that ECL was not facing injury of any kind from China in general and Xinxing in particular during the POI.

101. It has been pointed out that there are several statements made in the GDR document where ECL has stated repeatedly that it is the market leader and it faces no threat from any source domestic or foreign.

102. ECL has specifically mentioned Xinxing and assured its investors that Xinxing's imports into India are not capable of having any impact on ECL's sales. The text is quoted below:

- "With regard to the domestic market, Xinxing supplied approximately 10,000 tons of DI pipes to India during the financial year ended 31st March 2005 but has yet to make a significant impact on the Indian market"
- The company believes that the extensive experience of its management combined with its 45 year history as a spun pipe manufacturer in India cannot be easily replicated by competitors or new entrants into the domestic market"

103. It was ECL's intention to raise 38.32 million USD from this GDR issue to fund its extensive capital expenditure. However, it raised USD 40 million. It is worth considering whether a company that is making losses can have the confidence to convince investors to invest in it and raise USD 40 million from such investment. It is also shocking that after having raised USD 40 million through its GDR issue, the ECL alleges in the Petition that it is unable to raise capital.

104. It has been pointed that petition's data of falling sales it unreliable. The petitioners fall in profit cannot be attributed to imports by Xinxing and are solely attributable to a meteoric rise in raw material prices. The GDR Offer Document states that the Company's PBDITM (profit before depreciation, interest and taxation margin) was 18.3%, 20.0% and 25.7%, for 31 March 2005, 2004 and 2003 respectively. It further explains that the PBDITM decreased during the period of financial years 2003 to 2005 primarily due to increases in the cost of raw materials, which have outweighed the greater margins realised by the Group's move away from DI pipe production.

105. The rise in raw material cost was so significant that it rose by 50% in 2004-05 as compared with previous year. A significant raw material is coking coal and prices of Goonyella hard coking coal price increased from USD 46 to USD 126 which is an increase of 173%. Similarly, there was an increase in iron ore prices from \$18 in 2003 to \$36 in 2005. In the 3 months ended June 2005 the price was at it was \$48. The company also experienced rises in prices of MS Scrap and Electricity. The company itself admits that this downward trend is primarily due to increases in the cost of raw materials.

106. It has been pointed out that the record shows that ECL did increase prices to counter rise in raw material costs however this rise in prices of DI pipes was not enough to counter rise in raw material cost. This has been admitted to in 2004-05 and 2003-04 annual reports which are reproduced below:

Annual Report 2004-05 at pg 14

"The year gone by witnessed high volatility in the price of imported coke which had major impact on the profit margins."

"apart from the increase in sale, the turnover has increased due to increase in selling price to partially off set the abnormal increase in coke price."

Annual Report 2003-04 at page 15

"Your company has effected an increase in prices of DI pipes, but this increase neutralise the increase in the price of imported coke, unless the artificial increase comes down to realistic levels. The hope of early reduction in the prices have been belied and there are no indications at present to this effect."

GDR offer document at pg.69

"PBDITM has decreased during the period of financial years 2003 to 2005. This downward trend is primarily due to increases in the cost of raw materials, which have outweighed the greater margins realised by the Group's move away from CI pipe production. As the cost increases associated with raw materials have not been reflected by corresponding increases in the Group's finished products, they have had a significant impact on the Group's profitability."

107. Regarding increase in capacities, it has been pointed out that ECL has commissioned 5 plants in 2005 and expansion was so expensive that ECL incurred capital expenditure at Rs.3 billion and Rs.100 million per year ended March 2006-07. "It is also intriguing that petitioners have installed most their new plants during the POI. This fact alone establishes that imports from China have not in any manner

hindered the extensive growth of the Petitioners or caused any injury to the petitioners.”

108. The production of DI pipes of the domestic industry has increased consistently from 2002-03 to 2004-05. Any alleged drop in production is attributable to the closure of mini blast furnace.

109. The data submitted by petitioner themselves proves that imports from China have fallen in both absolutely and also relatively to production and consumption. Market share constituted by imports is negligible, as it constitutes only 2.56% of total market share. The market share of imports have fallen to 2.56% of production, Jindal's production at the same time has increased to 30% and petitioners market share fell to 67% from 92%. Thus loss of market share of the petitioners coincided with market entry of Jindal. The fall of market share of Chinese imports and the coincidental rise in market share of Jindal establishes that imports are not the reason for any alleged injury to the petitioners.

Loss of Contract

110. Electrosteel has raised a false alarm in the nature of “loss of contracts” for the Kerala Water Authority project. While Electrosteel has cried hoarse about the fact that XDIPL secured an order from L&T and Subhash for supply of 25,000 MT of DI pipes for the KWA project, it has failed to mention that it too supplied 30,000 MT of DI pipes for the same project. Their tender too was opened during the POI, so they too knew that in the coming year they would be supplying 30,000 MT of DI pipes to KWA. In this scenario, how is there loss of contracts?

111. Further any claims that Electrosteel had to reduce its prices on account of XDIPL for the supply of 30,000 MT is false because XDIPL does not even submit price bids to contractors for “local competitive bidding” tenders. Thus Electrosteel bid and supplied these pipes knowing fully well that XDIPL is not even in contention.

112. The only reason that L&T and Subhash procured pipes from XDIPL is on account of their quick delivery time (9 months as against Electrosteel's 18 months) and the absence of a price escalation clause in XDIPL's contract. Thus, XDIPL secured the contracts because Electrosteel cannot supply pipes on time which is a crucial requirement in all internationally funded projects.

113. On the issue of lost contracts, XDIPL would like to submit that Electrosteel and Lanco have intentionally withheld information pertaining to other tenders either opened or awarded during the POI, which were awarded to Electrosteel and Lanco and which proves that their claim of “lost contracts” bears no merit whatsoever. The list of such tenders is provided below:

1. PRED-Jal Nirmal Projects-Bijapur district (Qty. 5318 MT)
2. Kerala Water Authority (Qty. 3122 MT)
3. Mangalore Municipal Corporation (Qty. 1137 MT)
4. BWSSB, 7 CMC and 1 TMC project (Qty. 9,000 MT)
5. Kerala Water Distribution Packages (Qty. 30,410 MT)
6. BWSSB 7 CMC project – Distribution network (Qty. 18,589 MT)

7. Karnataka Land Army Corp., Koppal Water supply project (Qty. 4,500 MT)
8. Rajasthan Bikaner project (Qty. about 35,000 MT)
9. Karnataka Rural Water Supply (Qty. 2,500 MT)
10. Jharkhand drinking water and sanitation, Ranchi (Qty. 2,700 MT)
11. PHED, Patna Bihar (Qty. 2,300 MT)
12. GWSSB, Gujarat (Qty. 7,300 MT)
13. J&K Economic Reconstruction Agency, J&K (Qty. 4,500 MT)
14. PHED, Rajasthan (Qty. 4,500 MT)

Potential imports as a parameter for present material injury

114. The petitioners have relied on the decision in *Lubrizol* to suggest that the DGAD should take into account tenders that were opened during the POI even though they were for supply of pipes after the POI. This amounts to saying that imports which were imported 6 months after the POI, should be considered as if they were made in the POI. This preposition is faulty, against the tenets of the WTO Agreement on Anti-dumping and amounts to re-writing the law on this point through an incorrect reading of the *Lubrizol* judgement.

Causal Link

115. Any imposition of duty requires that there be a clear connection between imports and injury to the domestic industry and the facts should establish beyond doubt that imports alone, and not other factors resulted in injury to the domestic industry.

116. Data presented by the petitioners show that during the POI imports fell from 2004-05 levels and constituted a mere 2.5% of the market share. The same period also saw Jindal increase its market share to 30%, which consequently also lead to a fall in the petitioners market share from 92% to 67%.

117. Decreasing imports during POI sever the causal link between imports and any alleged injury suffered by the petitioners.

118. The Hon'ble DGAD should also recall the statement made by the petitioners in the GDR Offer Document dated September 30, 2005, i.e. in the middle of the POI that "Xinxing has yet to make a significant impact on the market". This statement itself goes to prove that the petition is baseless and filed with a malafide intention of thwarting all legitimate competition.

119. The DGAD should note that the petitioners have not experienced injury on any of the injury parameters. The GDR Offer Document and the Annual Reports for both companies establish that production volume, sales, net sales, realisation, capacity expansion, cash flow, wages, employment, inventories, growth and productivity have all shown positive trends and indicate further that the companies are slated for major expansion.

120. If a domestic industry is indeed materially injured due to imports, it would be constrained from raising capital and going in for expansion. However, as the record indicates, investment and expansion of the type that both Electrosteel and Lanco are

planning goes against a finding of injury. Not only did Electrosteel successfully raise 40 million through the GDR issue, it now planning to go in for another GDR issue/FCCB offering to fund its coal mine and sinter plant acquisition.

121. The Hon'ble DGAD should also consider "other factors" in the injury analysis:-

- a) XDIPL is the holder of 33 patents pertaining to specific aspects of DI pipe production technology which lend immense levels of productivity that cannot be matched by any of the producers in India. Respondent's technology enables it to efficiently use raw materials and even use different grades of raw materials to produce quality DI pipes. The domestic industry in India does not possess comparable technology and know-how and therefore are inherent deficiencies in its production processes.
- b) Even Electrosteel recognised the superior value of XDIPL's technology and has in the past procured the same from XDIPL. Specifically in 1999, XDIPL and Electrosteel entered into an agreement for the supply and installation of an entire DI fittings plant. Subsequently XDIPL has supplied technology and know-how from XDIPL and benefiting from the same are now trying to keep them from the market by filing a baseless petition with the DGAD.
- c) Petitioners faced high coke prices due to an anti-dumping duty in place on the product since 1998. The petitioners coking coal needs are met by imports mainly from China and Australia. As the DGAD is aware, there has been an anti-dumping duty on imports of Met Coke from China since August 1998, which was extended after a sunset review in January 2004. The duty is therefore in place at this point and will come up for review in January 2008. Thus the imposition of an AD duty has also substantially increased prices of Met Coke, which is the most important ingredient for manufacture of DI pipes and thus contributed to high raw material costs.
- d) Further basic customs duty on DI pipes has consistently been reducing since 2000 when it was 35%. Basic customs duty fell to 20% in 2004 and then to 15% in 2005. The current duty is at 12.5%.
- e) Falling customs duty also a reflective of the fact that the Indian Government recognises the need for importance of DI pipes to the water supply problem in India and has seen it necessary to facilitate the entry of imports by consistently lowering customs duty over the years.

122. None of the data and information submitted by the petitioners shows "material injury" or causal link between imports and alleged injury to the domestic industry and further establishes that the petitioners have not fulfilled their burden under the anti-dumping Agreement and Rules.

123. In the light of the above, the DGAD should reject any finding of injury or causal link. Further the DGAD should find against the petitioners for concealing important documents such as the GDR Offer Document that state the actual condition of ECL as claimed before its investors. Not disclosing the content of the Offer Document and alleging injury based on inadequate and baseless information amounts to misrepresentation and the Hon'ble Authority should take strict note of this act.

124. It has been submitted that Jindal Saw Ltd. has submitted some confidential data. The information is inadmissible for purpose of investigation, as the same has

been submitted in clear violation of Anti-dumping Rules as Rule 7 requires that all information should be accompanied by a non-confidential version of the same. In this case Jindal has refused to submit non-confidential version, therefore, data is liable to be wholly rejected. However, it has also been contended that XDIPL is forwarding an evidence which establishes that Jindal Saw has been on an expansion spree and suffered no injury during the entire POI. In this regard, it has quoted interview of Shri Inderesh Batra, Vice Chairman of the company to CNBC-TV18 and also quoted Annual Report of 2005-06 stating that 2005-06 has been one of the most profitable years of the company.

F.3. Submissions made by M/s Larsen & Toubro Ltd.

125. The argument advanced by domestic industry that duty free imports are made under Custom Notification No.84/1997 dated 11.11.97 for the projects financed by international organisations and hence should be excluded for injury analysis is a baseless and debarred of any merits or legal basis. It also means that they admit that supplies for pipes for the internationally funded projects are not injuring them.

126. It has been submitted that before entry of Jindal Saw in the field of DI pipes only Electrosteel and Lanco were only two producers and suppliers of DI pipes. In fact Electrosteel and Lanco have been the sole suppliers to all water projects in India until in 2004 when due to the high demand that Electrosteel and Lanco could not meet, contractors were forced to import pipes for supply to water projects. It only after witnessing buoyant growth in demand for DI pipes in India, that Jindal Saw made an entry to the production of DI pipes and commenced its production during the period of investigation itself. The period of investigation is that period in which not only Jindal Saw commenced its production operations but was able to sell substantial quantities of DI pipes in India and was able to secure sizeable portion of domestic market i.e., 30% (approx) market share within 9 months into production.

127. It has been further submitted that prior to entry of Jindal Saw Electrosteel has been a monopoly manufacturer and supplier of DI pipes in India. Its only some competition for some years was Lanco Kalahasti which entered into the market in 2001. The profit of Electrosteel drastically fell by 25% upon Lanco's entry into the DI pipe market, which clearly shows how Electrosteel was abusing its monopolistic status. In order to reinforce its monopoly position Electrosteel bought a major shareholding in Lanco and today controls upto 48% of the company. Lanco now functions as an associate company of Electrosteel. However the entry of Jindal has led to a drastic fall in the Domestic Industry share and renewed the fierce competition between the petitioners and Jindal Saw. This is a clear sign the competition between the two players, which has forced prices down and led to a shift in the domestic market share. The loss of such a huge market share of domestic industry is a result of competitive prices at which Jindal Saw Ltd has offered its goods in the Indian market thereby forcing the domestic industry to drop their profit margins from unreasonable high to reasonable level.

128. It has been alleged by the domestic industry that the respondent/importer M/s Larsen & Toubro Ltd. instead of placing the order on ECL has sourced its requirement for the product under consideration from China. It has also been submitted that a MOU concerning sourcing of DI pipes was entered into between

ECL and L&T. The said MOU was executed on 1.10.2005 wherein ECL had quoted a price for supply of DI pipes to L&T for 5 Kerala Water Supply project for which L&T had made bids. The tenders/products for which MOU were signed, were not for the period of investigation and are immaterial to the present case. The said tenders never opened up during the period of investigation, therefore; ordering for any quantity for the said contract/MOU during the period of investigation never arise. The said contracts were awarded to the L&T not before May 2006, much after period of investigation. Further the importer has not imported any quantity of the product under consideration during POI belies the claim of domestic industry as the L&T is not substituting its requirement for the product under consideration with Chinese goods over domestic industry goods.

129. Imports have declined drastically during the POI, the reason for such sharp decline in imports was the entry of new Indian producer in the Indian market i.e. Jindal Saw Ltd. The domestic demand which was facing supply pressure earlier due to shortage of supply of material from the domestic industry was left with no option but to import the same from China but with the entry of new producer in Indian market the imports reduced significantly. Not only imports were reduced drastically but also Jindal Saw which is relatively a new entrant in the Indian market has eaten up considerable market share of the domestic industry and imports.

130. All the parameters such as capacity, production, capacity utilisation, sales and stocks are showing positive trend during the injury period. The sales of domestic industry which has declined in the POI as compared to the preceding year cannot be ascribed to imports from China as the same also declined significantly. The domestic industry lost its sales in the POI due to the entry of a new producer in Indian market.

131. In view of the above the domestic industry has faced no injury on account of these parameters due to imports of DI Pipes from China PR.

132. It is submitted that not only sales of the domestic industry have increased substantially but the selling price of the domestic industry has also increased significantly, clearly refuting the theory of price pressure as being built by the petitioners of projecting injury to the domestic industry. It may be argued by the domestic industry that their selling price has declined from the preceding year; however, it may be observed that volume of imports has also declined significantly during the POI from preceding year. It is further worth noting that the prices of the domestic industry were at its peak when the imports from China were at its highest clearly proves that there is no correlation between imports and selling price of domestic industry.

133. The domestic industry recorded its highest profit in the year 2004-05 when the imports were at its peak clearly establishes the fact that the imports from China have not caused any losses to the domestic industry.

134. The decline in profitability of domestic industry is not because of imports from China as the imports have decreased substantially during the period of investigation. Hence, here is no nexus between imports and performance of the domestic industry.

135. It is beyond our comprehension that such a steep decline in imports can cause any injury to the domestic industry. Imports declined by 60% during the period of investigation from the preceding year. Landed value of the imports has been increasing over the years despite reduction in customs duty. In spite of reduction in landed value by 2% during the POI from preceding year, imports have also declined by 60%, rather than increasing.

136. M/s Jindal Saw Ltd. found the market lucrative for production of ductile iron pipes as the domestic industry was making huge profits before entry of M/s Jindal Saw Ltd. Had the Jindal Saw Ltd. found that market not lucrative because of presence of imports from China, the company would not have entered in the production of DI Pipes.

137. Thus, the decline in market share held by the domestic industry is not due to imports from China, the same is due to entry and competition posed by other producers in the Indian market. The domestic industry was enjoying monopoly in the Indian market which is challenged by other producer.

138. It is admitted by the domestic industry itself that domestic industry was able to fetch maximum price and recorded maximum sale in 2004-05, while the imports were also maximum during the same period. Hence the domestic industry performed much better in the presence of maximum imports, rather their selling price declined as the imports declined.

139. The profitability of the domestic industry declined during POI, which is due to entry of other producer in the Indian market.

140. It may be concluded that Jindal Saw is undercutting the prices of domestic industry and domestic industry is forced to benchmark its prices upon the prices of Jindal Saw, which resulted in decline in profitability of the domestic industry increased market of the Jindal Saw and reduced market share of the Domestic Industry.

141. DI has claimed it has lost a number of contracts to the exports from China PR against without any basis. It may be noted that the domestic industry despite increase in capacity, capacity utilisation, production and sale was unable to fulfil the rising demand of the domestic industry which resulted in imports from China. The imports from China came down significantly once the demand supply gap was filled with the entry of new producer i.e. Jindal Saw Ltd. in the Indian market who not only gobble the share of imports from China but also significantly captured the market share of the domestic industry.

F.4. Examination By The Authority

Volume of Dumped Imports

142. Transaction-wise data of imports from DGCI&S does not show imports of DI pipes in 2003-04 and 2004-05. However, some transactions of imports have been reported during the POI. The transaction-wise data from IBIS shows imports in 2003-04, 2004-05 and POI. The data provided by the importers also shows the imports

were made in preceding years. It appears that imports data provided by DGCIS has not captured all transactions of imports, therefore, the transaction-wise data provided by IBIS has been relied upon for analysis.

Market Share of Imports from Subject countries

	(% of Total Imports)				
	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr 05-Dec 05 POI	POI (Annualized)
Imports from subject country (MT)	0	2867	13412	4644	6192
Total Imports (MT)	0	2867	13412	4644	6192
% Share	0	100%	100%	100%	100%

143. The data shows that import of subject goods was made from subject country only, therefore, imports from subject country constitute 100% of the total imports. In 2002-03, the imports were nil. In 2003-04 imports were 2867 MT, rose to 13412 MT in 2004-05 and declined to 6192 MT (annualised) in POI. The trend shows that imports rose up to 2004-05, however, it declined during the POI. The Authority also notes that rise in imports in 2004-05 coincided with the significant undercutting by imports of selling price of the domestic industry.

144. The domestic industry has submitted that the imports have come under two distinct categories during the entire injury investigation period. Substantial quantities of imports have come duty-free under Customs Notification No. 84/1997-Cus. dated 11.11.1997. The break-up of the duty-free and duty-paid imports, as culled out from the IBIS transaction-wise data is as follows:

Year	Duty-paid	Duty-free	Total Qty in MT
2002-03	Nil	Nil	Nil
2003-04	584	2283	2867
2004-05	6952	6460	13412
POI	4644	Nil	4644
POI (Annualized)	6192	Nil	6192

145. The domestic industry further submits that the duty-free imports are made under the aforesaid Customs Notification which is granted specifically to projects financed by international organizations like ADB/World Bank. The demand against such projects is sporadic as can be seen from the above figures. This also explains as to why the industry saw a spurt in demand in 2004-2005 which came down again to its normal level when there were no projects financed by the international organizations like ADB/World Bank. In view of the irregular and transient nature of such imports, it has been submitted that the Authority may consider it appropriate to exclude the imports made without payment of customs duties for the purpose of injury analysis.

146. It has been contended by the other interested parties that "if the petitioners are demanding the imports for project funded by international organisations be excluded

from injury analysis, it also means that they admit that supply of pipes for internationally funded projects are not injuring them."

147. The Authority notes that substantial quantities of imports had taken place under the specific notification which exempts specified imports from payment of customs duties. It is also seen that substantial proportion of imports in the years 2003-2004 and 2004-2005 were against such projects whereas no such imports have taken place during 2002-2003, which is the base year of the injury investigation period nor are there any imports under the aforesaid notification during the period of investigation.

148. The Authority observes that by excluding the duty free imports, the trend of imports remains same from the base year to POI.

Share of Imports from China in comparison to Total Demand and Domestic Production

	(% of Total Demand)				
	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr 05-Dec 05 POI	POI (Annualized)
Total Demand (MT)	152193	168187	203355	168933	225244
Trend	100	111	134	111	148
% Share from China	0.00%	1.70%	6.60%	2.75%	2.75%

149. The data shows that demand of the subject goods rose by 48% during POI (annualised) as compared to base year. The share in demand of subject country was 1.70% in 2003-04, 6.60% in 2004-05 and 2.75% during POI. The trend shows that share of subject country rose from 2002-03 to 2004-05 when it was 6.60% of total demand, however, it declined to 2.75% in POI.

	(In proportion to domestic production)				
	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr 05-Dec 05 POI	POI (Annualized)
Total Production of all domestic producers (MT)	201976	218579	240549	222574	296765
Imports from China (MT)	0	2867	13412	4644	6192
Proportion of Domestic Production	0	1.31	5.6	2.1	2.1

150. The data shows that imports as ratio of total production was 0% in 2002-03, 1.21% in 2003-04, 5.6% in 2004-05 and 2.1% in POI. The trend shows, as compared to base year it rose from 0% to 5.6% in 2004-05, however, it declined to 2.1% during the POI.

Effect of Dumped Imports on Domestic Prices

151. The Authority notes that the selling price of the domestic industry has

increased over the injury investigation period. However, the cost of sales of the domestic industry at the same time has also increased. The increase in the cost of sales is much more than the increase in selling prices resulting into substantial loss of profit to the domestic industry. It can be seen from the following table that the selling price per MT has gone up by about 36 percent points during the POI as compared to the year 2002-2003, the costs per MT have increased by about 54 percent points during the same period. It is noted that while the costs and resulting prices of the domestic industry had been going up, the landed value of imports has been showing a downward trend. This clearly indicates that the domestic selling prices have been suppressed during the period of investigation.

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr 05-Dec 05 POI	POI (Annualized)
Landed Value from China Rs. / Unit	-	32841	30945	30171	30171
Domestic Selling Price Rs. / Unit	***	***	***	***	***
Trend	100	118	142	136	136
Cost/Unit	***	***	***	***	***
Trend	100	115	146	154	154

Price Undercutting

152. It was contended by the cooperating exporter that undercutting and dumping margin should be examined grade-wise, however, on examination of the prices in terms of weight of the exporter of various grades, it was found that there is variation of approx. plus-minus 1%, therefore, the Authority has examined the undercutting by the weighted average imports of all the grades.

153. In determining the weighted net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated.

154. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject country for the period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the value reported in the IBIS data of import prices from the subject country. The price undercutting from subject country was in the range of 2-10% during POI.

	Price undercutting
Domestic S.P	***
Landed Value	30171
Price Undercutting	***
Undercutting (%)	2-10%

155. The domestic industry has cited instances to demonstrate that due to the dumped imports and undercutting by Chinese exporters, they had to reduce their prices. These instances indicate that the prices offered by the domestic industry had to be reduced in view of the fact that their customers were being offered lower prices by the Chinese exporter. It can be seen from the MOUs signed between domestic industry and L&T and domestic industry and Subhash Projects that the prices had to be dropped to match the prices offered by the Chinese exporter. The fact that the contracts were finally not awarded to the domestic industry is clear evidence of substantial undercutting of prices.

Price Underselling

156. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed prices of imports from subject country have been compared with the weighted Non-injurious price (NIP) of the domestic industry determined for the POI. (M/s Jindal Saw Ltd. after providing some data did not cooperate further. The data available in latest cost audit report was for the financial year 1.10.2004 to 30.9.2005 and the same could not be adopted because POI for the investigation was for period 1.4.2005 to 31/12/2005. Therefore for determining NIP, data of M/s Electrosteel Castings Ltd. and M/s Lanco Industries Ltd. has been taken. For this purpose, factors including cost of raw material, consumption thereof, the cost of utilities, cost of labour, depreciation cost, selling and administrative expenses, interest and reasonable profit on capital employed have been taken into account.) The comparison shows that underselling during the POI is in the range of 10-25%

	Price underselling
Non-Injurious Price (NIP)	***
Landed Value/MT	30171
Price Underselling	***
% Underselling	10-25%

In view of the above, the Authority observes that the dumped imports from China have adversely affected the prices of the domestic industry.

Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

157. The Authority had further examined the effect of the dumped imports on the domestic industry by analyzing various injury parameters in terms of Annexure II of the Anti-dumping Rules.

Sales Volume of the Domestic industry

158. The Authority notes that M/s Jindal Saw Ltd. has made sales during the POI, therefore, the analysis has been done by including the volume of all the producers. The volume of sales by all producers has risen by 44% during POI as compared to base year. The demand of the subject goods has risen by 48% during the same period. The Authority also notes that the sales of the applicant domestic industry has risen by 9% in 2003-04, 25% in 2004-05 and 9% during POI as compared to base year. The Authority further notes that the overall volume of sales of all producers has risen by 44% in consonance with the rise in demand during the same period.

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr-Dec 05 (POI)	POI (Annualized)
Sales of all producers (MT)	152193	165320	189943	164289	219052
Trend	100	109	125	108	144

Sales of DI (MT)	***	***	***	***	***
Trend	100	109	125	109	109

Market Share of Domestic Industry

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr-Dec 05 POI	POI (Annualized)
Domestic Sales of Domestic industry (MT)	***	***	***	***	***
Domestic sales of other producers (MT)				***	***
Imports from subject country (MT)	0	2867	13412	4644	6192
Total Demand (MT)	152193	168187	203355	168933	225244
Share of DI	100%	98.30%	93.40%	73.50%	73.50%
Share of other producers	0%	0%	0%	23.75%	23.75%
Share of all producers	100%	98.30%	93.40%	97.25%	97.25%
Share of subject country	0%	1.70%	6.60%	2.75%	2.75%

159. The data shows that the share of all the producers was 100% in 2002-03, 98.30% in 2003-04, 93.40% in 2004-05, and 97.25% during POI. The share of the domestic industry from base year declined from 100% to 97.25% in POI. The share of subject country was 1.70% in 2003-04, rose to 6.60% in 2004-05 and declined to 2.75% in POI.

Production, Capacity & Capacity Utilization

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr 05-Dec 05 POI	POI (Annualized)
Capacity of DI (MT)	***	***	***	***	***
Capacity of other producers (MT)				***	***
Total capacity of all producers	260000	290000	290000	367500	490000
Trend (Indexed)	100	112	112	141	188
Production of DI (MT)	***	***	***	***	***
Production of other producers (MT)	***	***	***	***	***
Total Production (MT)	201976	218579	240549	222574	296765
Trend	100	108	119	110	147
Capacity Utilization of DI (%)	***	***	***	***	***
Capacity utilisation of other producers (%)	***	***	***	***	***
Total capacity utilisation (%)	78%	75%	83%	60.56	60.56

160. The Authority notes that the capacity of all producers rose to 490000 MT during POI i.e. by 88% as compared to 260000 MT during the base year. The production of all producers rose by 47% during POI as compared to base year. The capacity utilisation of all the producers however, declined from 78% in the base year to 61% during POI. The Authority also notes that the decline in capacity utilisation has occurred because of new capacity addition during POI by new entrant in the market. The Authority further notes that the production of all producers rose by 47% during POI as compared to base year. The demand of the subject goods during the same period rose by 48%.

Profitability

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr-Dec 05 POI	POI (Annualized)
Profit/Loss (Rs./Unit)	***	***	***	***	***
Trend	100	128	123	54	54
Profit/Loss (Rs. Lacs)	***	***	***	***	***
Trend	100	139	154	44	58

161. The data shows that the profit per MT from base of 100 (indexed) in 2002-03 rose to 128 in 2003-04, declined to 123 in 2004-05 and was 54 during POI. It indicates that the domestic industry has suffered significant loss of profits during the POI. The Authority notes that decline in profitability began in 2004-05, however, there was sharp decline in profitability in POI. In absolute terms, profits went up from 100 to 154 and then fell sharply to 44 during the same period.

Return on Investment (Capital Employed)

162. The Return on Capital Employed (ROCE) of the domestic industry has shown a drastic decline from 19.42% in 2002-2003 to a mere 4.79% during the POI. The data also shows that the decline began in 2004-05, however, drastic decline occurred in POI, indicating that the domestic industry has indeed suffered on account of dumped imports.

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr 05-Dec 05 POI
Capital Employed (in lakhs)	***	***	***	***
- Net Fixed Assets	***	***	***	***
- Net Working Capital	***	***	***	***
Profit Before Interest	***	***	***	***
ROCE (%)	***	***	***	***

Actual and potential negative effect on cash flows

163. An examination of the financial data of the domestic industry reveals that the dumped imports have had an adverse impact on the cash flow position of the domestic industry in as much as the profit plus depreciation has declined in the POI. The cash profit figures are given in the following statement:

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	Apr 05-Dec 05 POI	POI (Annualized)
Profit/Loss	***	***	***	***	***
Depreciation	***	***	***	***	***
Cash profit	***	***	***	***	***
Trend	100	140	155	56	75

Productivity

164. The productivity per employee for the domestic industry has increased over the injury investigation period. Thus, the productivity is not a cause of injury to the domestic industry as the productivity has increased from Indexed 100 per employee in 2002-03 to 120 during POI.

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	POI (Annualized)
Production(MT)	***	***	***	***
Employees	***	***	***	***
Production / Employee	***	***	***	***
Trend	100	103	118	120

Employment and Wages

165. The number of employees engaged by the domestic industry has not changed over the injury investigation. The wages per employee have increased over the injury investigation period which, according to the domestic industry, is in view of the contractual/legal obligations.

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	POI (Annualized)
No of Employees	***	***	***	***
Trend	100.00	105	101	99
Wages Total (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Wages /Employee (Rs.)	***	***	***	***
Trend	100	168	207	180

Inventories

166. The average inventories of the domestic industry in absolute terms as well as in terms of number of days have declined over the injury investigation period. The average stock has declined from 100 in 2002-2003 to 98 annualised during the POI. In terms of number of days' sales it declined from 100 to 90 over the same period.

	April 02 to March 03	April 03 to March 04	April 04 to March 05	POI
Average Stock (MT)	***	***	***	***
Trend	100	112	80	98
Average Stock (No. of Days)	***	***	***	***
Trend	100	103	71	90

Magnitude of Margin of Dumping

167. From the data supplied by the domestic industry and the cooperating exporter, it has been observed that there is a significant magnitude of dumping margin 46.47% as far as the imports from China are concerned.

Growth

168. The data shows that the demand of subject goods, production and sales of domestic industry shows rising trend, however, in terms of profits, profitability and return on capital employed, it shows declining trend.

Ability to Raise Capital Investments

169. The domestic industry claims that in view of the falling profitability, market share and ROCE, it would not be feasible for them to raise any fresh capital in the business. During the proceedings, the exporter also referred to the GDR Offer Document of ECL which, according to them, would have established beyond doubt that ECL was not facing injury from China in general and Xinxing in particular during the POI. The domestic industry in its rejoinder submissions claimed that the present investigations are restricted to product under consideration. They have further submitted that the injury determination is for the domestic industry as a whole under Annexure II and not in respect of one of the constituents of the domestic industry. They claimed that petition that was filed was for the domestic industry as a whole and GDR averments were relating to ECL only that too for the company as a whole and not for product under consideration. Further, it was submitted that the GDR document referred to does not pertain to the period of investigation. On examination of the submissions made by the concerned parties, the Authority is of the view that it is under an obligation to examine injury under Annexure-II for the domestic industry as a whole and not for its individual constituents. At the same time, the domestic industry has rightly pointed out that the statements made in GDR offer document were in respect of ECL's overall operations and not for the product under consideration alone and not for the period of investigation. Xinxing's reliance on the extract from the GDR offer document is also misplaced as the GDR offer document refers to information prior to 31st March 2005 and some unaudited information up to June 2005 not for the full period of investigation. In view thereof, it is clear that the statement contained therein about Xinxing cannot be relied for analysis of data for the period of investigation.

170. The statement that the experience of ECL cannot be easily replicated by competitors is not a statement made in the context of injury but in the context of producers setting up operations in India. Further, there is no indication that the company is of the view that they can face even unfair competition. The evidence on record clearly goes to show that the goods were dumped in India indicating thereby that the exporter was resorting to unfair competition. The object of any investigation is to restore fair trade by imposition of anti-dumping duties to the extent necessary to remove injury to the domestic industry. In view of the above, the Authority finds no merit in the arguments made by the exporter in this respect.

Evidence of Lost Contracts

171. The domestic industry has submitted information indicating several instances of the competition between Chinese supplier and domestic industry indicating undercutting during the period of investigation as well as in the Pre-POI period. It is seen from these documents that during the POI, the domestic industry lost a huge contract of 26238 MT for supplies to be made to Kerala Water Authority (KWA) through L&T and Subhash Projects & Marketing Ltd. The Authority also corresponded with Kerala Water Authority as well as other parties involved in the contract. The Kerala Water Authority has confirmed that the Chinese exporter had been added as an approved supplier for the said projects. It has been stated by the exporter that the Chinese supplier replaced the Indian supplier because of the delivery schedule and not because of the prices, however, the correspondence between domestic industry and the contractor very clearly indicate that the negotiations were concerning the prices and not for the delivery schedule. Thus, it is clear that the above orders to the tune of 26238MT of supplies went to the account of the Chinese exporter. It is also apparent that this contract was lost only on account of the lower prices offered by the Chinese exporter.

172. The exporter has mentioned number of contracts which the exporter claim to have been awarded to the domestic industry. It has also been stated that the domestic industry withheld the information from the Authority regarding the contracts. The domestic industry stated that these contracts relate to POI and post-POI period and many of these instances have already been informed to the Authority in the submissions made after the Public Hearing. The Authority notes that the instances of the contract cited by domestic industry were in the context of competition and undercutting by the Chinese supplier. The Authority holds that it is not necessary for the domestic industry to inform all the contracts awarded to the domestic industry as the investigation concerns contracts lost by the domestic industry because of undercutting and dumping by the exporter.

173. As stated earlier, in the face of substantial loss of contracts, the domestic industry was compelled to reduce its prices for other contracts as well to ensure that they do not lose further contracts even though this meant a substantial loss of profitability to the industry. This is evidently reflected in the price trend of the domestic industry over the injury period. Thus, it is evident that the domestic industry lost substantial contracts to the Chinese exporters and also suffered heavily on account of price reduction. The loss of contracts is also reflective of volume injury to the domestic industry.

F.5. Conclusion on Injury

174. The demand of subject goods from base year to POI has increased by 48%. The imports of subject goods from China PR has increased from 0 MT to 6192 MT during POI, the domestic sales of all producers has increased by 44% and production of all producers have increased by 47% during the same period.

175. The cost of sales of the domestic industry has increased by 15% in 2003-04, 46% in 2004-05 and 54% in POI as compared to base year. The trend on selling price shows that selling price increased by 18% in 2003-04, 42% in 2004-05 and 36% in POI during the same period. As compared to base year, profit per unit increased

by 28% in 2003-04, 23% in 2004-05 and declined to 54% of base year in POI. The data indicates that the cost of sales kept on increasing from base year to POI whereas selling price declined marginally in 2004-05, however, it declined sharply in POI. The return on capital employed shows similar trend. It increased in 2003-04, declined marginally in 2004-05, however, there was sharp decline in POI. The evidence of loss of contract indicates that the domestic industry was in position to sell the product only by reducing the price because of the undercutting by the exporter. The loss of volume because of lost contract would actually be translated after POI.

176. The above analysis indicate that though there was increase in imports from base year to POI, however, as compared to 2004-05, the imports declined in absolute term from 13412 MT to 6192 MT (annualised) during POI. The sales volume of applicant domestic industry increased up to 2004-05, however, in POI it declined. The sales of all domestic producers shows that it increased during POI as compared to base year. The data indicates that imports declined in POI as compared to immediate preceding year, however, sales of all domestic producers increased inconsonance with the growth in demand of the subject goods.

177. The data indicates that cost of sales kept on increasing from base year to POI, the selling price increased up to 2004-05 before declining in POI. The data on per unit profit/loss indicate that the decline began in 2004-05, however, there was sharp decline in POI as compared to immediate preceding as well as base year. The return on capital employed shows the same trend. The analysis indicates that the domestic industry kept the pace concerning production and sales with the growth in demand, however, the domestic industry was under severe pressure concerning profitability and return on capital employed during POI indicating injury to the domestic industry.

178. In view of the above, the authority concludes that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation on account of dumped imports from China and that there is also an imminent threat of injury on account of order of the large quantities accrued to exporter during the period of investigation.

F.6. Other Known factors

179. The Authority has also examined the issue of causal link and other non-attribution factors as laid down in the Rules to segregate injury if any caused by other factors. In this regard the following indicative factors as laid down in the Rules have been examined.

i) Volume and prices of imports from other sources

180. The authority notes that there was no imports from other country during the entire injury period, therefore, this factor cannot be considered as causing injury to the domestic industry.

ii) Competition by other domestic producers

181. M/s Jindal Saw Ltd. entered the market during POI. It has been contended by the exporter and importers that the injury to the domestic industry has occurred because of competition created by M/s Jindal Saw Ltd. It has further been contended

that the volume loss of the applicant domestic industry has been cornered by the new entrant in the market. It has also been stated that M/s Jindal Saw Ltd. is exempted from payment of excise duty, therefore, has price advantage vis-à-vis existing producers. The Authority notes that with the entry of new producer in the market, the competition was bound to arise. However, where there was robust growth in demand of the subject goods, the sales in absolute term were not affected though the new entrant captured share in the market. The Authority also notes that excise exemption given to M/s Jindal Saw Ltd. for the purpose of setting up unit in a specified area. The excise exemption had been given by the Government to offset the disadvantage of setting up unit in that area.

182. The Authority notes that in 2004-05, in absence of M/s Jindal Saw Ltd. the domestic industry could not increase price in proportion to the rising cost of production. The Authority also notes that the landed value of imports was undercutting the selling price in 2004-05 indicating that because of undercutting by the dumped imports from China PR the domestic industry was prevented from raising their prices in proportion to the cost of production and consequently impacting their profitability. As undercutting from China PR continued during POI, therefore, the Authority holds that in spite of entry of M/s Jindal Saw Ltd. during the POI, the injury to the domestic industry is attributable to the dumped imports from the subject country.

iii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

183. The subject goods have shown robust growth during the injury period. The total demand of subject goods has shown growth of 48% during Period of Investigation as compared to the base year. There is no change in consumption pattern of the product in the domestic market which could be attributed to the injury to the domestic industry.

iv) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

184. The Authority notes that there is no restricted practice prevalent in the industry which could be attributed to the injury to the domestic industry.

v) Development of technology

185. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Development of any other technology, therefore, cannot be attributed to the injury to the domestic industry.

vi) Export performance

186. For the purpose of production, capacity utilisation, the export production has been taken into account, however, for selling price, profitability, profit and return on capital employed, data relating to domestic sales is taken into account. Therefore, the effect of export performance will not impact the analysis relating to sales of the domestic industry in the domestic market, therefore, this factor cannot be considered causing injury to the domestic industry.

vii) Productivity of the Domestic Industry

187. Productivity of the domestic industry in terms of production per employee has increased during the injury period, therefore, it cannot be considered as factor causing injury to the domestic industry.

188. No other factor which could have possibly caused injury to the domestic industry has been brought to the knowledge of Authority.

F.7. Causal Link

189. The demand of subject goods grew by 48%, the imports though increased in absolute term from base year to POI, however, actually declined in POI as compared to immediate preceding year. The Authority notes that sharp increase in imports in 2004-05 coincided with significant undercutting of the selling price by the imports from subject country. The market share of all domestic producers declined from 100 in the base year to 97.25% during POI. The share of subject country increased from 0% to 2.75% during the same period, however, the share of subject country declined to 2.75% in POI from 6.60% in immediate preceding year. It has been argued by the cooperating exporter that the domestic industry has not lost in volume term as the share from subject country has actually declined. It has also been argued that loss of volume by applicant domestic industry has actually been garnered by the new producer who entered the market during POI. The domestic industry, from the data shows, has not lost in volume term, however, the D I has submitted evidence that they lost the contract during the POI because of undercutting by the exporter. The Authority notes that the loss of volume because of contract will actually be translated in the period in which the actually deliver of goods will take place, however, because of undercutting by the dumped imports, the domestic industry be under constant fear of losing volume unless it matches prices with the dumped imports.

190. The domestic industry has shown sharp decline in selling price and profitability during the POI as compared to immediate preceding year whereas the cost of sales during the same period has increased. The landed value of imports goods shows declining trend and decline during the same period. With the rising cost of sales, there was no reason for the domestic industry to reduce the selling price except that it had to benchmark its prices with that of imports. It has been argued by the exporter that the new entrant M/s Jindal Saw Ltd. was having benefit of exemption of excise and, therefore, they reduced the prices giving competition to the applicant domestic industry with the result that the volume loss of the applicant was garnered by the new entrant. It has been noted that in the year 2004-05, the Domestic Industry did not increase the selling price in consonance with the rise in cost of production on account of rise in the cost of raw materials. It indicated that the domestic industry was benchmarking its prices with the imports. (In preceding years M/s Jindal Saw Ltd. was not in the market and could not have given competition to the existing producers) The Authority holds that M/s Jindal Saw Ltd. has created competition in the market, however, the domestic industry was also benchmarking its prices with the imports as indicated from declining landed value of imports. The Authority also holds that the loss of contract by the domestic industry to the exporter during the POI very clearly indicate that the domestic industry was under pressure from the exporter to reduce

the prices for keeping their share in the market. It has been argued by the exporter that the loss of contract will actually affect the domestic industry beyond the POI period, the Authority notes that in this type of product where tender processes are involved, there is a gap of time between floating of tenders and actual supply of goods, however, the undercutting by the exporter was visible when the tender was opened and the contractors were putting pressure on the producer to reduce the prices. The goods are actually being supplied by the exporter as indicated from the documents available very clearly shows that though the loss of volume will actually be translated in period beyond the POI, however, the price effect become visible even during the POI.

191. In view of the above the Authority holds that though in response to the dumped imports the domestic industry did not lose in volume term immediately, however, it had to reduce the prices to retain the share in the market and suffered in the profitability and return on capital employed. The loss of contract by the domestic industry and replacement of the domestic producer with that of exporter for which supplies are to be made after the POI period also establishes the causal link between the potential imports and the financial performance of the domestic industry.

G. Indian Industry's interest & Other Issues

192. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

193. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the subject goods or the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. With a view to minimize the impact on the downstream industry, the Authority has considered it appropriate to recommend anti dumping duty based on the lower of the dumping and injury margins. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

H. Conclusions

194. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- a) The subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;
- b) The domestic industry has suffered material injury;
- c) The injury has been caused by the dumped imports from subject country.

I. Recommendations

195. It is considered necessary to impose definitive anti-dumping duty on the

imports of subject goods. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti dumping duty on the imports of DI Pipes

196. It is decided to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. The landed price of imports was also compared with the non-injurious price of the domestic industry, determined for the period of investigation. In this case injury margin is less than dumping margin, accordingly, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 8 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	73030030 and 73030090	DI Pipes	China PR	China PR	M/s Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd.	Any	127.40	MT	US\$
2.	Do	do	China PR	China PR	Any other than above	Any	139.79	MT	US\$
3.	do	do	China PR	Any other than subject country	Any	Any	139.79	MT	US\$
4.	do	do	Any other than subject country	China PR	Any	Any	139.79	MT	US\$

197. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority